राष्ट्रीय संस्करण

विराट सेना की इंग्लैंड में आज से परीक्षा >>7

वर्ष 5 अंक 55

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, बुधवार, 4 अगस्त, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

जागरण विशेष

उमस खत्म कर आक्सीजन दे सकेंगी घर की दीवारें

वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने ऐसी जेली बनाई है जो भीषण गर्मी और उमस से निजात दिलाकर कमरे में आक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ा देगी। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राष्ट्रीय फलक ▶ पृष्ठ 5

त्रिपुरा में उग्रवादियों का हमला, दो बीएसएफ जवान शहीद

अगरतला : त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एनएलएफटी उग्रवादियों ने घात लगाकर किए गए एक हमले में एक सब इंस्पेक्टर समेत बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए हैं। उग्रवादियों ने मंगलवार को यह जानलेवा हमला तब किया जब बीएसएफ के जवान इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर भारु सिंह और कांस्टेबल राज कुमार का निधन हो गया। घटनास्थल पर मिले खून के धब्बों से साफ है कि उग्रवादियों को भी गोली लगी है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 7

वोडा आइडिया में पूंजी डूबने की आशंका से बैंकों में हड़कंप

नई दिल्ली : टेलीकाम कंपनी वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति का सरकार और इसके कर्जदाता बैंकों को पहले से अंदाजा है। लेकिन जिस तरह से इस कंपनी में 27 फीसद हिस्सेदारी रखने वाले आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला ने सरकार को पत्र लिखकर कंपनी को बचाने और अपनी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव किया है, उससे बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया है। इस पत्र के बाद कर्जदाता बैंकों पीएनबी, एसबीआइ, यस बैंक, आइडीएफसी, आइसीआइसीआइ बैंक व इंडसइंड में विमर्श शुरू हो गया है।

आज का मैच

पहला टेस्ट

भारत vs इंग्लैंड — स्थान नाटिंघम

दोपहर 3:30 बजे से

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

फिर बेटियों से उम्मीदें

- महिला हाकी टीम का सेमीफाइनल आज
- फाइनल में जगह बनाना चाहेंगी लवलीना

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : टोक्यो ओलिंपिक में बुधवार को एक बार फिर निगाहें देश की बेटियों पर होंगी। जहां महिला हाकी टीम ओलिंपिक इतिहास का अपना पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेलने उतरेगी तो वहीं पहले ही पदक पक्का कर चुकीं मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई अपने पंचों के दम पर फाइनल में पहुंचना चाहेंगी।

असंभव कुछ भी नहीं : रानी रामपाल की अगुआई वाली भारतीय महिला हाकी टीम के लिए सिडनी और लंदन ओलिंपिक की रजत पदक विजेता अर्जेंटीना से पार पाना आसान नहीं होगा। हालांकि उसने तीन बार की ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता आस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में हराकर बता दिया है कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर टीम सेमीफाइनल जीत जाती है तो उसका पदक पक्का हो जाएगा।

इतिहास रचने का मौका : असम की 23 साल की महिला मुक्केबाज लवलीना, तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली से भिड़ेंगी। दोनों पहली बार एक-दूसरे के आमने-सामने होंगी।

भारत के अन्य परिणाम

- युवा पहलवान सोनम मलिक को महिलाओं के 62 किग्रा भार वर्ग के पहले दौर के मुकाबले में ही हार का सामना करना पड़ा
- महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में अनु रानी अपने ग्रुप में 14वें और कुल 30 खिलाड़ियों में 29वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकीं
- एशियाई रिकार्ड धारी गोला फेंक एथलीट तजिंदर पाल सिंह तूर क्वालीफिकेशन दौर में अपने ग्रुप में 13वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गए

पुरुष हाकी में स्वर्ण का सपना टूटा

टोक्यो : मनप्रीत सिंह की अगुआई वाली पुरुष हाकी टीम को मंगलवार को सेमीफाइनल में बेल्जियम के हाथों 2-5 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारतीय टीम का 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने का सपना टूट गया, लेकिन उसके पास अभी भी कांस्य जीतने का मौका है। कांस्य पदक के मुकाबले में गुरुवार को उसका सामना 2004 एथेंस की ओलिंपिक स्वर्ण पदक विजेता जर्मनी से होगा।

TOKYO 2020

भारत पहुंचने के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के दौरान पीवी सिंधु ● एएनआइ

स्वतंत्रता दिवस पर विशेष अतिथि होगा भारतीय ओलिंपिक दल

नई दिल्ली, जाब्यू : 15 अगस्त को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश को लगातार आठवीं बार संबोधित करेंगे तो इस दौरान टोक्यो ओलिंपिक में भाग लेने वाला भारतीय दल भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेगा। बाद में प्रधानमंत्री अपने आवास पर सभी खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर उनका अनुभव भी जानेंगे।

सिंधु का स्वागत

नई दिल्ली, जासं : टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतकर लौटी भारतीय शटलर पीवी सिंधु का मंगलवार को देश लौटने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंधु को सम्मानित किया।

सीबीएसई 10वीं में 99 फीसद से ज्यादा छात्र पास

रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मंगलवार को 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए। छात्रों ने बिना परीक्षाओं के केवल आंतरिक परीक्षाओं के आधार पर ही बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा के लिए इस साल 21 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। 20 लाख से अधिक उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत 99.04 रहा। बीते साल उत्तीर्ण प्रतिशत 91.46 था। बोर्ड ने 16,639 छात्रों का परिणाम फिलहाल जारी नहीं किया है। सीबीएसई का कहना है कि इन छात्रों के अंक स्कूलों द्वारा समय से नहीं भेजने के चलते ऐसा किया गया है। एक हफ्ते के अंदर इनका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बीते साल की तरह इस साल भी त्रिवेंद्रम जोन टाप पर रहा। त्रिवेंद्रम जोन का पास फीसद 99.99 रहा। दूसरे स्थान पर बेंगलुरु व तीसरे पर चेन्नई रहा।

लड़कियों के परिणाम में छह फीसद का सुधार : 10वीं के परिणाम में लड़कियों व लड़कों दोनों ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। बीते साल के मुकाबले लड़कियों के परिणाम में छह और लड़कों के परिणाम में आठ फीसद तक का सुधार हुआ है। इस साल कुल 99.24 फीसद लड़कियां व 98.89 फीसद लड़के पास हुए हैं। ट्रांसजेंडरों के परिणाम में भी छह फीसद का सुधार हुआ है। इस साल 100 फीसद ट्रांसजेंडर पास हुए हैं। बीते साल 94.74 फीसद पास हुए थे।

पोर्टल से डाउनलोड करें प्रमाणपत्र पेज>>5

ओबीसी की पहचान का राज्यों को फिर दिया जाएगा अधिकार

अहम फैसला ▶ केंद्र सरकार मानसून सत्र में ही लाएगी विधेयक

कैबिनेट से बिल को आज मिल सकती है मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण पर राज्यों को मिले अधिकार बहाल होंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए अब संसद का रास्ता चुना है। इसे लेकर बुधवार को कैबिनेट में विधेयक को लाने की तैयारी है। वहां से मंजूरी के बाद इसे संसद के चल रहे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक को दोनों सदनों से अगले एक-दो दिनों में पारित कराने की योजना है।

केंद्र सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद उठाया है, जिसमें ओबीसी की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार को अवैध बताया था। कोर्ट का कहना था कि 102वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर पिछड़ों की पहचान करने और अलग से सूची बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ केंद्र ही ऐसी सूची बना सकता है। वही सूची मान्य होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया था, क्योंकि मौजूदा समय में ओबीसी की केंद्र और राज्यों की सूची अलग-अलग है। राज्यों की सूची में कई ऐसी जातियों को रखा गया है, जो केंद्रीय सूची में नहीं हैं। केंद्र इस मामले को लेकर इसलिए भी सतर्क है, क्योंकि राज्य की सूची के आधार पर ही कई ऐसी पिछड़ी जातियां हैं, जो राज्य की सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण का लाभ पा रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होने से इन जातियों को नुकसान होने का खतरा है।

- सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की ओर से ओबीसी की पहचान करने को बताया था गलत
- मौजूदा समय में अलग-अलग है ओबीसी की केंद्र और राज्यों की सूची
- राज्य की सूची के आधार पर ही कई पिछड़ी जातियों को मिलता है आरक्षण

जोखिम नहीं लेना चाहती केंद्र सरकार : आरक्षण जैसे संवेदनशील मामले में केंद्र सरकार किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही साफ कर दिया था कि वह इससे सहमत नहीं है। वह राज्यों को उसके अधिकार वापस देगी।

नए मंत्री ने भी दिखाई सजगता : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद नए मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी अधिकारियों के साथ सबसे पहले इस मुद्दे पर मंत्रणा की। साथ ही कानूनी विशेषज्ञों और पीएमओ से मशविरा करने के बाद विधेयक को अंतिम रूप दिया।

केंद्र की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी खारिज

- केंद्र ने मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी।
- इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में मौजूदा समय में करीब 26 सौ जातियां शामिल हैं।

हाल के दिनों में ओबीसी को लेकर दूसरा अहम फैसला : ओबीसी को लेकर केंद्र ने हाल के दिनों में यह दूसरा अहम फैसला लिया है। इससे पहले सरकार ने 29 जुलाई को मेडिकल की सभी स्नातक व पोस्ट ग्रेजुएट सीटों पर नामांकन के लिए केंद्रीय कोटे में ओबीसी की खातिर 27 फीसद कोटा लागू करने का फैसला किया था। फैसले के मुताबिक, यह आरक्षण इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो जाएगा।

'संसद ठप करना संविधान-लोकतंत्र का अपमान'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद नहीं चलने देने पर मंगलवार को विपक्ष पर जमकर बरसे। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने संसद ठप करने को संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया। उन्होंने तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन के संसद में पारित विधेयकों की तुलना 'पापड़ी चाट' से किये जाने को भी अपमानजनक बताया।

संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी के अनुसार संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। पीएम ने भाजपा सांसदों से कहा कि संसद चलाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन विपक्ष न सिर्फ अपनी संसदीय जिम्मेदारी से भाग रहा है, बल्कि संसद, संविधान और लोकतंत्र का अपमान करने की हद तक चला गया है। उन्होंने कहा कि संसद के भीतर विपक्षी सांसदों का कागज फाड़कर उड़ाना उस जनता का भी अपमान है, जिसने उन्हें चुनकर संसद में भेजा है।

उन्होंने कहा कि कागज फाड़कर फेंकना और उसके लिए माफी तक नहीं मांगना विपक्ष के अहंकार को दर्शाता है। ध्यान देने की बात है कि पिछले हफ्ते संसदीय दल की बैठक में भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया था।

प्रह्लाद जोशी के अनुसार प्रधानमंत्री ने डेरेक ओ ब्रायन के 'पापड़ी चाट' के बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे अपमानजनक बताया। दरअसल डेरेक ओ ब्रायन ने संसद में बिना बहस के चंद मिनट में ही विधेयकों को पास किए जाने की तुलना पापड़ी चाट से की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर विधेयक पर बहस के तैयार है और विपक्ष इससे भाग रहा है। विपक्ष के नकारात्मक रवैये के कारण विधेयक बिना बहस के पास हो रहे हैं। इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। उनका कहना था कि संसद और उससे पारित विधेयक की एक गरिमा है। डेरेक ओ ब्रायन का बयान इस गरिमा के खिलाफ है।

नई दिल्ली में मंगलवार को भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रेट्र

बरसे पीएम

- डेरेक ओ ब्रायन के 'पापड़ी चाट' वाले बयान पर जताई आपत्ति
- कागज फाड़कर फेंकने और माफी न मांगने को बताया विपक्ष का अहंकार

रंग लाई राहुल की विपक्षी एकता की पहल

नई दिल्ली : पेगासस जासूसी कांड, महंगाई, किसानों के मुद्दे को लेकर संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी की नाश्ते पर बुलाई गई बैठक कामयाब रही। अब तक कांग्रेस की रहनुमाई में आने से हिचक रही तृणमूल कांग्रेस भी इसमें शरीक हुई, जिससे विपक्षी गोलबंदी को नई ऊर्जा मिली। पंद्रह दलों के करीब 100 से ज्यादा सांसदों ने नाश्ते के बाद राहुल की अगुआई में मंगलवार को संसद तक साइकिल मार्च निकाला। (विस्तृत खबर पेज 3 पर)

नई दिल्ली में मंगलवार को राहुल गांधी पेट्रोल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ साइकिल से संसद भवन गए। जागरण

पेंटागन के बाहर हमले में पुलिस अफसर की हत्या

वाशिंगटन, एपी : अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पेंटागन की इमारत के बाहर मंगलवार सुबह एक पुलिस अधिकारी को हमलावर ने चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मार गिराया गया। लोगों ने मौके पर गोलियां चलने की आवाज भी सुनी। इस घटना के बाद इमारत को लाकडाउन कर दिया गया।

अर्लिंग्टन काउंटी फायर डिपार्टमेंट के अनुसार इस घटना के बाद कई लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका कि उन्हें गोली लगी है या अन्य कारणों से चोट लगी है।

पेंटागन की सुरक्षा करने वाली एजेंसी पेंटागन प्रोटेक्शन फोर्स ने ट्वीट किया कि यह घटना पेंटागन ट्रांजिट सेंटर के मेट्रो बस प्लेटफार्म पर हुई। यह जगह पेंटागन की इमारत से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। यह जगह वर्जीनिया की अर्लिंगटन काउंटी में है। यह क्षेत्र वाशिंगटन, डीसी में पोटोमैक नदी के पार पड़ता है।

वन भूमि से एक-एक अवैध निर्माण हटेगा : सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- फरीदाबाद के खोरी गांव में वन भूमि पर अवैध कब्जे का मामला
- सूरजकुंड रोड स्थित 15 मैरिज हाउस राहत के लिए कोर्ट पहुंचे
- कोर्ट ने कहा, राधास्वामी कांप्लेक्स भी यदि वन भूमि पर है तो हटेगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर साफ कर दिया है कि वन भूमि से सारा अवैध निर्माण हटेगा, फिर वह चाहे जिसका हो या जैसा हो। कोर्ट के सख्त रुख से सिर्फ खोरी गांव में वन भूमि पर अवैध कब्जा कर घर बनाने वाले ही निशाने पर नहीं आए हैं बल्कि वन क्षेत्र में आने वाले मैरिज हाउस और फार्म हाउसों पर भी ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। राहत के लिए सूरजकुंड रोड पर स्थित 15 मैरिज फार्म के मालिक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने राधा स्वामी सत्संग कांप्लेक्स का मुद्दा उठाए जाने पर कहा, अगर वह वन भूमि पर होगा तो वह भी हटेगा।

हरियाणा के फरीदाबाद जिले के खोरी गांव में वन भूमि पर अवैध निर्माण के मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान फरीदाबाद नगर निगम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरुण भारद्वाज ने जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि पुनर्वास नीति का ड्राफ्ट तैयार करके मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। इस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 25 अगस्त तक फैसला कर ले।

इसके अलावा कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कोलिन गोन्साल्विस और संजय पारिख की ओर से वन भूमि से हटाए गए कब्जेदारों के बेघर होने और उन्हें आश्रय दिए जाने की दलीलों पर नगर निगम से कहा कि वह राधा स्वामी कांप्लेक्स के साथ कमिश्नर का एक एडीशनल आफिस बनाए ताकि बेघर हुए लोग आश्रय और भोजन आदि के लिए वहां आवेदन दे सकें। बेघर हुए लोगों के संबंध में कोर्ट ने फिर साफ किया कि जो लोग पुनर्वास नीति के तहत हकदार होंगे उनका पुनर्वास होगा, जैसा कि नगर निगम ने भरोसा दिलाया है। लेकिन जो लोग नीति के तहत पुनर्वास के हकदार नहीं हैं, उनका पुनर्वास क्यों होना चाहिए।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई 25 अगस्त को तय करते हुए नगर निगम को आदेश दिया कि वह कोर्ट के पूर्व आदेश के मुताबिक 23 अगस्त तक वन भूमि से अवैध निर्माण हटाने का काम पूरा कर ले और अगली सुनवाई की तिथि से पूर्व कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। रिपोर्ट में निगम को बेघर हुए लोगों के ज्ञापनों की भी संक्षिप्त में बताना होगा। निगम आयुक्त लोगों की शिकायतों और ज्ञापनों पर विचार करें और उन्हें पूर्व आदेश के मुताबिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

उधर, सूरजकुंड रोड स्थित 15 मैरिज फार्मों के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर निगम की ओर से अपना निर्माण अवैध बताकर ढहाने के लिए भेजे गए नोटिस को रद करने और उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने की मांग की है। अर्जी में यह भी कहा गया कि हरियाणा के वन विभाग को निर्देश दिया जाए कि वह मौके पर वन भूमि चिह्नित करे। साथ ही हरियाणा सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह नियमानुसार शुल्क लेकर उनके मैरिज फार्म और फार्म हाउस नियमित करे।

अगर आपका मामला उसमें नहीं तो फिर क्यों आए हैं : कोर्ट पेज>>2

गोगरा से पीछे हटेंगे भारत और चीन के सैनिक

नई दिल्ली, एएनआइ : पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध दूर करने की दिशा में काफी दिनों बाद सकारात्मक संकेत मिले हैं। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को गोगरा इलाके से पीछे हटाने पर सहमति जताई है। भारत और चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत में दोनों पक्ष पट्रोलिंग पाइंट 17-ए से पीछे हटने के लिए तैयार हुए हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में इस पट्रोलिंग पाइंट को लेकर दोनों देशों में गतिरोध बना हुआ था।

सूत्रों ने बताया कि 12वें दौर की बातचीत में दोनों पक्षों में पट्रोलिंग पाइंट 17-ए से पीछे हटने को लेकर सहमति हुआ है। पट्रोलिंग पाइंट 17-ए को गोगरा के नाम से जाना जाता है।

इससे पहले इस साल फरवरी में दोनों पक्ष पैंगोंग झील से अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हुए थे। सूत्रों ने कहा कि जमीनी कार्रवाई की पुष्टि की जाएगी। उम्मीद है कि जल्द ही इस सिलसिले में कदम उठाया जाएगा।

दोनों पक्ष पीपी-15 (हाट स्प्रिंग्स) और डेपसांग सहित टकराव के अन्य बिंदुओं को हल करने के लिए अपनी बातचीत जारी रखेंगे।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चुशुल-मोल्डो में 31 जुलाई को दोनों देशों के बीच वार्ता हुई थी, जिसके बाद उन्होंने दो अगस्त को एक संयुक्त बयान जारी किया था।

बयान के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच सीमा के पश्चिमी इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी पर विचारों का स्पष्ट और गहन आदान-प्रदान हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर ध्यान दिया कि बैठक का यह दौर रचनात्मक रहा, जिसने आपसी समझ को और बढ़ाया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष मौजूदा समझौतों और प्रोटोकाल के अनुसार शेष मुद्दों को शीघ्रता से हल करने और बातचीत की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए। बयान के मुताबिक, दोनों देश इस बात के लिए राजी हैं कि पश्चिमी सेक्टर में एलएसी पर स्थिरता बनाए रखने के लिए वे संयुक्त प्रयास जारी रखेंगे और शांति बनाए रखने के लिए काम करेंगे।

- 12वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत में बनी सहमति
- टकराव के अन्य बिंदुओं को हल करने के लिए जारी रखेंगे बातचीत

मिले सकारात्मक संकेत। फाइल फोटो

खतरनाक संकेत

केंद्र ने कहा, दूसरी लहर अभी गई नहीं, आठ राज्यों में आर नाट ज्यादा, एक संक्रमित व्यक्ति कितनों में फैलाता है बीमारी, यह मापने का पैमाना है आर नाट, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आर नाट सबसे अधिक 1.4, इसमें बढ़ोतरी भी जारी

आर नाट ने बढ़ाई कोरोना की तीसरी लहर की चिंता

नीलू रंजन, नई दिल्ली

देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आर नाट ने तीसरी लहर को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आर नाट को आर फैक्टर भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति आगे कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर नाट बढ़ रहा है, वहीं सात में स्थिर बना हुआ है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के अनुसार देश में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आर नाट सबसे अधिक 1.4 पर पहुंच गया है और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि इन दोनों राज्यों में कोरोना संक्रमित 100 लोग दूसरे 140 लोगों में संक्रमण फैला रहे हैं। आर फैक्टर लक्षद्वीप में 1.3, तमिलनाडु, मिजोरम व कर्नाटक प्रत्येक में 1.2 और केरल व पुडुचेरी में 1.1 है। एक से अधिक आर नाट होने का सीधा मतलब यह है कि इन राज्यों में एक संक्रमित व्यक्ति एक से अधिक व्यक्तियों तक संक्रमण फैला रहा है। जो तीसरी लहर का स्वरूप धारण कर सकता है। वहीं नगालैंड, हरियाणा, मेघालय, गोवा, झारखंड, दिल्ली और बंगाल में आर नाट एक पर स्थिर है। यानी वहां नए मरीजों की संख्या न तो बढ़ रही है और न कम हो रही है। केवल आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में आर नाट में कमी देखी जा रही है।

इतने आर नाट पर अमेरिका तीसरी लहर से जूझ रहा

देश में औसत आर नाट का 1.2 फीसद तक पहुंच जाना तीसरी लहर के लिए गंभीर माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देश कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं, इन देशों में भी आर नाट 1.2 है।

राज्यों को किया सावधान

लव अग्रवाल ने कहा कि बढ़ते आर नाट को देखते हुए राज्यों को सावधान हो जाना चाहिए। कोरोना से बचाव के उपायों को सख्ती से लागू करने का प्रयास करना चाहिए ताकि कोई संक्रमित व्यक्ति कम से कम लोगों तक संक्रमण फैला सके।

44 जिलों में 10 फीसद से ज्यादा संक्रमण दर

डा. वीके पाल ने 44 जिलों में 10 फीसद से अधिक संक्रमण दर का हवाला देते हुए कहा कि दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह केरल व पूर्वोत्तर के राज्यों तक सीमित है। देश के 222 जिलों में मामले कम हो रहे हैं, लेकिन 18 जिलों में मामले बढ़ रहे हैं जो चिंता का कारण है। इनमें से 10 जिले केरल से हैं। इन्हीं 18 जिलों में आधे से ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं।

आर नाट 0.6 से नीचे, मतलब संक्रमण काबू में : नीति आयोग के सदस्य और कोरोना वैक्सीन पर गठित टास्क फोर्स के प्रमुख डा. वीके पाल ने कहा कि आर नाट के 0.6 के नीचे आने पर ही संक्रमण को नियंत्रण में माना जा सकता है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी से साफ है कि वायरस फैल रहा है।

भारत में औसत आर नाट 1.2 : भारत में औसत आर नाट 1.2 है जो 22 जुलाई के पहले यह एक के नीचे बना हुआ था। ध्यान देने की बात है कि दूसरी लहर में नौ मार्च से 21 अप्रैल के बीच आर नाट 1.37 पहुंच गया था। लेकिन मई में इसके एक नीचे आते ही दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी और जून में यह 0.78 तक आ गया था। (कोरोना से जंग-पेज-6)

95 हजार से अधिक लोगों को दिल्ली में मंगलवार को कोरोना का टीका लगा। इनमें 49 हजार 736 लोगों को टीके की पहली डोज व 45 हजार 271 लोगों को टीके की दूसरी डोज दी गई।

'सेवानिवृत्ति में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक डाक्टरों में भेदभाव नहीं'

माला दीक्षित, नई दिल्ली

राहतकारी आदेश : सुप्रीम कोर्ट। फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- दिल्ली नगर निगम के डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 से 65 करने का मामला
- अदालत ने आयुर्वेदिक डाक्टरों को बकाया वेतन और अन्य लाभ भुगतान करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि इलाज प्रणाली के आधार पर एलोपैथी और आयुर्वेदिक डाक्टरों की सेवानिवृत्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इलाज का तरीका इसका आधार नहीं हो सकता। ऐसा करना भेदभाव और संविधान में मिले बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम के आयुर्वेदिक डाक्टरों के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उनकी सेवानिवृत्ति आयु भी 60 से बढ़कर 65 वर्ष 31 मई, 2016 से ही लागू मानी जाएगी, जिस तारीख पर यह सेंट्रल हेल्थ स्कीम के जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसर (एलोपैथी डाक्टर) के लिए लागू हुई। कोर्ट ने कहा कि आयुर्वेदिक डाक्टरों को उनके साथी सेंट्रल हेल्थ स्कीम के डाक्टरों की तरह वेतन और अन्य लाभ न दिया जाना उनके साथ भेदभाव है। कोर्ट ने बढ़ी सेवानिवृत्ति आयु के मुताबिक आयुर्वेदिक डाक्टरों का बकाया वेतन और अन्य लाभ आठ सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया है। तय अवधि से देर में भुगतान किया गया तो छह फीसद की दर से ब्याज भी देना होगा।

दिल्ली नगर निगम के आयुर्वेदिक डाक्टरों के बारे में यह फैसला जस्टिस एल नागेश्वर राव व ऋषिकेश राय की पीठ ने सुनाया है। इस मामले में उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। नगर निगम ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल (कैट) और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम की अपीलें खारिज करते हुए कैट और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। इसमें कहा गया था कि आयुष के तहत आने वाले आयुर्वेदिक डाक्टर भी एलोपैथिक डाक्टरों की तरह ही सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 65 करने का लाभ पाने के अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने में सिर्फ इलाज के तरीके के आधार पर वर्गीकरण करना ठीक नहीं है। दोनों डाक्टर लोगों का इलाज कर रहे हैं।

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से आयुर्वेदिक डाक्टर 60 वर्ष के बाद भी नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में निगम की ओर से दलील दी गई थी कि आयुर्वेदिक डाक्टर इस दौरान का वेतन पाने के अधिकारी नहीं हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 31 मई, 2016 को तत्काल प्रभाव से सेंट्रल हेल्थ स्कीम और जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसर की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ा कर 65 साल कर दी। अधिसूचना भी जारी हो गई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने भारत सरकार के आदेश को लागू करते हुए निगम के एलोपैथी डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 से 65 साल करने का आदेश जारी कर दिया। आयुर्वेदिक डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु नहीं बढ़ी थी। इसलिए उन्होंने कैट में याचिका दाखिल कर भेदभाव की दलीलें देते हुए उनकी भी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 60 से 65 वर्ष करने की मांग की। कैट ने 24 अगस्त, 2017 को बहुत सारे मामलों में एक साथ फैसला देते हुए माना कि यह आयुर्वेदिक डाक्टरों के साथ भेदभाव है। कैट ने कहा कि आयुर्वेदिक डाक्टर समान सेवा शर्तों और बढ़ी हुई 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ पाने के हकदार हैं। नगर निगम ने कैट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी।

दिल्ली हाई कोर्ट में जब अपील लंबित थी, इसी दौरान भारत सरकार के आयुष ने 24 नवंबर, 2017 को आदेश जारी किया और आयुष डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी। केंद्र ने यह आदेश 27 सितंबर, 2017 से लागू किया। हाई कोर्ट ने 15 नवंबर, 2018 को फैसला दिया और कैट के आदेश को सही ठहराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश में आयुर्वेदिक डाक्टरों को 60 साल के बाद भी नौकरी में जारी रहने का आदेश दिया था। हालांकि कहा था कि उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। निगम ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि सेंट्रल हेल्थ स्कीम के डाक्टरों और आयुष डाक्टरों के बीच वर्गीकरण तर्कसंगत और न्याय संगत है। लेकिन कोर्ट ने ये दलीलें खारिज कर दीं। कहा कि आयुष डाक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने वाला 24 नवंबर, 2017 का सरकार का आदेश भी पूर्व तिथि 31 मई, 2016 से लागू होगा।

अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नंबर आवंटित हो गया है तो हम सुनवाई के लिए तारीख तय करेंगे
- याचिकाकर्ता ने अस्थाना की नियुक्ति में लगाया है अवमानना का आरोप

नई दिल्ली, प्रेट्र : राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने वाले वकील ने अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया है।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को वकील एमएल शर्मा से कहा कि अगर रजिस्ट्री ने नंबर आवंटित कर दिया है तो उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। शर्मा ने कहा, मैंने राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है।

याचिका के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने संयुक्त रूप से फैसला किया तथा अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह प्रकाश सिंह मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ है।

शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार, डीजीपी के रूप में नियुक्ति से पहले व्यक्ति की कम-से-कम तीन महीने की सेवा शेष होनी चाहिए।

राकेश अस्थाना। फाइल फोटो

1984 बैच के आइपीएस अधिकारी अस्थाना को 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले हुई थी।

2047 तक ग्लोबल सिटी की तरह विकसित करेंगे दिल्ली : केजरीवाल

लक्ष्य ▶ सभी के सहयोग से ऐसी दिल्ली बनानी है, जिस पर सभी को हो गर्व

कहा– चुनौतियों से निपटने के लिए सभी का सहयोग जरूरी

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

अरविंद केजरीवाल। फाइल फोटो

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार आनलाइन प्लेटफार्म दिल्ली <e>@ 2047 लांच किया। यह प्लेटफार्म सीएसआर और गैरसरकारी दान दाताओं के संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने का मंच है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को 2047 तक ग्लोबल सिटी (वैश्विक शहर) के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। इस मंच के माध्यम से इसी का खाका खींचने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को विकसित करने के लिए नीति और रणनीति बनाई ही जा रही है। इसमें सरकार के सामने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, परिवहन नेटवर्क, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं के समाधान की चुनौती है। इससे निपटने के लिए उद्यमियों और नागरिक समूह का सहयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल जब विधानसभा में दिल्ली सरकार ने बजट प्रस्तुत किया था, उस समय इसकी एक छोटी-सी रूपरेखा हम लोगों ने विधानसभा में प्रस्तुत की थी। चूंकि, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया से लोग पहले दिल्ली आते हैं और फिर यहां से अन्य राज्यों में जाते हैं। यह लोग दिल्ली के जरिये ही पूरे देश को देखते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार इसे ग्लोबल सिटी की तरह विकसित करना चाहती है। 2047 में देश जब आजादी के 100 साल पूरे कर लेगा, तब तक दिल्ली को कहां लेकर जाना है, उसका एक रोडमैप लोगों के साथ मिलकर तैयार करना है।

दिल्ली सरकार ने इसी दृष्टिकोण से बजट में एक विजन रखा था और उसके लिए एक बजट भी रखा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के साथ मिलकर वह दिल्ली को 21वीं सदी की दिल्ली बनाना चाहते हैं, जिस पर सभी को गर्व हो। केजरीवाल ने कहा कि आज 100 से ज्यादा ऐसी सरकारी सेवाएं हैं, जो लोगों को उनके दरवाजे पर मिलती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को वह सिंगापुर के स्तर तक पहुंचाएंगे और 2048 में ओलिंपिक के लिए बोली लगाएंगे।

पहले समस्याएं दूर करें फिर दिखाएं सपना : बिधूड़ी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली को वर्ष 2047 तक वैश्विक शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उसका कहना है कि दिल्लीवासियों की समस्याएं हल करने में नाकाम रहने के बाद अब मुख्यमंत्री उन्हें वर्ष 2047 का सपना दिखा रहे हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि सात साल में दिल्ली को बदहाल करने के बाद एक बार फिर से झूठे वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार की गलत नीतियों के कारण राजधानी की समस्याएं लगातार गंभीर होती जा रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में जिस तरह का मंजर था, उसे कोई नहीं भूल सकता। इसके विपरीत मुख्यमंत्री कोरोना पर जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। आप के शासन में दिल्ली में एक भी नया अस्पताल नहीं खुला है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन इससे बचाव की तैयारी को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में 25 हजार शिक्षकों की कमी है और अतिथि शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। कोई नया स्कूल नहीं बना है। कुछ स्कूलों की इमारतों में सुधार करके शिक्षा में सुधार का दावा किया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन की बुरी स्थिति है।

पार्क में कार्यक्रमों पर एनजीटी की रोक पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सामाजिक, वाणिज्यिक, विवाह या इसी प्रकार के अन्य समारोह के लिए उद्यानों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था।

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में उद्यानों के महीने में 10 दिनों से अधिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एनजीटी के चार फरवरी के आदेश के खिलाफ नगर निकायों की याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अपीलकर्ताओं को बिना कोई नोटिस दिए फैसला सुनाया गया है।

पीठ ने कहा, कि प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें। तदनुसार, अपील के तहत निर्णय और आदेश लागू होने तक रोक रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि उद्यानों (पार्कों) के उपयोग के संबंध में एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और उक्त निर्णय में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किसी भी परिस्थिति में एक महीने में 10 दिन से अधिक समय के लिए उद्यानों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मेडिकल आक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगी दिल्ली

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- मेडिकल आक्सीजन उत्पादन में खर्च बिजली पर चार रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी देगी सरकार
- इस नीति की अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के अंदर सब्सिडी के लिए लिए जाएंगे आवेदन

देश की राजधानी अब मेडिकल आक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को मेडिकल आक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन नीति-2021 को मंजूरी दी है। नीति के तहत भविष्य में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली को मेडिकल आक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति आक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने, भंडारण सुविधाएं और आक्सीजन टैंकर के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कई प्रोत्साहन प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि इस नीति के तहत मेडिकल आक्सीजन उत्पादन की प्रक्रिया में खर्च होने वाली बिजली पर चार रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा संयंत्र के चालू होने के एक महीने के अंदर तरल आक्सीजन उत्पादन संयंत्रों और गैर-कैप्टिव आक्सीजन उत्पादन संयंत्र पर लगे कर की भरपाई की जाएगी। इस नीति की अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के अंदर सब्सिडी के लिए आवेदन लिए जाएंगे। यदि आखिरी तारीख तक आवेदन तय लक्ष्य क्षमता से अधिक आते हैं, तो इसका चयन सभी पात्र आवेदनों का ड्रा निकालकर किया जाएगा।

कोरोना की संक्रमण दर 0.08 फीसद, 50 नए मामले

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर 0.12 फीसद से घटकर 0.08 फीसद पर आ गई है। इस वजह से मंगलवार को कोरोना के 50 नए मामले आए। वहीं, 65 मरीज ठीक हुए, लेकिन इस दौरान चार मरीजों की मौत हो गई। एक अगस्त को संक्रमण दर 0.12 फीसद हो गई थी, तब 85 मामले आए थे। हालांकि, उस दिन 72,447 सैंपल की जांच भी हुई थी। इसके तहत 50,319 सैंपल की आरटीपीसीआर व 22,128 सैंपल की एंटीजन जांच हुई थी। वहीं, पिछले 24 घंटे में 64,276 सैंपल की जांच हुई। इसके तहत 39,498 सैंपल की आरटीपीसीआर व 24,778 सैंपल की एंटीजन जांच हुई।

दिल्ली के विधायकों के वेतन-भत्तों में 66 फीसद बढ़ोतरी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने मंगलवार को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक विधायकों के वेतन और भत्तों में कुल 66 फीसद बढ़ोतरी को मंजूरी दी। अब दिल्ली के विधायकों को 12 हजार की जगह 30 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन के तौर पर मिलेंगे। इसके साथ ही तमाम भत्तों को जोड़ दिया जाए तो अभी के 54 हजार की जगह विधायकों को 90 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। हालांकि, दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली के विधायकों को देश में सबसे कम वेतन मिल रहा है और बीते 10 वर्ष से वेतन नहीं बढ़ा है।

दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली के विधायकों को अन्य राज्यों के विधायकों के बराबर 54,000 रुपये वेतन देने का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा दिल्ली सरकार का कहना है कि कई राज्य अपने विधायकों को हाउस रेंट, आफिस रेंट, कर्मचारियों का खर्च, कार्यालय के उपकरण खरीदने के लिए भत्ता, उपयोग के लिए वाहन, चालक भत्ता आदि देते हैं, लेकिन दिल्ली के विधायक इन सुविधाओं व भत्तों से वंचित हैं। सरकार ने दावा किया कि दिल्ली के विधायकों के वेतन व भत्तों में वृद्धि का प्रस्ताव पिछले पांच वर्ष से गृह मंत्रालय के पास लंबित था।

महिला अपराधों पर केजरीवाल की चुप्पी चिंताजनक : कांग्रेस

ओल्ड नांगल राय गांव की घटना के विरोध में मुंह पर पट्टी और हाथों में तख्ती लेकर विरोध मार्च निकालती महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। सौजन्य : कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में महिलाओं और बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराधों के कारण दिल्ली की स्थिति चिंताजनक हो गई है। हैरत की बात यह कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली छावनी के ओल्ड नांगल राय गांव में नौ साल की दलित बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले पर पूरी तरह चुप्पी साधे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी इस जघन्य मामले को पूरी तरह दबाने की कोशिश की। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद ही पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा और बच्ची के अधजले शरीर को पोस्टमार्टम और फारेंसिक जांच के लिए भेजा। चौधरी ओल्ड नांगल राय गांव में पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश उपाध्यक्ष जयकिशन ने कहा कि कहा, पार्टी का विधिक एवं मानव अधिकार विभाग पीड़ित परिवार को कानूनी मदद प्रदान करेगा। वहीं, महिला कांग्रेस ने आइटीओ चौक पर प्रदर्शन कर केजरीवाल का पुतला फूंका ।

> नौ साल की मासूम के साथ हैवानियत के बाद हत्या बेहद शर्मनाक है। दिल्ली में कानून-व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। न्याय की इस लड़ाई में परिवार की हर संभव मदद की जाएगी।
>
> -अरविंद केजरीवाल (मुख्यमंत्री)

जयपुर गोल्डन अस्पताल में आक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी मौत : पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: जयपुर गोल्डन अस्पताल में आक्सीजन की कमी से 21 कोरोना मरीजों की मौत नहीं हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में मंगलवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर यह बात कही है। रोहिणी कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी विवेक बेनीवाल ने अस्पताल के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग से संबंधित अर्जी पर पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

ऐसे में रोहिणी जिले के डीसीपी प्रणव तायल की ओर से दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले की जांच के दौरान पता चला कि आक्सीजन की कमी के कारण किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। इस मामले में लगाए गए आरोपों को देखते हुए दिल्ली मेडिकल काउंसिल से भी लापरवाही को लेकर राय मांगी गई है। हालांकि जांच के क्रम में अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि अपर्याप्त आक्सीजन की आपूर्ति और रोगियों की मृत्यु के बीच एक संबंध था, क्योंकि उन्हें 30 घंटे तक आक्सीजन की आपूर्ति नहीं की गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट में अस्पताल के हवाले से कहा कि 22 अप्रैल को शाम साढ़े पांच बजे 3.8 टन आक्सीजन की आपूर्ति की गई, लेकिन 23 अप्रैल को निर्धारित समय पर कोई रीफिलिंग नहीं हुई।

45 किलो वजन वाली दो वर्षीय बच्ची की सफल वेटलास सर्जरी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

जन्म के बाद लगातार बढ़ रहे वजन से परेशान दो साल की बच्ची की डाक्टरों ने सफल बैरिएट्रिक सर्जरी (वजन कम करने के लिए) की है। इसकी जानकारी अस्पताल के डाक्टरों ने मंगलवार को एक प्रेसवार्ता में दी। सर्जरी मरीज की जान बचाने के लिए जरूरी थी। सर्जरी के एक सप्ताह बाद ही उसका वजन 40 किलो हो गया है। डाक्टरों के अनुसार सुधार जारी है। छह माह महीने में बच्ची का वजन सामान्य रूप से 15 किलो होने की संभावना है। यह आपातकालीन सर्जरी मैक्स हास्पिटल, पटपड़गंज और वैशाली के मैक्स इंस्टीट्यूट आफ मिनिमल एक्सेस, बैरिएट्रिक एंड रोबोटिक सर्जरी के विभागाध्यक्ष डा. विवेक बिंदल ने की। डाक्टर बिंदल ने बताया कि बच्ची ख्याति को आब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (सोते समय सांस लेने में परेशानी) हो गया था। वह अब तक न तो घुटने के बल और न ही पैरों से चली थी। साथ ही पीठ के बल लेटकर सो भी नहीं सकती थी। पिछले छह महीनों से व्हीलचेयर पर ही रह रही थी। क्योंकि वजन के कारण उसके माता-पिता उसे उठाने में असमर्थ थे। बच्ची का बीएमआइ (बाडी मास इंडेक्स) 41.5 था।

सर्जरी से पहले इतनी मोटी थी ख्याति। सौजन्य-अस्पताल

डाक्टर ने बताया कि इस उम्र में सामान्य विकास करने वाले बच्चे का वजन 12 से 15 किलोग्राम के बीच होता है। वहीं, बच्चों में बैरिएट्रिक सर्जरी किए जाने की निम्नतम उम्र सीमा 12-15 वर्ष है। चूंकि बच्चों में बैरिएट्रिक सर्जरी न के बराबर होती है। इसलिए ख्याति को पिछले एक दशक में भारत में सबसे कम उम्र की बैरिएट्रिक सर्जरी रोगी कहा जा सकता है। सर्जरी की टीम में डा. मनप्रीत सेठी, डा. राजीव उत्तम और डा. अरुण पुरी शामिल थे, जिन्होंने आपरेशन से पहले और बाद में बच्चे को अपनी निगरानी में रखा। डा. सेठी ने कहा कि यह बच्ची जन्म के समय सामान्य थी। उसका वजन 2.5 किलोग्राम था।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सात किलो सोने की छड़ें बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त हैं। सुरक्षा बलों की चौकसी का ही नतीजा है कि गत दिनों रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने सोने की छड़ें लेकर दिल्ली आए दो तस्करों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दबोच लिया। दोनों को थाने लाकर पूछताछ के बाद कस्टम अधिकारी को सौंप दिया गया।

रेलवे सुरक्षा बल के जवान अविनाश, संजय, जितेंद्र, कुलदीप ने एक अगस्त को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 3.53 करोड़ रुपये मूल्य की 7.379 किलो सोने की छड़ें बरामद की थी। इन्होंने प्लेटफार्म नंबर छह-सात पर सोना की तस्करी के मामले में दो लोगों को पकड़ा। पूछताछ करने पर उनकी पहचान शेख अब्दुल जब्बार, बंगाल व शेख मुस्तफीजुर रहमान, मेदिनीपुर, बंगाल के रूप में हुई। दोनों लखनऊ से शताब्दी एक्सप्रेस से आए थे। उन्हें थाने लाकर कस्टम विभाग को सूचना दी गई। कस्टम निरीक्षक विनोद कुमार ने थाने पहुंचकर सोने की छड़ों को अपने कब्जे में ले लिया। महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने उपरोक्त चारों रेलवे सुरक्षा बलकर्मियों को ड्यूटी पर सतर्कता बरतने, ईमानदारी और निष्ठा के लिए प्रत्येक को 5000-5000 रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया।

मेट्रो स्टेशनों में प्रवेश की परेशानी अभी भी कायम

लंबी लाइनें

स्टेशनों में प्रवेश के लिए एक ही गेट खुल रहे, ऐसे में बाहर लग जा रही हैं लंबी लाइनें, कारोबारी संगठनों और यात्रियों ने मेट्रो के और गेट खोलने की मांग की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

नई दिल्ली-कनाट प्लेस में मेट्रो में सफर करने के लिए यात्रियों की लगी लंबी कतार। ध्रुव कुमार

मेट्रो ट्रेन में बैठने वालों की संख्या तो बढ़ा दी गई है, पर स्टेशनों में प्रवेश के अभी भी सीमित द्वार खोले जा रहे हैं। इसके चलते बाहर लंबी लाइनें लग जा रही हैं। व्यस्त समय में स्टेशनों में प्रवेश के लिए आधे से एक घंटे लग रहे हैं। इसके चलते किसी स्टेशनों के बाहर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है तो अधिकतर स्टेशनों पर भीड़ के चलते कोरोना दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) ने सभी सीटों पर यात्रियों को बैठाने की मंजूरी दी है, पर गेटों की व्यवस्था यथावत रखी है।

दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन, भागीरथ पैलेस के अध्यक्ष आशीष ग्रोवर ने कहा कि मेट्रो में बैठने की संख्या तो बढ़ा दी गई है पर प्रवेश द्वारों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। इसके चलते स्टेशनों में प्रवेश को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि खुले हुए गेटों पर प्रवेश के लिए लोगों का दबाव दोगुना से अधिक हो गया है। स्थिति यह है कि व्यस्त समय में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में प्रवेश के लिए आधे किमी से अधिक की लाइन लग जा रही है। लोग एक-दूसरे पर गिरे जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन के भीतर प्रवेश में एक घंटे से अधिक लग जा रहे हैं। यह काफी खराब स्थिति है। इसके चलते कोरोना दिशानिर्देशों का पालन भी नहीं हो रहा है।

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, दिल्ली के महासचिव हेमंत गुप्ता ने मांग करते हुए कहा कि मेट्रो स्टेशनों के जितने अधिक गेट खुलेंगे, उतनी ही बाहर भीड़ कम होगी। इससे लोगों को सहूलियत होगी। अधिक संख्या में लोग बाजारों में आने की सोचेंगे। इससे बाजारों का कारोबार बढ़ेगा। छात्र अपूर्वा नोएडा से दिल्ली की यात्रा रोजाना करती हैं। उन्होंने कहा कि नोएडा से दिल्ली आना तो आसान होता है। पर जाना उतना ही मुश्किल, क्योंकि शाम के वक्त मेट्रो स्टेशन में प्रवेश के लिए लड़कियों की लाइनें भी काफी अधिक होती है। पुरुषों की लाइन तो उससे भी कहीं अधिक होती है। इसलिए प्रवेश के लिए सभी द्वार खोले जाने चाहिए। इस संबंध में मेट्रो प्रवक्ता ने कहा कि मेट्रो ट्रेनों के भीतर भीड़ कम रखने के लिए और कोरोना दिशानिर्देशों के पालन के लिए प्रवेश के द्वार सीमित किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक वैसे भी इस व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा। उसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए विचार किया जा सकता है।

अगर आपका मामला उसमें नहीं तो क्यों आए हैं : कोर्ट

प्रथम पृष्ठ से आगे

अर्जी देने वालों की ओर से मंगलवार को पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि मैरिज फार्म उनकी अपनी जमीन पर हैं। इस पर पीठ ने कहा कि यहां सिर्फ वन भूमि पर अवैध कब्जे के मामले पर सुनवाई हो रही है। अगर आपका मामला उसमें नहीं आता तो फिर क्यों आए हैं। रोहतगी ने कहा कि जिस जमीन पर उनके फार्म हैं वह वन भूमि अधिसूचित नहीं है बल्कि पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट (पीएलपीए) में नोटिफाई है। वैसे भी इनमें से 13 लोग सुप्रीम कोर्ट के पूर्व संरक्षण आदेश के तहत कामकाज कर रहे हैं। उनके काम पर एनजीटी ने रोक लगाई थी लेकिन उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को शुक्रवार को सुनेंगे। साथ ही फरीदाबाद नगर निगम से कहा कि अगर इनका निर्माण वन भूमि में आथराइज्ड स्ट्रक्चर है तो शुक्रवार तक कुछ मत करिये। लेकिन अगर वन भूमि पर अवैध निर्माण है तो हटा दीजिए। कोर्ट ने रोहतगी के मुवक्किलों को बुधवार दोपहर अथारिटी के समक्ष संबंधित दस्तावेज पेश कर अपनी बात साबित करने का मौका दिया। सुनवाई के दौरान संजय पारिख ने कहा कि जब भी निगम से बेघर लोगों के अस्थायी आश्रय की मांग की जाती है वे सभी को राधास्वामी कांप्लेक्स भेज देते हैं। लेकिन वह भी वन भूमि पर है। इस पर कोर्ट ने निगम के वकील से पूछा कि क्या वह वन भूमि पर है, भारद्वाज ने कहा, नहीं। कोर्ट ने पारिख से कहा कि उन्हें कोर्ट में सही बात रखनी चाहिए लेकिन तभी एक वकील ने कहा कि एनजीटी के मुताबिक राधास्वामी वन भूमि पर है। भारद्वाज ने कहा कि वह इस बारे में पता करेंगे। बाद में गोन्साल्विस ने फार्म हाउसों का मुद्दा उठाया। इस पर पीठ ने कहा कि वह साफ आदेश दे चुके हैं कि वन भूमि से सभी अवैध निर्माण हटेंगे। राधा स्वामी कांप्लेक्स भी अगर वन भूमि पर है तो वह भी हटेगा।

31 अगस्त से होंगे एम टेक में दाखिले के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) के रजिस्ट्रेशन। आइआइटी खड़गपुर ने इसके लिए gate.iitkgp.ac.in पोर्टल शुरू किया है।

अब सभी स्कूलों में मिलेगा एनसीसी का प्रशिक्षण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : युवाओं में सेना और दूसरे सुरक्षा बलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अब सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को अनिवार्य एनसीसी (नेशनल कैडेट कोर) प्रशिक्षण से जोड़ने की तैयारी में है। इस दिशा में काम शुरू हो गया है। फिलहाल इसकी शुरुआत सभी केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों से होगी। इस दौरान आदिवासी बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता से शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्कूलों में एनसीसी विंग के विस्तार की यह योजना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद बनाई गई है, जिसमें रक्षा मंत्रालय की मदद से राज्य सरकारों को इसके लिए प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। साथ ही कहा गया है कि इससे छात्रों की प्रतिभा की पहचान में मदद मिलेगी। इससे वे सेना और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अपने करियर को भी संवार सकेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। पहले चरण में देशभर के सभी केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में इस प्रशिक्षण को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यों को भी इसकी तैयारी करने को कहा है। फिलहाल ऐसे सभी केंद्रीय व नवोदय विद्यालयों की जानकारी जुटाई जा रही है, जहां मौजूदा समय में एनसीसी प्रशिक्षण की सुविधा नहीं है।

आजादी के बाद गोदाम तो भरे, पर भुखमरी में कमी नहीं आई : मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा ▸ सदी की सबसे बड़ी आपदा में भी कोई भूखा नहीं रहा

गरीबों को सशक्त करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के बाद से खाद्य भंडार तो भरते रहे, लेकिन भुखमरी और कुपोषण में कमी नहीं आई। डिलिवरी सिस्टम की खामियां इसकी मूल वजह थी। वर्ष 2014 के बाद स्थिति बदली और सदी की सबसे बड़ी आपदा में भी कोई भूखा नहीं रहा। देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। यह योजना दीवाली तक लागू रहेगी। इस पर तकरीबन दो लाख करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबों का सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू होने के बाद लाभार्थी उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में लगभग दोगुना राशन मिल रहा है।

नई दिल्ली में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। प्रेट

पीएम मोदी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाइ) के गुजरात के लाभार्थियों से बातचीत करने बाद खाद्य प्रबंधन की खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि सालों साल से गोदामों में अनाज का स्टाक बढ़ता रहा, लेकिन उस अनुपात में भुखमरी और कुपोषण में कमी नहीं आई। आजादी के बाद सभी सरकारें गरीबों को सस्ता भोजन देने की बात कहती रहीं, इसके लिए चलाई गईं योजनाओं का दायरा और बजट साल दर साल बढ़ता गया, लेकिन अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद नई तकनीक का उपयोग करके करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को राशन प्रणाली से बाहर कर दिया गया। राशन कार्डों को आधार नंबर से जोड़ दिया गया, जिससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिली है। खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए देश के 33 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में वन नेशन-वन राशन प्रणाली लागू कर दी गई है। कोरोना के चलते देशव्यापी लाकडाउन में गरीबों और मजदूरों का संकट बढ़ गया था, लेकिन सरकार ने तय किया था कि देश का कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा।

मोदी ने कहा कि गांवों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष जोर दिया है। इस पर लाखों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। दो करोड़ से अधिक परिवारों को पक्का मकान मिला है। 10 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह हर व्यक्ति को जनधन खाते से जोड़कर बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, बीते वर्ष के दौरान 9.48 करोड़ टन खाद्यान्न का आवंटन किया गया था, जो सामान्य वर्ष के मुकाबले 50 फीसद अधिक है। इस दौरान कुल 2.84 लाख करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी दी गई।

हथियार व गोला-बारूद की निर्बाध आपूर्ति की तैयारी

बड़ा कदम
- अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक को मिली लोकसभा की मंजूरी
- विपक्ष ने कहा, आयुध कर्मियों के अधिकार छीन रही सरकार

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच मंगलवार को 'अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021' को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में राष्ट्र की सुरक्षा एवं जन-जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनिवार्य रक्षा सेवाएं बनाए रखने का उपबंध किया गया है। यह विधेयक संबंधित 'अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021' का स्थान लेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसका मकसद यह है कि हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति में बाधा नहीं आए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आयुध कारखानों के नियोक्ताओं और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से अच्छी चर्चा की गई है। इसमें कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा गया है, अतः इस विधेयक को आम-सहमति से पारित किया जाना चाहिए। इससे पहले विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर जो स्थिति है उससे पूरा सदन अवगत है। इसलिए हमारी सेना को आयुध की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पूर्व का कानून खत्म हो चुका है। आवश्यक रक्षा आयुध सेवाओं के लिए कानून नहीं था। उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए मंत्रिमंडल ने 30 जून को अध्यादेश को मंजूरी दी।

भट्ट ने इस बात पर बल दिया कि किसी भी कर्मचारी और अधिकारी के हितों को प्रभावित करने वाला कोई प्रविधान विधेयक में नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे मित्रों (सदस्यों) ने जो आपत्तियां दी हैं वे निराधार हैं। कहीं भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है। कर्मचारियों को मिलने वाली सुख-सुविधा में कोई कटौती नहीं होती है। रक्षा राज्य मंत्री ने सदस्यों से अपील की कि सब मिलकर इस विधेयक को पारित करें, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। रिवाल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 को पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इसमें कर्मचारियों की हड़ताल रोकने का प्रविधान है जो संविधान में मिला मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक कामगार वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों को समाप्त करने वाला है और सदन में व्यवस्था नहीं होने पर इस विधेयक को पेश नहीं कराया जाना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार आयुध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि सदन नहीं चल रहा है तो इस तरह का विधेयक पारित नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि पेगासस मामले पर चर्चा हो और फिर सभी मुद्दों पर चर्चा हो। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने भी विधेयक का विरोध किया। निचले सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए सशस्त्र बलों को आयुध मदों की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना और आयुध कारखानों का बिना किसी व्यवधान के कार्य जारी रखना अनिवार्य है। रक्षा से संबद्ध सभी संस्थानों में अनिवार्य रक्षा सेवाओं के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए लोकहित में या भारत की संप्रभुता और अखंडता या किसी राज्य की सुरक्षा या शिष्टता या नैतिकता के हित में सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए। चूंकि संसद सत्र नहीं चल रहा था और तुरंत विधान बनाने की जरूरत थी, ऐसे में राष्ट्रपति ने 30 जून, 2021 को अनिवार्य रक्षा सेवा अध्यादेश, 2021 प्रख्यापित किया था।

रंग लाई राहुल की विपक्षी एकता की पहल

नाश्ते पर बैठक ▸ तृणमूल समेत 15 दल बैठक में जुटे, बसपा और आप ने बनाई दूरी

- पेगासस, महंगाई, किसानों के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट, ठप रही संसद
- विपक्षी सांसदों ने राहुल संग संसद तक किया साइकिल मार्च

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस जासूसी कांड, महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी की नाश्ते पर बुलाई गई बैठक कामयाब रही। अब तक कांग्रेस की रहनुमाई में आने से हिचक रही तृणमूल कांग्रेस के नेता भी इसमें शरीक हुए, जिससे विपक्षी गोलबंदी को नई ऊर्जा मिली। 15 दलों के करीब 100 से ज्यादा सांसदों ने नाश्ते के बाद राहुल की अगुआई में मंगलवार को संसद तक साइकिल मार्च निकाला।

विपक्ष ने पेगासस मामले के साथ पेट्रोल व डीजल के अलावा आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ दोनों सदनों में हंगामा कर सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस कारण 10वें दिन भी संसद सुचारु रूप से नहीं चल पाई।

विपक्षी एकजुटता से मानसून सत्र में सरकार व विपक्ष के बीच जारी गतिरोध का हल निकलने की उम्मीद और कम हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाकर मोदी सरकार देश के 60 फीसद लोगों को चुप कराना चाहती है, लेकिन अब हमारी आवाज कोई दबा सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे।

पेगासस समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर नई दिल्ली में मंगलवार को कंस्टीट्यूशन क्लब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अगुआई में विपक्षी नेताओं की नाश्ते पर बैठक हुई। एएनआइ

नाश्ते पर चर्चा के लिए 17 दलों को न्योता भेजा गया था। इसमें 15 पार्टियां शामिल हुईं। बसपा और आम आदमी पार्टी इस पहल में शरीक नहीं हुईं। तृणमूल कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी, द्रमुक, एनसीपी, राजद, झामुमो, शिवसेना, माकपा, भाकपा, आरएसपी, आइयूएमएल, केसीएम, नेशनल कांफ्रेंस और एलजेडी के नेता शामिल हुए। विपक्षी नेताओं की इस चर्चा में तय हुआ कि केवल पेगासस मामले ही नहीं जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में सरकार की आक्रामक घेराबंदी जरूरी है। महंगाई और कृषि कानूनों को रद करने की मांग भी आक्रामक रूप से उठाने पर सहमति बनी। इस रणनीति के अनुरूप राहुल और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने कंस्टीट्यूशन क्लब से संसद तक साइकिल मार्च निकाल पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। संसद के दोनों सदनों में भी मंगलवार को विपक्ष के स्वर कुछ ज्यादा तेज दिखे। बार-बार के व्यवधान के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। नाश्ते पर बैठक में विपक्षी दलों में फिलहाल माक संसद बुलाने के प्रस्ताव पर जल्दबाजी करने के बजाय सरकार की अगली रणनीति का इंतजार करने पर सहमति बनी।

राहुल ने बैठक में आए नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि इस बैठक का एक ही उद्देश्य है कि विपक्ष को एकजुट किया जाए। एकजुटता जितनी मजबूत होगी भाजपा व संघ के लिए विपक्ष की आवाज दबाना उतना ही कठिन होगा। विपक्षी गोलबंदी की राहुल की कामयाबी से गदगद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तो इसे 2024 का ट्रेलर तक कह दिया। उनका कहना था कि नाश्ते पर हुई बैठक में जितने दल शामिल हुए वे 60 फीसद भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें जबरदस्त समन्वय और सहयोग दिखा है। विपक्षी पार्टियां नए संकल्प और नए उददेश्य से आगे बढ़ी हैं। इस एकता से घबरा कर भाजपा बेतुके सवाल उठा रही है। हम भाजपा के ध्यान भटकाने वाले प्रयास कामयाब नहीं होने देंगे।

झांसी स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, प्रेट्र : उप्र सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर 'वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन' करने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि उप्र सरकार के प्रस्ताव पर प्रक्रिया के तहत संबंधित एजेंसियों से प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां मांगी गई हैं। एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि सभी संबंधित एजेंसियों से प्रतिक्रियाएं और टिप्पणियां आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

संसद में पारित विधेयकों की तुलना तृणमूल कांग्रेस सदस्य डेरेक ओ ब्रायन द्वारा पापड़ी चाट से किए जाने पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। वहीं, मंगलवार को नई दिल्ली में डेरेक ओ ब्रायन और काकोली घोष दस्तीदार ने पापड़ी चाट खाई। प्रेट्र

एससीओ सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे रिजिजू

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्य देशों के न्याय मंत्रियों की आठवीं बैठक में शरीक होंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, वर्चुअल बैठक में महामारी में कानूनों की भूमिका, राष्ट्रीय कानून के मुताबिक, नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता मुहैया करने, भ्रष्टाचार से निपटने में (कानून एवं) न्याय मंत्रालयों की भूमिका तथा विधिक सेवाओं में सहयोग से संबद्ध क्षेत्रों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। सत्रों की समाप्ति के बाद एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सस्ती लोकप्रियता के लिए राहुल अपना रहे हथकंडे : भाजपा

नई दिल्ली, प्रेट्र: भाजपा ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सस्ती लोकप्रियता के लिए 'हथकंडे' अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष ने संसद की कार्यवाही को बंधक बनाने और सरकार को बदनाम करने के लिए 'हंगामा करने और भाग निकलने' की रणनीति अपनाई है।

केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा में उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्षी सदस्य खुद को भाजपा विरोधी समूह के नेता के रूप में पेश करने की होड़ में हैं। इसके लिए सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए एक-दूसरे से प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं। मोदी का विरोध करते-करते विपक्ष देश विरोध पर उतर आया है। ज्ञात हो कि पेगासस जासूसी मामले और तीन केंद्रीय कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रहे हैं और इस वजह से कार्यवाही बाधित हो रही है। संसद में विपक्षी दलों की रणनीति को धार देने के लिए राहुल गांधी ने मंगलवार को समान विचारधारा वाले दलों के नेताओं के साथ नाश्ते पर चर्चा की और मंहगाई के विरोध में संसद तक साइकिल मार्च निकाला। राज्यसभा सदस्य व भाजपा के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी ने कहा कि राहुल गांधी कभी ट्रैक्टर चलाकर तो कभी साइकिल से संसद पहुंचकर सस्ती लोकप्रियता के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए इस प्रकार की बातें करते रहते हैं।

एडिटर्स गिल्ड ने पेगासस मामले में जांच के लिए दायर की याचिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने पेगासस जासूसी साफ्टवेयर के जरिये सरकार द्वारा पत्रकारों और अन्य पर कथित तौर पर नजर रखने की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि पत्रकारों का काम है कि वे जनता को सूचना देने और सरकार को जवाबदेह बनाने का काम सुनिश्चित करें। गिल्ड के सदस्यों और सभी पत्रकारों का कर्तव्य है कि वे राज्य की कार्रवाई और निष्क्रियता के लिए सूचना, स्पष्टीकरण और संवैधानिक रूप से वैध औचित्य की मांग करके सरकार की सभी शाखाओं को जवाबदेह ठहराएं। साथ ही यह भी कहा कि इस भूमिका को पूरा करने के लिए प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। याचिका में कहा गया, प्रेस की स्वतंत्रता पत्रकारों की रिपोर्टिंग में सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जाने पर निर्भर होती है।

नायडू ने संसद का गतिरोध खत्म करने की पहल की

जाब्यू, नई दिल्ली : संसद के गतिरोध को समाप्त कराने के लिए राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्ष के नेताओं से संयुक्त रूप से समाधान की अपील की है। इस दिशा में पहल करते हुए नायडू ने मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ इस गंभीर विषय पर चर्चा की। उन्होंने सदन में जारी गतिरोध को दूर करने पर मंत्रणा की।

सभापति नायडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल के साथ शाम को समाधान करने के लिए बैठक की। बैठक में सरकार की ओर से पहल करने और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमति बनाने पर चर्चा की गई। उन्होंने सरकार से भी इस गतिरोध को समाप्त करने की पहल करने का अनुरोध भी किया। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ है, लेकिन बीते दो सप्ताह के दौरान सदन ठीक से नहीं चल पाया है। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने कुछ जरूरी कामकाज करा जरूर लिए हैं, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी है।

विपक्षी दल पेगासास जासूसी मामले, कृषि कानूनों के साथ अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की यह भी मांग है कि पेगासस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। विपक्ष के हंगामे के कारण मंगलवार को भी राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई।

लालकिले के जश्न-ए-आजादी में घर बैठे भी कर सकेंगे 'प्रतिभाग'

- 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को यादगार बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने लांच की विशेष वेबसाइट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोविड महामारी के इस दौर में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से देश ही नहीं, दुनियाभर के भारतीयों को एकसाथ जोड़ने की पहल की है। इसके लिए विशेष इंटरैक्टिव वेबसाइट विकसित की गई है, जिसमें देश के हर हिस्से के आम नागरिक भी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराने से लेकर आजादी के जश्न से जुड़ी तस्वीरों को साझा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के माध्यम से दूर रहकर भी लालकिले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक समारोह में वर्चुअल रूप से शामिल होने का एहसास कर सकेंगे।

रक्षा सचिव डा. अजय कुमार ने मंगलवार को इंडियनआइडीसी2021. एमओडी.जीओवी.इन नामक इंटरैक्टिव वेबसाइट लांच की। इसका मोबाइल एप भी जल्द ही लांच किया जाएगा। वेबसाइट के जरिये सुदूर अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव से लेकर कन्याकुमारी के तट तक, अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक देश-विदेश में कहीं से भी लोग 15 अगस्त को लालकिले के जश्न में वर्चुअल रूप से शरीक हो सकेंगे। लोग आजादी के रंग से सराबोर अपनी तस्वीरों और कार्यक्रमों को भी इस प्लेटफार्म पर साझा कर सकेंगे।

इस मौके पर रक्षा सचिव ने कहा कि यह प्लेटफार्म और इससे जुड़े इंटरनेट मीडिया हैंडल कोविड के इस दौर में लालकिले के स्वतंत्रता दिवस समारोह से लोगों की दूरियां घटाएंगे। वेबसाइट में स्वतंत्रता दिवस समारोह रेडियो गैलरी, ई-बुक्स, वीरता पदक से लेकर 1971 में पाकिस्तान से जंग में मिली जीत की 50वीं वर्षगांठ और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े ब्लाग की अलग-अलग गैलरी भी हैं, जो लोगों को खूब आकर्षित करेंगी। डा. अजय ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के दौरान जल्द ही इंडिया गेट पर स्थित वार मेमोरियल में एक विशेष डिजिटल कियोस्क लगाया जाएगा, जहां शहीद हुए तमाम सैनिकों के साथ-साथ अपने प्रेरणास्रोत जांबाज शहीद को श्रद्धांजलि दी जा सकेगी। लोग जांबाज शहीद को श्रद्धांजलि देने की यादगार तस्वीर भी अपने कैमरे में कैद कर सकेंगे। रक्षा सचिव के मुताबिक, पूरे देश में रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र सेनाओं की ओर से 40 विशेष स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि इस ऐतिहासिक वर्ष की स्मृतियों को विशेष रूप से यादगार बनाया जा सके।

लोकसभा प्रश्नोत्तर

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने दी जानकारी, सबसे ज्यादा 49 हत्याएं झारखंड में

तीन साल के दौरान हुईं 230 राजनीतिक हत्याएं

नई दिल्ली, प्रेट्र : 2017 और 2019 के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक कारणों से 230 लोगों की हत्याएं हुईं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि इन हत्याओं में से 49 झारखंड में, 27 बंगाल में और 26 बिहार में हुई हैं। राय ने कहा कि 2017 में 99, 2018 में 59 और 2019 में 72 राजनीतिक हत्याएं हुईं। तीन वर्षों में हुईं राजनीतिक हत्याओं में से 24 कर्नाटक में और केरल एवं महाराष्ट्र में 15-15 हुई हैं।

फरवरी में समझौते के बाद से संघर्ष विराम उल्लंघन की छह घटनाएं : एक लिखित उत्तर में राय ने कहा कि फरवरी में भारत और पाकिस्तान के जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग से संबंधित सभी समझौतों का पालन करने पर सहमति के बाद से संघर्ष विराम उल्लंघन की केवल छह घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में संघर्ष विराम उल्लंघन की 5,133, 2019 में 3,479 और 2018 में 2,140 घटनाएं हुई थीं।

किसी को करतारपुर कारिडोर से यात्रा की अनुमति नहीं दी गई : गृह राज्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से करतारपुर कारिडोर से होकर श्रद्धालुओं का पाकिस्तान जाना निलंबित है। पाकिस्तान ने इस साल अप्रैल में कोविड के मामलों में वृद्धि देखते हुए भारत से सभी तरह की यात्रा पर रोक लगा दी। पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर, 2019 को करतारपुर कारिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत भारत से सभी धर्मावलंबी करतारपुर कारिडोर से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब तक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। करतारपुर साहिब सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है।

नए राज्य के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं : नित्यानंद ने कहा कि केंद्र के पास किसी राज्य के बंटवारे का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यहां तक कि विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों से इस संबंध में मांगें मिलती रहती हैं। तमिलनाडु के सांसद टीआर पारिवेंधर और एस. रामलिंगम ने लोकसभा में सवाल किया था कि क्या केंद्र सरकार तमिलनाडु समेत देश के किसी राज्य को बांटने पर विचार कर रही है।

पिछले तीन साल के दौरान पुलिस हिरासत में 348 मौतें : राय ने बताया कि पिछले तीन साल के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में करीब 348 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हो गई जबकि हिरासत में प्रताड़ना के 1,189 मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मिली सूचना के आधार पर 2018 में 136, 2019 में 112 और 2020 में 100 लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई।

पुलिस में महिलाओं की उपस्थिति 33 फीसद करने के लिए पांच परामर्श भेजे : गृह राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर 33 फीसद करने को कहा है ताकि प्रत्येक थाने में तीन महिला उप-निरीक्षक (एसआइ) और 10 महिला पुलिस कांस्टेबल हों। उन्होंने कहा कि महिला पुलिस कर्मियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर कुल पुलिस कर्मियों का 33 फीसद करने के लिए 2013 से सभी राज्यों को पांच परामर्श भेजे गए और अंतिम परामर्श 22 जून, 2021 को भेजा गया।

तीन वर्ष में साइबर अपराध के 93,000 से ज्यादा मामले सामने आए : नित्यानंद राय ने कहा कि देश में 2017 से 2019 के बीच साइबर अपराध के 93000 मामले सामने आए। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान साइबर आतंकवाद के 46 मामलों की रिपोर्ट मिली और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66एफ के तहत एफआइआर दर्ज की गईं।

बांग्लादेश तस्करी हो रहे 1.24 लाख पशुओं के सिर जब्त किए गए : केंद्रीय गृह राज्यमंत्री निशीथ प्रमाणिक ने एक सवाल के लिखित उत्तर में लोकसभा में कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने 2019 और 2020 के दौरान बांग्लादेश तस्करी किए जा रहे 1.24 लाख पशुओं के सिर जब्त किए। उन्होंने कहा कि 2019 में 77,410 सिर और 2020 में 46,809 सिर जब्त किए गए। सुरक्षा एजेंसियों ने दो वर्षों में करीब 1,163 तस्करों को भी पकड़ा।

कह के रहेंगे माधव जोशी

2015 के नवंबर माह में पीएम के विकास पैकेज के तहत स्वीकृत 56,261 करोड़ के 54 प्रोजेक्ट में से जून, 2018 तक सात प्रोजेक्ट पूरे हुए थे जम्मू-कश्मीर में। अब 21 पूरे हो चुके हैं। 12 और इस साल पूरे हो सकते हैं।

त्रिवेंद्र को दिया जा सकता है उप्र का प्रभार

राज्य ब्यूरो, देहरादून : उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सियासी तजुर्बे का इस्तेमाल भाजपा अब संगठन में करने की तैयारी में है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें बतौर चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है। त्रिवेंद्र पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव सह प्रभारी की भूमिका निभा चुके हैं। बीते रोज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात के बाद इस तरह की चर्चाओं को बल मिला है।

मार्च 2017 में उत्तराखंड के सीएम बने त्रिवेंद्र को इसी मार्च में अपना चार साल का कार्यकाल पूर्ण होने से कुछ ही दिन पहले पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि भाजपा उनका उपयोग केंद्रीय संगठन में कर सकती है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल से ठीक पहले सियासी गलियारों में यह चर्चा भी रही कि केंद्र में मंत्री बनाकर भाजपा मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की उनकी कसक को दूर कर सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका न मिलने पर माना गया कि पार्टी उनके तजुर्बे को देखते हुए उन्हें संगठन में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। नई दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से त्रिवेंद्र ने भेंट की। हालांकि, त्रिवेंद्र ने इन्हें महज शिष्टाचार भेंट बताया। कहा कि गृह मंत्री ने उनसे राज्य के राजनीतिक हालात की जानकारी ली। बकौल त्रिवेंद्र, शाह ने उन्हें 15 अगस्त के बाद फिर दिल्ली आने को कहा है।

भाजपा और रूठे राजभर आए समझौते की मेज पर

उप्र अध्यक्ष स्वतंत्रदेव से मिलने पहुंचे सुभासपा अध्यक्ष बोले, राजनीति में कुछ भी संभव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

पिछले उप्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर लड़ी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर बीते कई माह से अलग ताल ठोंक रहे हैं। सत्ताधारी दल से प्रतिशोध के अंदाज में विपक्षी दलों का संकल्प भागीदारी मोर्चा बनाने में जुटे हैं। इस बीच अटकलें भी चल रही थीं कि एक-दूसरे की जरूरत को समझते हुए भाजपा और सुभासपा 2017 की तरह फिर साथ आ सकती हैं। आखिरकार ना-नुकुर करते-करते राजभर भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंच ही गए। 'राजनीति में कुछ भी संभव है...।' इस बात ने अटकलें तेज कर दीं कि मुलाकात समझौते की मेज पर हुई है। हालांकि, राजभर अभी भी इससे इन्कार ही कर रहे हैं।

चुनावों में लगातार प्रचंड बहुमत हासिल कर रही भाजपा को भरोसा है कि वह अकेले भी 2022 का उप्र विधानसभा चुनाव बहुमत से जीतेगी, लेकिन सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की अपनी रीति-नीति नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि

ओमप्रकाश राजभर फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

कुछ दिन पहले रूठे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को मना लिया गया है। चूंकि पूर्वांचल की कई सीटों पर राजभर वोट का प्रभाव है, इसलिए भाजपा चाहती है कि उप्र के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर भी साथ ही रहें। इधर, राजभर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अपने मोर्चे में शामिल करने की चाहत जाहिर करने के साथ ही आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, एआइएमआइएम के असदुद्दीन ओवैसी और प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव से कई दौर की वार्ता कर चुके हैं। दावा करते हैं कि टीएमसी व शिवसेना से भी गठबंधन की बात चल रही है। भाजपा की भी कोशिश है कि छोटे दलों के खड़े हो रहे इस मोर्चे में सेंध लगा दी जाए। इसमें सबसे अधिक सहूलियत राजभर का हाथ पकड़ने में ही है। मंगलवार सुबह राजभर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह के साथ स्वतंत्रदेव सिंह के गौतमपल्ली स्थित आवास पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि लगभग एक घंटे तक मुलाकात चली। जब पत्रकारों ने राजभर से भेंट का मकसद पूछा तो बोले कि यह औपचारिक मुलाकात थी, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। और कुरेदने पर बोले कि मुलायम सिंह पीएम मोदी से मिल सकते हैं, अखिलेश और मायावती मिल सकते हैं तो राजभर स्वतंत्रदेव सिंह से क्यों नहीं मिल सकते। राजनीति में कुछ भी संभव है।

जब भाजपा से समझौते की संभावना का सवाल किया तो राजभर ने दो टूक कहा कि भाजपा अहंकारी पार्टी है। हमारे दरवाजे सपा और कांग्रेस सहित सभी छोटे दलों के लिए खुले हैं, लेकिन भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उधर, स्वतंत्रदेव सिंह का कहना था कि औपचारिक मुलाकात हुई। कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, जबकि पत्रकारों से चर्चा में दयाशंकर सिंह का कहना था कि 2017 में राजभर भाजपा के साथ थे, इसलिए हम चाहते हैं कि आगे भी साथ रहें।

सांसद की संदिग्ध हालात में हुई मौत पर विधानसभा में हंगामा

राज्य ब्यूरो, शिमला

- हिमाचल प्रदेश में विपक्ष ने सीबीआइ जांच की मांग की, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं

शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध मौत पर खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने प्रश्नकाल आरंभ होने से पहले मामले को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने इस पर नियम-67 यानी स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा मांगी। अनुमति न मिलने पर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने मामले की सीबीआइ जांच करवाने की मांग की। शोर के बीच 22 मिनट तक प्रश्नकाल की कार्यवाही आरंभ नहीं हो सकी। इसके बाद विपक्ष के सदस्य वेल में आए और चार मिनट तक नारेबाजी करते रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सांसद के बेटे के अखबार में जरूर कोई बयान दिया है, लेकिन सरकार के पास किसी प्रकार की जांच करवाने का आग्रह नहीं किया है। सरकार ने इस बयान का कड़ा संज्ञान लेकर मामला पार्टी नेतृत्व के साथ उठाया है। कांग्रेस विधायक इससे संतुष्ट नहीं हुए। इस बीच राज्य विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने स्थगन प्रस्ताव पर दिए गए नोटिस को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाकआउट किया।

जैसे ही 11 बजे प्रश्नकाल की कार्यवाही आरंभ होनी थी, कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि सांसद रामस्वरूप की रहस्यमयी हालत में मौत हुई है। चार माह से फारेंसिक जांच रिपोर्ट, काल डिटेल की रिपोर्ट नहीं आई है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ने कुछ कागजात भी लहराए। विस अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि ऐसे कागजात नहीं लहराए जा सकते हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि 18 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद की मौत की सीबीआइ जांच क्यों हो सकती है।

नेता प्रतिपक्ष और मंत्री भिड़े : अभी मुकेश अपनी बात रख ही रहे थे कि संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि बिना आसन की अनुमति के विपक्ष के सदस्य नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को टोका तो वह मंत्री से भिड़ गए। बोले कि जितनी दफा के विधायक आप हैं, मैं भी उतनी बारी जीत कर आया हूं।

दिल्ली पुलिस कर रही जांच : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि सांसद मौत मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। घटना दिल्ली की है। दूसरी जांच करवाने की जरूरत नहीं है। सांसद के बेटे ने सरकार के पास ऐसी कोई बात नहीं कही है। उन्होंने कहीं बयान दिया है, जिसका जिक्र विपक्ष कर रहा है। सरकार स्वजन को पूरा सहयोग करेगी। मैंने इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बात की है।

गुजरात में कांग्रेस की महिला विधायक के बिगड़े बोल, वीडियो वायरल

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद: उत्तर गुजरात की वाव विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गेनीबेन ठाकोर का डेढ़ माह पुराना एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह भाजपा नेताओं की हत्या करने की बात कहते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में वह कहती हैं कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनी तो भाजपा नेताओं को सचिवालय में घुसने नहीं देंगी और सचिवालय का गंगाजल से शुद्धीकरण कराएंगी, क्योंकि भाजपा ने इसे अपवित्र कर दिया है।

गेनीबेन यह भी कहती नजर आ रही हैं कि देश में किसान परेशान हैं। उनकी परेशानी सभी सीमाएं पार कर चुकी हैं। नहीं चाहते हुए भी उन्हें ऐसे शब्द कहने पड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार चलाने वालों के दिल में किसानों के प्रति हमदर्दी खत्म हो गई है। किसान सम्मेलन के वायरल वीडियो में उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा भी नजर आ रहे हैं।

भाजपा के एक भी नेता को सचिवालय में नहीं घुसने देंगी : वायरल वीडियो 17 जून का बताया जा रहा है। कांकरेज तहसील के एक गांव में गेनीबेन ने किसान सम्मेलन में कहा था कि गुजरात में कांग्रेस सरकार बनती है तो उन्हें मंत्रीपद नहीं चाहिए, बल्कि वह सचिवालय के गेट पर बैठेंगी और भाजपा के एक भी नेता को सचिवालय में नहीं घुसने देंगी। गेनीबेन पूर्व मंत्री शंकरभाई चौधरी को हराकर विधानसभा पहुंची हैं।

गहलोत और पायलट के बीच कैबिनेट विस्तार पर सहमति

कांग्रेस का कलह

- सुलह का सूत्र लेकर दिल्ली पहुंचीं सोनिया की विशेष दूत सैलजा
- विस चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन थीं सैलजा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा दो दिन के प्रवास के बाद दिल्ली पहुंच चुकी हैं। कुमारी सैलजा कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी की विशेष दूत बनकर रविवार जयपुर गई थीं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस दौरान सैलजा की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दो दौर की विस्तृत चर्चा हुई है। इन मुलाकात को मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही तनातनी को खत्म करने के नजरिये से देखा जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पार्टी संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने भी जयपुर प्रवास किया था। सैलजा ने सोनिया के निर्देश पर गहलोत से उन मुद्दों को पर सहमति बनाने का प्रयास किया है जो इन दोनों नेताओं ने बीच में छोड़ दिए थे। सैलजा जयपुर में तैयार गहलोत और पायलट के बीच सुलहनामा की रिपोर्ट

कुमारी सैलजा फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

शीघ्र सोनिया गांधी को देंगी। इसके बाद राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ हो जाएगा।

कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार सैलजा ने हरियाणा प्रदेश प्रभारी बनने से पहले राजस्थान कांग्रेस के सहप्रभारी रहे विवेक बंसल से भी मुलाकात की। दोनों ने हरियाणा कांग्रेस संगठन की सूची को अंतिम रूप देने से लेकर राजस्थान के ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा हुई। सैलजा भी 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन थीं। तब सैलजा ने टिकट वितरण में पार्टी हाईकमान द्वारा तय मापदंड को पूरी तरह लागू करवाने का प्रयास किया था।

सैलजा फिलहाल राजस्थान मुद्दे पर मीडिया के समक्ष चुप हैं क्योंकि उनका यह दौरा हाईकमान के विशेष दूत के रूप में था। इतना अवश्य माना जा रहा है कि सैलजा ने गहलोत के साथ ऐसा सहमति सूत्र तैयार कर लिया है जिस पर पायलट भी राजी हैं।

घोटाले के आरोपित के अधिवक्ता और जज की मुलाकात मामले की हो जांच : सुवेंदु

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज और बंगाल में हुए एक बड़े घोटाले के मुख्य आरोपित के अधिवक्ता की मुलाकात को लेकर ममता सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस मामले की बारीकी से जांच कराए जाने की भी मांग की है।

गौरतलब है कि सुवेंदु ने गत दिनों ट्वीट कर जज और अधिवक्ता की दिल्ली में मुलाकात का दावा किया था। सुवेंदु ने उक्त आरोपित का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका इशारा कोयला व गाय तस्करी के आरोपित विनय मिश्रा की तरफ है। अब उन्होंने ममता बनर्जी सरकार से मामले की जांच की मांग की है।

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर कानून-व्यवस्था बदहाल होगी और न्यायपालिका भी दांव पर लगेगी। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने सुवेंदु अधिकारी के नई दिल्ली में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता से मुलाकात करने का दावा किया था।

नीतीश के नेतृत्व में एकजुट हो सकते हैं समर्थन करने वाले दल

जाति आधारित जनगणना

- इस मुद्दे को नियोजित तरीके से उठा रहा जदयू, उसके इस रुख के समर्थन में कई राज्य आ रहे आगे

राज्य ब्यूरो, पटना

संसद में केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना से इन्कार के बाद जदयू नियोजित तरीके इस मुद्दे को उठा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे कि हमें अपनी बात तो रखनी ही है। जाति आधारित जनगणना का निर्णय लेना या नहीं लेना केंद्र सरकार का विषय है। यह तस्वीर भी सामने आ रही कि बिहार के बाद देश स्तर पर भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस मुद्दे की समर्थक पार्टियां एकजुट हो सकती हैं। नीतीश कुमार के आगे आने के बाद देश के कई राज्यों में जाति आधारित जनगणना का स्वर तेज हुआ है। महाराष्ट्र और ओडिशा में भी यह बात शुरू हो गई है।

करीब तीन दशक पहले ही नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना के समर्थन में आगे आए थे। अब जदयू ने नियोजित तरीके से इस विषय को आगे किया है। जिस दिन संसद में जातिगत जनगणना नहीं कराने की बात आई, उसी दिन नीतीश कुमार ने मुखर होकर कहा कि यह जरूरी है और होना चाहिए। दिलचस्प यह रहा कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नीतीश कुमार के इस रुख को विपक्ष का समर्थन मिल गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ही सबसे पहले सदन में यह कहा कि जाति आधारित जनगणना के मसले पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर इस संबंध में अपनी बात कहे। नीतीश मानसून सत्र के दौरान ही विधानसभा स्थित अपने कक्ष में तेजस्वी यादव सहित कांग्रेस और वाम दलों से इस मुद्दे पर मिले। लंबी अवधि बाद विपक्ष ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसी अभियान पर एकजुटता दिखाई। विपक्ष के साथ हुई बैठक में यह तय हुआ कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को इस मसले पर पत्र लिखेंगे और मिलने का समय मांगेंगे।

जदयू ने 31 जुलाई को दिल्ली में संपन्न अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव भी ले लिया। उस दिन भी इस विषय पर नीतीश कुमार खुलकर बोले। उसके बाद जदयू के सांसदों ने इस मसले पर पर पीएम को पत्र लिखा। फिर जदयू सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। गेंद अब केंद्र के पाले में है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि क्या करना है और क्या नहीं, यह तो केंद्र जाने।

हर महीने सभी घरों को 400 यूनिट मुफ्त बिजली देने का एलान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : शिरोमणि अकाली दल ने 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद करते हुए 13 बड़े चुनावी एलान किए हैं। शिअद ने किसान, युवा, उद्योगपतियों आदि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए महिलाओं पर विशेष फोकस किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी अध्यक्ष सुखबीर बादल ने हर घर को हर महीने 400 यूनिट मुफ्त बिजली देने का एलान किया। इससे अधिक होने वाली खपत पर ही बिल लिया जाएगा। नीला कार्ड धारकों का बिजली बिल माफ होगा। इससे पहले कांग्रेस हाईकमान ने राज्य में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के लिए कैप्टन सरकार को कहा था, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंदर केजरीवाल पंजाब में सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली का एलान कर चुके हैं। सुखबीर ने सेहत सुविधा के लिए हर परिवार का 10 लाख रुपये का बीमा करने, एक लाख सरकारी व 10 लाख निजी क्षेत्र की नौकरियों के प्रबंध करने, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में 75 फीसद पंजाबियों को नौकरी देने के लिए बिल लाने, ठेका कर्मचारियों को पक्का करने, एक साल में सभी सरकारी दफ्तरों का कंप्यूटरीकरण करने का एलान भी किया। इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए जाने के सवाल पर सुखबीर ने कहा कि पार्टी आय के स्रोत बढ़ाने पर अध्ययन कर रही है। जल्द ही उसका एलान भी किया जाएगा।

सुखबीर के वादे

महिलाओं के लिए: नीला कार्ड धारक परिवार की मुखिया महिलाओं को 2000 रुपये प्रति माह और सरकारी नौकरियों में 50 फीसद आरक्षण दिया जाएगा।

किसान : तीनों कृषि कानून पंजाब में लागू नहीं होंगे, पहली ही कैबिनेट में सरकार इन्हें रद करेगी। खेती के लिए डीजल 10 रुपये प्रति लीटर सस्ता दिया जाएगा। दूध, सब्जियों और फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा।

युवा : स्टूडेंट कार्ड बनाए जाएंगे। देश-विदेश में पढ़ने और आइलेट्स की कोचिंग के लिए सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन लेकर देगी और ब्याज खुद अदा करेगी। विद्यार्थी नौकरी मिलने पर अगले दस साल में इसे लौटा सकेंगे। हर जिले में मेडिकल कालेज खोला जाएगा, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 33 फीसद सीटें आरक्षित होंगी।

चीनी की कीमत बढ़वाने के लिए गृह मंत्री शाह से मिले शरद पवार

राकांपा प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चीनी के मूल्य निर्धारण और पेट्रोल में इथेनाल मिश्रण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : महंगाई का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को घेरने वाले विपक्षी दलों में शुमार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को चीनी की कीमत बढ़वाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने पेट्रोल में इथेनाल मिलाए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की।

गृह मंत्री शाह के साथ मुलाकात के बाद पवार ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने चीनी की मौजूदा कीमत पर चर्चा की, जो उत्पादन लागत से भी कम है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार से इस मुद्दे पर गौर करने का आग्रह किया है।

पूर्व कृषि मंत्री पवार ने कहा कि उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों में इथेनाल का मिश्रण बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बातचीत की। बकौल पवार शाह ने उन्हें चीनी उद्योग से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार करने का भरोसा दिया है। इस दौरान पवार के साथ राष्ट्रीय राज्य सहकारी चीनी मिल संघ के अध्यक्ष व रायगढ़ से राकांपा सांसद जयप्रकाश दांडेगांवकर भी मौजूद रहे।

बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर सुनवाई पूरी, हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ ने की सुनवाई
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच समिति ने 13 जुलाई को सौंपी थी अंतिम रिपोर्ट

बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले की सुनवाई मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में पूरी हो गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के नेतृत्व वाली पांच जजों की पीठ ने हिंसा मामले की स्वतंत्र जांच की मांग से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सालिसिटर जनरल से मामले पर सभी स्वतः संज्ञान मामलों के रिकार्ड मुहैया कराने के लिए कहा है। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले से संबंधित सभी पक्षों से कहा कि यदि इस मामले में अब भी उन्हें कुछ कहना है या दस्तावेज देना है तो वे बुधवार दोपहर 2:30 बजे तक लिखित तौर पर अदालत में जमा दे सकते हैं।

गौरतलब है कि हिंसा मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की समिति ने 13 जुलाई को पांच जजों की पीठ के समक्ष सौंपी अपनी अंतिम रिपोर्ट में बंगाल में कानून- व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर

कलकत्ता हाई कोर्ट फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया

सवाल उठाए थे। जांच समिति ने कहा था कि यह मुख्य विपक्षी दल (भाजपा) के समर्थकों के खिलाफ सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा प्रतिशोधात्मक हिंसा थी और दुष्कर्म एवं हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआइ को सौंपने की सिफारिश की थी। हालांकि, इसके बाद राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर एनएचआरसी समिति की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए इसे आधारहीन और राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया था। गौरतलब है कि मामले में हाई कोर्ट ने 18 जून को एनएचआरसी अध्यक्ष को समिति गठित करने के निर्देश दिए थे। समिति की कई टीमों ने बंगाल के विभिन्न इलाकों का दौरा कर शिकायतों की वास्तविकता का पता लगाने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

राज्य सरकार की ओर से बचाव में उतरे बड़े-बड़े वकील : राज्य सरकार व पुलिस की ओर से हिंसा मामले में बचाव के लिए अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी व कपिल सिब्बल उतरे। एक दिन पहले भी इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य पुलिस का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एनएचआरसी समिति के रिपोर्ट को राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित बताते हुए दावा किया था कि कमेटी के कुछ सदस्यों का जुड़ाव भाजपा से है। वहीं, एनएचआरसी कमेटी की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं में से एक का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने अदालत से मामले की जांच सीबीआइ को सौंपने का अनुरोध किया था।

प्रदर्शन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में की तोड़फोड़

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: भाजपा शासित त्रिपुरा के दौरे पर गत सोमवार को गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हुए कथित हमले के विरोध में मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे बंगाल में प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस एवं उसकी युवा इकाई के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता से लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क पर उतर कर पैदल मार्च निकाला और भाजपा पर हमले का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने जलपाईगुड़ी कार्यालय में तोड़फोड़ की। भाजपा ने इसको सोची समझी साजिश करार दिया है।

कोलकाता, हावड़ा, हुगली, खड़गपुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी व अन्य शहरों में तृणमूल कार्यकर्ता ने भाजपा कार्यालयों के सामने भी विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। वहीं, इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जलपाईगुड़ी में भाजपा कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ का भी आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगा है। भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए राज्य सरकार व तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में लागू कोरोना प्रतिबंधों के बावजूद सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। उन्होंने जलपाईगुड़ी में पार्टी कार्यालय पर हुए हमले को सोची समझी साजिश करार दिया। उल्लेखनीय है कि सोमवार को त्रिपुरा के दौरे पर गए अभिषेक बनर्जी के काफिले को कई बार रोकने की कोशिश की गई। तृणमूल का आरोप है कि अगरतला हवाई अड्डे से जब त्रिपुरेश्वरी मंदिर की ओर अभिषेक का काफिला जा रहा था तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके वाहन पर हमला किया। अभिषेक ने ट्विटर पर अपने काफिले पर हुए हमले का एक वीडियो भी साझा किया था, जिसमें भाजपा के झंडे लिए कुछ लोग गाड़ी पर लाठी से हमला करते नजर आ रहे हैं। हालांकि, इसके बाद बनर्जी ने उदयपुर के त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना की। वहीं, भाजपा ने इस हमले के पीछे हाथ होने से इन्कार किया था।

उत्तर प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में लागू होगा सिटीजन चार्टर

धर्मेश अवस्थी, लखनऊ

- शुरू हुआ 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार-जन सेवाएं हमारे द्वार' अभियान
- सभी को भेजा गया माडल सिटीजन चार्टर, 15 अगस्त तक घोषित करेंगी पंचायतें

उत्तर प्रदेश में गांवों का विकास कराने के साथ ही ग्राम पंचायतें जनसुविधाओं के प्रति भी जवाबदेह भी होंगी। योगी सरकार सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है, इसमें संबंधित सुविधा का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा। शासन ने माडल सिटीजन चार्टर जारी कर दिया है। ग्राम पंचायतों को इसमें कुछ सुविधाओं का चयन करके 15 अगस्त तक लागू करना होगा।

गांवों की सरकार यानी ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन हो चुका है। जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण के बाद ही सरकार ने विकास के लिए धन देने का ऐलान कर दिया। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना और पंचायत सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया भी चल रही है। प्रदेश सरकार अब 'मेरी पंचायत, मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार' अभियान शुरू कर रही है। इसमें गांव की सरकार को आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाने की योजना है। लोगों को यह पता हो कि इस सुविधा का लाभ या समस्या का निस्तारण इतने दिनों में हो जाएगा। यह पहल सिटीजन चार्टर के तहत हो रही है।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने पंचायतीराज विभाग सहित सभी जिलों को आदेश कर दिया है कि वे हर ग्राम पंचायत में सिटीजन चार्टर को लागू कराएं। विभाग ने इसके लिए माडल सिटीजन चार्टर भी तैयार कराया है, जिसमें कई जनसुविधाओं का उल्लेख है। ग्राम पंचायतें अपनी सहूलियत से उसे अपना सकती हैं। यह कार्य हर हाल में 15 अगस्त तक पूरा होना है।

पंचायतें कर सकती संशोधन : शासन ने माडल सिटीजन चार्टर में प्रशासनिक, विकास, पेयजलापूर्ति, स्वच्छता-साफ सफाई, सामुदायिक संपत्ति, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोविड व डिजिटल की करीब 39 सुविधाओं का उल्लेख किया है। पंचायतें इनमें से कुछ या फिर इसके अलावा अन्य सुविधाएं दे सकती हैं।

शरद से मिले लालू, बोले-सांप्रदायिकता के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ेंगे

राज्य ब्यूरो, पटना

सेहत में सुधार होते ही राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। मंगलवार को वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद बोले कि सांप्रदायिकता और गैर-बराबरी के खिलाफ अंतिम दम तक लड़ाई जारी रहेगी। सोमवार को लालू ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी। दिल्ली में मंगलवार को शरद के आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान लालू ने कहा कि वह समाजवादियों को संगठित कर रहे हैं। शरद यादव के संसद में नहीं रहने से देश की बड़ी आबादी का नुकसान हो रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में लोजपा नेता चिराग पासवान और तेजस्वी यादव

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (दाएं) ने मंगलवार को नई दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव से मुलाकात की। प्रेट्र

के एक मंच पर आने की संभावना से इन्कार नहीं किया।

चिराग को तो नेता बना दिया : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मैटेरियल बताने पर लालू की टिप्पणी थी कि इसके बारे में नरेंद्र मोदी सोचें। भाजपा ने कह दिया है कि पीएम की वैकेंसी नहीं है। लालू ने चिराग पर टिप्पणी की, उसे नेता बना दिया गया। उसके साथ जो हो रहा, लोग साथ दे रहे हैं।

खालिस्तान समर्थक दे रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धमकी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कृषि कानून विरोधी आंदोलन की आड़ लेकर खालिस्तान समर्थक स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। इस बार वह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने देने की धमकी दे रहे हैं। मंगलवार सुबह से ही दिल्ली, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के जिलों में लोगों के मोबाइल फोन नंबर पर सीएम मनोहर लाल को धमकी की रिकार्डेड फोन काल आ रही हैं। आधे घंटे के अंतराल में ये धमकी भरी फोन काल एक फोन पर दो बार आई हैं। धमकी देने वाले की आवाज तो एक ही तरह की है, मगर ये फोन काल अलग-अलग नंबरों से आ रहे हैं। लोग इन फोन काल को सुनकर हैरान हैं।

हरियाणा की सरकारी एजेंसियों ने धमकी देने वाले की आवाज के आधार पर उसकी पहचान खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के रूप में की है। यह पन्नू वही है, जिसका एक आडियो तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों के हक में जारी हुआ था। अंग्रेजी और पंजाबी में धमकी देने वाला खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू बीच में भिंडरावाला की आवाज भी सुनवाता है। इसमें भिंडरावाला को शहीद कहकर पुकारा जा रहा है। हरियाणा सरकार के आदेश पर एजेंसियां इस पूरे मामले की विस्तृत जांच में जुट गई हैं।

इन विदेशी नंबरों से आ रहे हैं धमकी भरी फोन

+17167558882	+17053007509
+441978804118	+441227949043
+441277283866	

15 अगस्त को लेकर धमकी भरे काल की मुझे जानकारी है। मेरे पास सीधे ऐसा कोई काल नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हमारी व्यवस्था चाक-चौबंद है। एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। पन्नू का विषय बहुत पुराना है। हम ऐसे किसी विषय को पनपने नहीं देंगे।

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

जयराम, आर्लेकर, नड्डा को जेड प्लस व अनुराग को जेड सुरक्षा

राज्य ब्यूरो, शिमला : खालिस्तान समर्थक की धमकी के बाद हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जेड प्लस, जबकि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। इस संबंध में प्रदेश पुलिस ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इन सबकी सुरक्षा को दोबारा से आकलन कर पूरे देश में लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रदेश पुलिस महानिदेशक ने पत्र लिखा है।

विधायक आशा कुमारी को भी आई फोन काल : खालिस्तान समर्थक ने अब डलहौजी की विधायक आशा कुमारी को भी धमकी भरा फोन किया है। विधायक ने कहा कि उन्हें सोमवार दोपहर बाद 3:50 पर यूके के नंबर से धमकी भरा काल आया। इसमें उन्हें 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज न फहराने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराने से हमें कोई नहीं रोक सकता है।

अदाणी लाजिस्टिक्स पार्क बंद, करोड़ों का माल फंसा

राजीव शर्मा, लुधियाना

तीन कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं। किला रायकोट में अदाणी ग्रुप का लाजिस्टिक्स पार्क बंद होना इसका ताजा उदाहरण है। इसके बंद होने से 400 से ज्यादा युवा बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि सरकार को अब तक 700 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। उद्योगों के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी 33 फीसद तक बढ़ गया है। दूसरी तरफ आठ माह से बंद इस पार्क के कारण आयातकों का करोड़ों रुपये का माल अंदर फंस गया है। किसान गेट पर धरना लगाकर बैठे है। कई बार अपील के बाद भी वे हटने को तैयार नहीं हैं।

ड्राई पोर्ट प्रबंधन का कहना है कि कम से कम सौ कंटेनर आयात का माल अंदर अटका है। आयातकों ने कस्टम क्लीयरेंस के अलावा सरकार को ड्यूटी भी जमा करवा दी है। विदेश से सामान मंगवाने के लिए उन्होंने कर्ज लेकर एडवांस पेमेंट भी कर दी है। अब लाखों रुपये का ब्याज पड़ रहा है।

गांव किला रायपुर में स्थित अदाणी लाजिस्टिक पार्क, जो किसानों के हड़ताल के कारण जनवरी माह से बंद है। फाइल फोटो

ट्रैक्टर पाट्र्स निर्माता बुल फोर्ज के संचालक गगनदीप सिंह आनंद ने यूक्रेन से फोर्जिंग मशीन मंगवाई थी। इससे ट्रैक्टर पाट्र्स बनते हैं। इसकी कीमत करीब 20 लाख है। यह पिछले साल दिसंबर में पहुंच गई थी, लेकिन अब तक डिलीवरी नहीं हुई। उन्हें अब तक पांच से सात लाख रुपये का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि मशीन भी काफी खराब हो गई है। सारी पेमेंट एडवांस में पिछले साल सितंबर में ही कर दी थी। इसके लिए बैंक से कर्ज लिया था। तब से ब्याज भी देना पड़ रहा है। किसानों को कई बार मजबूरी भी बताई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

वहीं, एमके इंपेक्स के संचालक जसकरण सिंह ने एल्यूमीनियम स्क्रैप के दो कंटेनर का आयात कनाडा से किया था। उनका माल 11 दिसंबर को पोर्ट पर पहुंच गया था। इसकी कीमत करीब 70 लाख रुपये है। एडवांस पेमेंट पिछले साल सितंबर में की थी। हर माह 70 हजार रुपये का ब्याज पड़ रहा है। माल खुले में होने के कारण खराब हो रहा है।

आयातक युवराज ट्रेडर्स के संचालक पंकज कुमार का कहना है कि उन्होंने अमेरिका से करीब 25 लाख रुपये की सीएनसी मशीन मंगवाई थी। यह दिसंबर से अंदर फंसी है। किसानों की मिन्नतें भी की, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया। मशीन अंदर पड़ी-पड़ी खराब हो रही है। अब तक छह-सात लाख रुपये का नुकसान हो चुका है।

हालात सुधरने की उम्मीद नहीं : पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए सियासी पार्टियां इस मामले को हल करने के बजाय और तूल दे रही हैं।

पंजाब का नुकसान होता देख बुद्धिजीवी चुप क्यों

पंजाब के जाने-माने कृषि अर्थशास्त्री व पद्म भूषण से सम्मानति डा. सरदारा सिंह जौहल ने वर्तमान हालात पर चिंता जताई है। 94 वर्षीय डा. जौहल ने ट्विटर पर लिखा, 'जो नेता, अभिनेता, आइएएस, आइपीएस, बड़े-बड़े तथाकथित बुद्धिजीवी या फिर लेखक एड़ियां उठा-उठा कर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उन्हें बहुत-बहुत बधाई...। पंजाब का नुकसान करवाने में उन्होंने खूब बढ़-चढ़कर योगदान दिया है। पंजाब का नुकसान होता देख अब सब चुप क्यों?' उन्होंने आगे लिखा, 'यह तो ट्रेलर ही है। आगे-आगे देखिए होता है क्या...। खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर... कटेगा खरबूजा ही...!' गौरतलब है कि डा. जौहल ने इससे पहले भी कहा था कि कृषि कानून किसानों के लिए नुकसानदेह नहीं हैं, लेकिन इन्हें लागू करने में केंद्र सरकार ने हड़बड़ी कर दी। उनके इस बयान पर उन्हें फेसबुक पर जान से मारने की धमकी तक दी गई थी।

न्यूज गैलरी

येदियुरप्पा और उनके बेटे समेत कई लोगों को नोटिस

बेंगलुरु : कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, उनके बेटे, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, उनके परिवार, पूर्व मंत्री एसटी सोमशेखर और एक आइएएस अफसर को नोटिस जारी किया है। जज जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव ने एक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम की शिकायत पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। (प्रेट्र)

देवस्थानम बोर्ड के विरोध में अनशन करेंगे तीर्थ पुरोहित

रुद्रप्रयाग : केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र उत्तराखंड चारधाम देवास्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो वे इसी सप्ताह से बेमियादी अनशन शुरू कर देंगे। तीर्थ पुरोहित पिछले लंबे समय से केदारनाथ मंदिर परिसर में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। (ससं)

राज्यों को 14 साल बाद कैदियों को छोड़ने का अधिकार

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि जिस अपराध में अधिकतम फांसी की सजा तक का प्रविधान हो उसमें आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) के तहत राज्य सरकार को 14 साल की कैद के बाद किसी अपराधी को छोड़ने का अधिकार है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर कोई अपराधी वास्तविक सजा से 14 साल या उससे ज्यादा समय तक जेल में नहीं रहा है तो संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सलाह पर उसकी सजा को माफ कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं या सजा को निलंबित कर सकते हैं। सीआरपीसी के तहत लागू प्रतिबंध भी इसके रास्ते में नहीं आएंगे। (प्रेट्र)

ईवीएम पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली : आगामी चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल पर रोक लगाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के संबंध में निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। बिना तथ्य एवं शोध के याचिका दाखिल करने पर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता एडवोकेट सीआर सुकिन पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीठ ने कहा कि यह याचिका सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दायर की गई प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता ने ईवीएम पर सवाल तो उठाए, लेकिन उनके पास ईवीएम को लेकर कोई खास जानकारी या शोध मौजूद नहीं है। पीठ ने सुकिन को शोध व तथ्यों के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी। (जासं)

त्रिपुरा में उग्रवादियों का घात लगाकर हमला, दो बीएसएफ जवान शहीद

मुठभेड़ ▶ बांग्लादेश से लगी सीमा पर एनएलएफटी उग्रवादियों का हमला

शहीद जवानों में एक सब इंस्पेक्टर और दूसरा कांस्टेबल

त्रिपुरा के ढलाई जिले में मंगलवार को उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए बीएसएफ के कांस्टेबल राजकुमार और सब इंस्पेक्टर भारु सिंह। फाइल फोटो, एएनआइ

अगरतला, प्रेट्र : त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एनएलएफटी उग्रवादियों के घात लगाकर किए गए एक हमले में एक सब इंस्पेक्टर समेत बीएसएफ के दो जवान शहीद हो गए हैं। उग्रवादियों ने मंगलवार को यह जानलेवा हमला तब किया जब बीएसएफ के जवान इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे।

बीएसएफ के प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि इस मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर भारु सिंह और कांस्टेबल राज कुमार का गंभीर रूप से घायल होने के बाद निधन हो गया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर मिले खून के धब्बों से साफ है कि उग्रवादियों को भी गोली लगी है। दोनों शहीदों ने बहुत ही बहादुरी से उग्रवादियों से मुकाबला किया और लड़ते-लड़ते शहीद हो गए। उन्होंने बताया कि उग्रवादियों की धर-पकड़ के लिए इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। उग्रवादी शहीद जवानों के हथियार लेकर भाग गए हैं।

त्रिपुरा के ढलाई जिले में सुबह 6.30 बजे करीब सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों पर उग्रवादियों ने यह हमला किया। उग्रवादियों के हमले और सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई ढलाई के पास स्थित पानीसागर सेक्टर के चावमानू पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आनेवाली आरसी नाथ बार्डर पोस्ट के नजदीक हुई है। राज्य की राजधानी अगरतला से ढलाई जिला करीब 94 किलोमीटर दूर है। इसकी सीमाएं उत्तरी और दक्षिणी छोर से बांग्लादेश से घिरी हुई हैं। भारत-बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा में त्रिपुरा की सीमा केवल 856 किलोमीटर ही है।

बांडीपोरा में लश्कर का पाकिस्तानी आतंकी बाबर ढेर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा जिले के चंदाजी इलाके में सुरक्षाबलों ने मंगलवार को बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी बाबर अली को मार गिराया। बाबर की गिनती लश्कर के टाप के आतंकियों में होती थी। यह आतंकी उसी गुट का था, जिसके आतंकी हफ्ते भर पहले बांडीपोरा में ही शोकबाबा के जंगल हुई मुठभेड़ में मारे गए थे। पुलिस को चंदाजी इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद पुलिस ने सीआरपीएफ और सेना की 26 असम राइफल्स के जवानों के साथ पूरे क्षेत्र को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। खुद को घिरा देख आतंकियों ने फरार होने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसके साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षाबलों ने आतंकी को आत्मसमर्पण करने का मौका भी दिया, लेकिन वह नहीं माना और फायरिंग करता रहा।

अभ्यास के दौरान संतुलन बिगड़ने से झील में गिरा हेलीकाप्टर

जागरण टीम, पठानकोट

सेना का ध्रुव एएलएच मार्क-4 हेलीकाप्टर मंगलवार सुबह 10:50 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हेलीकाप्टर नियमित अभ्यास के दौरान संतुलन बिगड़ने के बाद पठानकोट से सटे रणजीत सागर बांध (आरएसडी) की झील में बसोहली (जम्मू-कश्मीर) के पुरथू के नजदीक गिर गया। इसमें दो पायलट सवार थे, जिनकी पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल एएस भट्ट व कैप्टन जयंत जोशी के रूप में हुई है। हालांकि, सेना ने कुल कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी नहीं दी है।

हेलीकाप्टर ने पठानकोट स्थित मामून कैंट से मंगलवार सुबह 8:30 बजे उड़ान भरी थी। अभ्यास के दौरान सुबह 10:50 बजे यह झील के लेवल से काफी नजदीक आ गया था। इस दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से यह झील में गिर गया। इसकी जानकारी मिलते ही जिला पुलिस, सेना और एनडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। आरएसडी प्रबंधन की मौजूदगी में राहत व बचाव कार्य दल भी मौके पर पहुंच कर झील से हेलीकाप्टर का मलबा निकालने में जुट गया है। अधिकांश मलबे को देर शाम तक निकाल लिया गया था, लेकिन खबर लिखे जाने तक दोनों पायलटों की तलाश जारी थी। सेना, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम रेसक्यू आपरेशन कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों पायलटों के जूते और हेलमेट रेस्क्यू आपरेशन के दौरान मिले हैं। कयास लगाया जा रहा है कि हेलीकाप्टर क्रैश होने से पहले दोनों पायलट कूद गए होंगे और वह झील की गहराई में चले गए हैं।

रणजीत सागर बांध की झील में सेना का हेलीकाप्टर गिरने के बाद तैरता मलबा। जागरण

झील के जिस क्षेत्र में हादसा हुआ वह जम्मू-कश्मीर के दायरे में आता है, इसलिए वहां के प्रशासन को भी सूचित कर दिया गया है। क्रैश होने के बाद हेलीकाप्टर से निकला ईंधन रेस्क्यू आपरेशन में बाधा बन रहा है। एनडीआरएफ के अधिकारियों का कहना है कि ईंधन पानी के ऊपर तैरने लगा है, जिससे गोताखोरों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। इसे देखते हुए दिल्ली से गहराई में जाने वाले गोताखोरों को बुलाया गया है।

'कुंद्रा पर समाज की सेहत के लिए हानिकारक अपराध का आरोप'

मुंबई, प्रेट्र : एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा है कि कारोबारी राज कुंद्रा व सहयोगी रयान थोर्पे को पिछले महीने जिस अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, वह समाज की सेहत के लिए हानिकारक है और समाज के हित में ऐसे मामलों की अनदेखी नहीं की जा सकती। पोर्न वीडियो बनाने और एप के जरिये प्रसारित करने के मामले में दाखिल जमानत याचिकाओं को 28 जुलाई को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले के आदेश का विस्तृत ब्योरा मंगलवार को उपलब्ध हुआ है। कुंद्रा व थोर्पे को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। आरोपितों ने बांबे हाई कोर्ट में भी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी गिरफ्तारी का कारण बता चुके हैं, जो जरूरी था। जज ने कहा, '20 जुलाई को रिमांड पर सुनवाई के दौरान अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि आरोपित की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप की गई है। जांच अधिकारी पहले ही कारण बता चुके हैं। ऐसी अवस्था में यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपित जमानत का हकदार है।' जांच अधिकारी ने कहा है कि कुंद्रा का रिश्तेदार और आरोपित प्रदीप बख्शी फरार है। पुलिस ने काफी डाटा बरामद किए हैं। आरोपितों ने कुछ डाटा डिलीट भी किए हैं और जमानत पर छोड़ा गया तो और साक्ष्यों को नष्ट कर सकते हैं।

अदालत ने ममता कुलकर्णी के बैंक खाते डीफ्रीज करने की अपील ठुकराई

ठाणे, प्रेट्र : एक विशेष अदालत ने दो हजार करोड़ रुपये के ड्रग केस मामले में बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के बैंक खातों को डीफ्रीज करने से और फ्लैटों की सील हटाने से इन्कार कर दिया है। कुलकर्णी की तीन एफडी समेत छह बैंक खाते फ्रीज और मुंबई में दो फ्लैट भी सील किए गए हैं।

'सीबीआइ जल्द शुरू करे हत्या की जांच'

राज्य ब्यूरो, रांची

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले की सीबीआइ जांच जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। सीबीआइ की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार की जांच की अनुशंसा का पत्र मिला है। चार अगस्त को सीबीआइ जांच की अधिसूचना जारी कर सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआइ को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। अदालत ने सरकार को केस के सभी दस्तावेज और अन्य लाजिस्टिक सपोर्ट सीबीआइ देने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले की जांच सीबीआइ को करने को कहा था तो महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि इससे पुलिस के अधिकारियों का मनोबल प्रभावित होगा। ऐसे में अब क्या हुआ कि सरकार अपनी ही बातों से पलट गई और सीबीआइ जांच की अनुशंसा की है। महाधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि इस मामले में की जांच सीबीआइ को इसलिए सौंपी जी रही है कि इसके तार दूसरे राज्य से जुड़े हो सकते हैं ऐसे में सीबीआइ ही इस मामले की जांच के लिए उपयुक्त एजेंसी है। इससे पहले एसआइटी की ओर से जांच की प्रगति रिपोर्ट कोर्ट को पेश की गई। रिपोर्ट देख कर अदालत ने काफी असंतुष्टि जाहिर की। अदालत ने कहा कि घटना सुबह 5.08 बजे हुई तो प्राथमिकी दर्ज करने में विलंब क्यों किया गया। क्यों प्राथमिकी 12:45 बजे दर्ज की गई। जबकि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट है कि जज को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। क्या पुलिस सिर्फ फर्द बयान के आधार पर ही प्राथमिकी दर्ज करती है। क्या पुलिस स्वतः प्राथमिकी दर्ज नहीं करती। आखिर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में छह घंटे क्यों लग गए। पुलिस को तो हमेशा अपनी आंख और कान खुले रखने चाहिए। सबूत कभी चल कर नहीं आता है। अदालत ने कहा कि इसका लाभ बचाव पक्ष को निचली अदालत में नहीं मिलेगा। जब वह इन बातों को अदालत में उठा कर अभियोजन को परेशानी में डाल देगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि जज के सिर की बाईं तरफ गंभीर चोट है। ऐसे में जांच एजेंसी का काम है कि वो इसका पर्दाफाश करे।

अदालतों और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ेगी

सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी को अदालतों की सुरक्षा सख्त करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस घटना के बाद न्यायिक अधिकारी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी न्यायिक पदाधिकारी पर हमला हुआ है इसको देखते हुए तत्काल धनबाद के न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा सख्त करनी चाहिए। उनके आवासीय क्षेत्र में पुलिस की तैनाती की जाए। हाई कोर्ट समेत सभी न्यायालयों में कुशल प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। इस पर डीजीपी नीरज सिन्हा ने तत्काल अमल करने का आश्वासन दिया। बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या मामले में धनबाद के प्रधान जिला जज ने हाई कोर्ट को पत्र लिखा था। इस पत्र को हाई कोर्ट जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई कर रहा है।

हनी सिंह पर पत्नी ने लगाया मारपीट और हिंसा का गंभीर आरोप

जागरण संवददाता, नई दिल्ली : पंजाबी गायक और अभिनेता हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत 10 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। शालिनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हनी सिंह व उनके स्वजन ने उन पर ऐसा मानसिक व भावनात्मक अत्याचार किया कि वह खुद को जानवर के रूप में मानने लगी थीं। तलवार ने हनी सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए याचिका में कहा कि वह अक्सर कई महिलाओं के साथ अनौपचारिक यौन संबंध रखते थे और उनकी शादी की अंगूठी नहीं पहनते थे। इतना ही नहीं शादी की तस्वीरें आनलाइन अपलोड करने पर हनी उन्हें बेरहमी से मारते थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि सिंह ने पिछले कुछ सालों में उसे कई बार पीटा और वह लगातार डर के साए में जी रही है।

यात्रा के सालभर

गत वर्ष पांच अगस्त को प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन के साथ किया था उत्कर्ष यात्रा का सूत्रपात, भव्य मंदिर के साथ दिव्य अयोध्या की परिकल्पना ले रही आकार

...सज्जित हो रहा रामनगरी का आत्माभिमान

रघुवरशरण, अयोध्या

राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के साथ रामनगरी का आत्माभिमान सज्जित हो रहा है। इस उत्कर्ष यात्रा का सूत्रपात गत वर्ष पांच अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखने के साथ किया था। गुरुवार को इस उत्कर्ष यात्रा का एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस बीच न केवल मंदिर निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, बल्कि भव्य राम मंदिर के साथ दिव्य अयोध्या की परिकल्पना भी आकार लेने लगी है।

यह बदलाव उन लोगों के लिए स्वर्णिम सौगात से भी बढ़ कर है, जिन्होंने श्रीराम और उनकी नगरी के अपमान-अवमान के एक-एक दिन एक-एक युग की तरह काटे हैं और जिन्हें करीब पांच सदी पुराने राम मंदिर विवाद के रूप में पीढ़ियों से व्यथा की विरासत मिलती रही। 1947 में देश की आजादी के साथ राम जन्मभूमि की आजादी की भी आकांक्षा ने नई करवट ली, किंतु यह आकांक्षा कोर्ट-कचहरी में उलझ कर घुटती रही। अंततः न्यायालय से न्याय पाने का चिर अपेक्षित सूत्र सफल हुआ। रामभक्तों ने इसे श्रीराम की ही कृपा-कृति के रूप में शिरोधार्य किया और दिव्य मंदिर की आकांक्षा फलीभूत करने के लिए रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सहित केंद्र एवं उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकारें आगे आईं।

विहिप ने जरूर मंदिर का मानचित्र पहले से तैयार कर रखा था, किंतु निर्माण शुरू होने की बेला तक यह मानचित्र छोटा प्रतीत होने लगा और आज जिस मंदिर का निर्माण हो रहा है, वह उस मानक से करीब पौने दो गुना बड़ा है तथा उसके शिखर की ऊंचाई भी पूर्व मानचित्र से 33 फीट अधिक है। भूमि पूजन के ही वक्त प्रधानमंत्री के उद्बोधन से यह भी साफ हो गया कि यह मंदिर वस्तुतः राष्ट्र मंदिर का प्रतिनिधित्व करने वाला है।

महान विरासत से प्रेरित होने और उसे सहेजने का उत्सवबोध : जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य के अनुसार मंदिर का निर्माण दुनिया के सामने अपूर्व मिसाल है और यह भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। शीर्ष पीठ रामवल्लभाकुंज के अधिकारी राजकुमारदास कहते हैं, श्रीराम और राम मंदिर के साथ रामलला के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी किसी महान विरासत से कम नहीं है और हम इस विरासत को पूरी निष्ठा से सहेज भी रहे हैं। न्यायालय में राम मंदिर की पैरोकारी से जुड़े रहे नाका हनुमानगढ़ी के महंत रामदास कहते हैं, इसी निर्णय के चलते गत वर्ष प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी और तभी से भव्य मंदिर के साथ दिव्य अयोध्या का स्वप्न साकार हो रहा है।

बढ़ रहा श्रद्धा का समर्पण

मंदिर निर्माण के लिए सतत श्रद्धा का समर्पण भी बढ़ रहा है। निधि समर्पण अभियान के अतिरिक्त बैंकों के खाते में रोज औसतन 15 लाख रुपये आ रहे हैं। यह पूरी रकम भक्तजन ई-बैंकिंग के माध्यम से ही ट्रस्ट के खातों में भेज रहे हैं।

मप्र में सात जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में

जागरण टीम, नई दिल्ली : अतिवृष्टि और बाढ़ से मध्य प्रदेश के शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड, गुना और रीवा में लगभग 1171 गांव प्रभावित हुए हैं। करीब 200 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। बचाव दल मंगलवार रात तक लगभग 1600 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा चुके हैं, मगर कई लोगों की जान भी चली गई है। सेना बुला ली गई है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी हालात की जानकारी दी है। उधर, राजस्थान में बारिश से हुए हादसों में छह की मौत हो गई है। बंगाल के छह जिलों में 16 की जान चली गई है। करीब ढाई लाख लोग बेघर हो गए हैं।

मप्र के भिंड-मुरैना जिलों में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव डूब गए हैं। मुरैना में चंबल खतरे के निशान से दो मीटर ऊपर बह रही है। शिवपुरी में दो हजार से ज्यादा लोग अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं।

पोर्टल से डाउनलोड करें प्रमाणपत्र

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि छात्र अपने सभी संबंधित सर्टिफिकेट मंजूषा पोर्टल के जरिये डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, डिजिलाकर एप और पोर्टल पर भी सभी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा है। इस बार विदेशी छात्रों को भी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा दी जा रही है। इस साल भी मेरिट सूची जारी नहीं हुई है।

इस फार्मूला से जारी हुआ परिणाम : कोरोना महामारी के कारण इस साल परीक्षाएं रद हो गई थीं। बोर्ड ने मूल्यांकन के लिए छात्रों की साल भर ली गई परीक्षाओं के आधार पर परिणाम जारी किया। 100 अंकों की परीक्षा के लिए इस बार स्कूलों ने ही छात्रों का 80 अंकों के लिए मूल्यांकन किया। वहीं, 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के जोड़े गए। बोर्ड ने इन 80 अंकों के लिए यूनिट टेस्ट के 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के 30 अंक और प्री-बोर्ड परीक्षा के 40 अंक के आधार पर परिणाम जारी करने को कहा था।

सीबीएसई 10वीं का परिणाम

कुल पंजीकृत छात्र	21,50,608
पास हुए	20,76,997
पास फीसद	99.04
नियमित छात्र	21,13,767
प्राइवेट और पत्राचार वाले छात्र	36,841
इतने छात्रों का परिणाम हुआ जारी	20,97,128
परिणाम अभी जारी होना है	16,639

देशभर के सरकारी व निजी स्कूलों का ये रहा परिणाम

संस्थान	पास फीसद
जवाहर नवोदय विद्यालय	99.99
केंद्रीय विद्यालय	100
केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	100
सरकारी	96.03
सरकारी सहायता प्राप्त	95.88
निजी	99.57
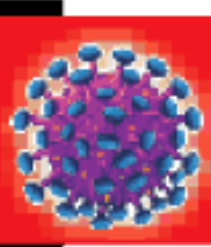
अब हर माह होगा कोविशील्ड की 12 करोड़ डोज का उत्पादन

संसद में सरकार ▸ दिसंबर तक कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता भी हो जाएगी 5.8 करोड़ डोज

रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता भी अप्रैल के 38.8 लाख से बढ़कर जून में 122.49 लाख शीशी प्रति माह हुई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि कोरोना रोधी वैक्सीन कोविश्लीड और कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिसंबर तक कोविशील्ड की मासिक उत्पादन क्षमता बढ़कर 12 करोड़ डोज और कोवैक्सीन की 5.8 करोड़ डोज हो जाएगी। इसके अलावा रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता भी अप्रैल माह के मध्य तक 38.8 लाख शीशी प्रति माह थी जो जून से बढ़ कर 122.49 लाख शीशी प्रति माह हो गई।

राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक लिखित जवाब में बताया कि उत्पादकों की तरफ से बताया गया है कि कोविशील्ड की उत्पादन क्षमता मौजूदा 11 करोड़ डोज प्रतिमाह से बढ़कर 12 करोड़ डोज से अधिक और कोवैक्सीन की 2.5 करोड़ डोज से बढ़कर 5.8 करोड़ डोज प्रतिमाह होने का अनुमान है।

उन्होंने कहा कि देश में अब तक टीकों की 47 करोड़ डोज दी गई हैं और केंद्र सरकार पूरे देश के जल्द से जल्द टीकाकरण का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि चार और भारतीय कंपनियों के अक्टूबर-नवंबर तक कोविड रोधी टीकों का उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है जिससे अभियान में तेजी आएगी। निजी अस्पतालों द्वारा उपयोग नहीं की गई सात से नौ फीसद डोज का भी सरकारी टीकाकरण केंद्रों में उपयोग हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में टीकाकरण के महाअभियान के दौरान मंगलवार को प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज में वैक्सीन लगवाती महिला। एएनआइ

62.54 फीसद रजिस्ट्रेशन आन-साइट

मांडविया ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए 62.54 फीसद रजिस्ट्रेशन आन-साइट किए गए और मौके पर जाकर 77 फीसद टीके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बिना फोटो पहचान पत्र वाले 4.35 लाख से ज्यादा लोगों को भी विशेष अभियान चलाकर अभी तक टीके लगाए गए हैं।

रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं

मांडविया ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह भी बताया कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की कमी नहीं है। दूसरी लहर के दौरान अप्रैल और मई 2021 में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग अचानक बढ़ गई और बाजार में इसकी किल्लत हो गई। रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंसधारी निर्माताओं के 40 नए उत्पादन स्थलों को शीघ्रता से मंजूरी दी गई। इस समय देश में हर महीने रेमडेसिविर की उत्पादन क्षमता बढ़कर 122.49 लाख शीशी हो गई।

कोरोना संबंधी शोध के लिए 1,600 करोड़ रुपये आवंटित

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन को बताया कि कोरोना संबंधी शोध और उत्पादन विकास के लिए 1,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और उसकी सहायक कंपनी बायोटेक्नोलाजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बीआइआरएसी) को 1,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

केरल में सीरो सर्वे कराने का सुझाव : केंद्रीय टीम

जेएनएन, नई दिल्ली

▸ बीते 24 घंटे में राज्य में 23 हजार से ज्यादा नए केस मिले, केरल सरकार से टीकाकरण में तेजी लाने को कहा

कोरोना महामारी की चपेट से केरल उबर नहीं पा रहा है। राज्य में एक बार फिर 20 हजार से ज्यादा मामले पाए गए हैं। सोमवार को राज्य में 13 हजार केस मिलने पर कुछ राहत की उम्मीद जगी थी, लेकिन मंगलवार को यह टूट गई। 148 लोगों की जान भी गई है। हालात को काबू में करने के लिए केंद्र की तरफ से भेजे गई विशेषज्ञों की टीम ने राज्य सरकार से टीकाकरण में तेजी लाने और जल्द से जल्द सीरो सर्वे कराने को कहा है।

केरल सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि मंगलवार को राज्य में 23,676 नए मरीज पाए गए और 15,626 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,73,221 हो गई है। राज्य में मंगलवार को संक्रमण दर 11.87 फीसद रही। सबसे ज्यादा मलप्पुरम में 4,276 केस मिले हैं।

राज्य में हालात को नियंत्रित करने में स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए केंद्र ने छह सदस्यीय टीम भेजी थी। इस टीम ने उन छह जिलों का दौरा किया, जहां सबसे ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। टीम ने राज्य सरकार से सीरो सर्वे कराने को कहा, जिससे यह पता चल सकेगा कि अब तक कितने फीसद लोग संक्रमित हो चुके हैं। इससे संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सटीक रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

इस बीच, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने राज्य में बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई है। उसने राज्य के आधे से ज्यादा आबादी के संक्रमण की जद में आने की आशंका भी जताई है।

राज्यों के पास अभी 2.75 करोड़ डोज उपलब्ध : इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अभी कोरोना रोधी वैक्सीन की 2.75 करोड़ डोज उपलब्ध हैं।

देश में कोरोना की स्थिति

24 घंटे में नए मामले	30,549
कुल सक्रिय मामले	4,04,958
24 घंटे में टीकाकरण	60.94 लाख
कुल टीकाकरण	47.85 करोड़

मंगलवार सुबह बजे तक कोरोना की स्थिति

नए मामले	30,549
कुल मामले	3,17,26,507
सक्रिय मामले	4,04,958
मौतें (24 घंटे में)	422
कुल मौतें	4,25,195
ठीक होने की दर	97.38 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	1.85 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.39 फीसद
जांचें (सोमवार)	16,49,295
कुल जांचें (सोमवार)	47,12,94,789

बचाव के लिए टेस्ट और ट्रैकिंग। फाइल फोटो

सोमवार शाम सात बजे तक किस राज्य में कितने टीके

उत्तर प्रदेश	21.95 लाख
गुजरात	2.81 लाख
राजस्थान	2.57 लाख
महाराष्ट्र	2.14 लाख
हरियाणा	1.40 लाख
दिल्ली	0.94 लाख
बिहार	0.70 लाख
उत्तराखंड	0.68 लाख
झारखंड	0.57 लाख
हिमाचल	0.52 लाख
पंजाब	0.52 लाख

(कोविन प्लेटफार्म के आंकड़े)

डीएम को सौंपी कुंभ में कोरोना जांच फर्जीवाड़े की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, हरिद्वार

हरिद्वार कुंभ-2021 के दौरान कोरोना जांच में फर्जीवाड़ा के मामले में शासन के आदेश पर चल रही जांच पूरी हो गई है। सीडीओ सौरभ गहरवार ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी हरिद्वार स्वास्थ्य महानिदेशालय के माध्यम से जांच रिपोर्ट शासन को भेजेंगे।

हरिद्वार कुंभ में कोरोना जांच के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा के मामला पंजाब के फरीदकोट निवासी विपिन मित्तल की आइसीएमआर को की गई शिकायत के बाद सामने आया था। आइसीएमआर के निर्देश पर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी के आदेश पर शासन स्तर से हुई प्राथमिक जांच में शिकायत की पुष्टि हुई थी। इसके बाद स्वास्थ्य सचिव के आदेश पर तत्कालीन जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने सीडीओ हरिद्वार सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच उन्हें सौंप दी थी। जांच समिति ने शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर दिल्ली की मैक्स कारपोरेट सर्विसेज, दिल्ली की लाल चंदानी लैब और हरियाणा हिसार की नलवा लैब के खिलाफ शहर कोतवाली में सीएमओ हरिद्वार के माध्यम से आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था। जिसे बाद में एसआइटी का गठन कर उसे सौंप दिया गया। जांच में एक लाख दस हजार मोबाइल नंबर और आधार नंबर के सत्यापन में करीब दो माह का समय लग गया। पूर्व जिलाधिकारी सी. रविशंकर का कहना है कि मैक्स कारपोरेट सर्विसेज, दिल्ली की लाल चंदानी लैब और हिसार की नलवा लैब और कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग की मामले की संलिप्तता को लेकर सामने आए तथ्यों की पुष्टि हुई है।

आत्महत्या व कोरोना के संबंधों पर अध्ययन नहीं

नई दिल्ली, एएनआइ : सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि देश में आत्महत्या और कोरोना महामारी के बीच संबंधों को लेकर उसने कोई अध्ययन नहीं कराया है।

लोकसभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) आत्महत्याओं पर सूचना संकलित करती है और अपनी रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया (एडीएसआइ) में उसे प्रकाशित करती है। अभी यह रिपोर्ट 2019 तक के लिए ही उपलब्ध है।

लोकसभा में यह सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है या अध्ययन कराने का प्रस्ताव है कि कोरोना महामारी के सामने आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों और देश अन्य भागों में आत्महत्या के बढ़े मामलों की वजह क्या हैं।

राय ने लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने आत्महत्या पर कोरोना के दुष्प्रभावों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया है। हालांकि, यह महसूस करते हुए कि लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोरोना का असर पड़ सकता है, सरकार ने महामारी के दौरान मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए कई पहल की है।

उन्होंने आगे कहा कि इसमें मनोसामाजिक मदद मुहैया कराने के लिए चौबीसों घंटे और सातों दिन काम करने वाली हेल्पलाइन की सुविधा शामिल है। इसमें मानसिक रोग के विशेषज्ञ कोरोना से प्रभावित सभी लोगों को अलग-अलग वर्ग समूह के हिसाब से सलाह देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के प्रबंधन पर भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

जवाब देने के लिए भाजपा सांसदों को बांटी गई पुस्तिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार के कोविड-19 प्रबंधन के पक्ष और विपक्ष में देश में जारी चर्चा के बीच भाजपा ने मंगलवार को अपने सांसदों के बीच एक पुस्तिका बांटी है। इसमें महामारी को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और टीकाकरण अभियान को लेकर उन्हें विभिन्न जानकारियों से लैस करने की कोशिश की गई है ताकि वह आलोचकों को सटीक जवाब दे सकें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका में दावा किया गया है कि कोरोना महामारी से मुकाबले के प्रयासों के लिए सिर्फ केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसका श्रेय 'टीम इंडिया' को जाता है जिसने एक सरकार और समाज के रूप में काम किया। ज्ञात हो कि विपक्षी दल कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर मोदी सरकार और भाजपा शासित राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश की आलोचना कर रहे हैं। मंत्रालय की पुस्तिका में बताया गया है कि भारत ने अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक लोगों को टीकों की खुराक दी है और इस संबंध में पारदर्शी आंकड़े सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं।

यूपी में बेसहारा महिलाओं को हर महीने मिलेंगे दो हजार रुपये

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

मदद

▸ कोरोना काल में बेसहारा हुई महिलाओं का भी सहारा बनेगी योगी सरकार

▸ महिला कल्याण विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, जल्द मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी

कोरोना व अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों का सहारा बनने के बाद योगी सरकार अब बेसहारा महिलाओं का भी सहारा बनने जा रही है। कोरोना काल में बेसहारा हुई महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। शीघ्र ही इसे कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस योजना के तहत गरीब बेसहारा महिलाओं को सरकार दो हजार रुपये प्रति माह प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कोरोना संक्रमण से निराश्रित हुई महिलाओं के लिए भी एक अलग योजना लाने की घोषणा की थी। उन्होंने महिला कल्याण विभाग से ऐसी महिलाओं की सूची बनाने के निर्देश दिए थे जो मार्च, 2020 के बाद निराश्रित हुई हैं। इन्हें योगी सरकार अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ देगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद महिला कल्याण विभाग ने इस नई योजना का खाका खींच लिया है। इस योजना में निराश्रित महिलाओं को दो हजार रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। साथ ही इन्हें राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। यदि किसी बुजुर्ग महिला के पास रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो सरकार इसकी भी व्यवस्था कराएगी। इससे बड़े स्तर पर राहत मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय फलक

लद्दाख की फिजा से लुप्त हो गया भेदभाव का संक्रमण

विवेक सिंह, जम्मू

अनुच्छेद-370 की बेड़ियों से आजादी के दो वर्षों में लद्दाख की फिजा से भेदभाव का संक्रमण लुप्त हो गया। केंद्र का साथ मिला और 75 वर्षों से नजरअंदाज होती आई उम्मीदों को पूरा करने की झड़ी लग गई।

पांच अगस्त, 2019 से पहले लद्दाख के विकास की योजनाएं कश्मीर में कागजों तक ही सिमट जाती थी। अब केंद्र के हाथ लद्दाख की कमान आने के बाद परिदृश्य बदल रहा है। केंद्रीय मंत्री और संसदीय समितियां विकास योजनाओं पर न केवल सीधे नजर रखे हैं बल्कि जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नई योजनाओं का खाका बुना जा रहा है। जुलाई में चार संसदीय समितियां लद्दाख के दौरे पर पहुंची। अब 17 अगस्त को फिर से समितियां जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं।

कार्बन मुक्त प्रदेश का सपना : लद्दाख के लोग अब देश के पहले कार्बन मुक्त प्रदेश के सपने को साकार करने की मुहिम में जुटे हैं। ई-बसों व ई-रिक्शा के साथ-साथ हाइड्रोजन ईंधन आधारित वाहन चलेंगे। लेह में 1.25 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन जेनरेशन पायलट प्रोजेक्ट बनेगा। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हेतु तीन समझौते हुए हैं।

चार नए एयरपोर्ट व 37 हेलीपैड बनेंगे : केंद्र द्वारा चार नए एयरपोर्ट और 37 हेलीपैड विकसित करने की योजना है। इस समय 100 के करीब छोटे बड़े पुलों के निर्माण के बाद 55 नए पुलों पर कार्य जोरशोर से जारी है।

शिक्षा का बनेगा हब : लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए 750 करोड़ मंजूर कर ऐतिहासिक फैसला किया है। इसके अलावा मेडिकल कालेज और अन्य कई कालेजों को मंजूरी मिल चुकी है।

हरियाणा में साइबर ठगी में पहली बार 1220 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश

विनीत तोमर, रोहतक

हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय ठग गिरोह के मामले में रोहतक पुलिस की इकोनामिक सेल ने कोर्ट में 1220 पेज की चार्जशीट पेश की है। हैरानी की बात यह है कि यह पहला ऐसा मामला है, जिसमें ठगी के प्रकरण में तीन आरोपितों को लेकर इतने अधिक पेज की चार्जशीट पेश की गई। चार्जशीट में 13 पुलिसकर्मी समेत 26 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कालाढूंगी थाने के मुंशी और कानुपर के सिनेमाघर संचालक को भी शामिल है। हालांकि, मामले में सरगना समेत अन्य आरोपितों की चार्जशीट बाद में पेश की जाएगी। अभी पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के अड्डुपुर गांव निवासी बीएससी का छात्र मोहित फरार चल रहा है, जिसके खाते में चार माह के अंदर करीब 38 लाख रुपये का लेनदेन हुआ था।

गत वर्ष सितंबर माह में रोहतक के कंसाला गांव निवासी एक युवक के खाते से एक लाख 98 हजार रुपये निकाल लिए गए थे। मामले की जांच इकोनामिक सेल के जांच अधिकारी दिनेश कुमार को सौंपी गई। जांच के बाद इस प्रकरण में कानपुर के सराय बाजार निवासी जफर मंसूरी, दिल्ली के जखीरा निवासी दीपक और रूबी उर्फ प्रिया को गिरफ्तार किया था, जो एक सिम कंपनी में प्रमोटर का काम करते थे और फर्जी तरीके से सिम उपलब्ध कराते थे। आरोपित दीपक और रूबी उर्फ प्रिया फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं, जबकि जफर मंसूरी न्यायिक हिरासत में है। जांच में सामने आया था कि यह अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह है, जो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ठगी की वारदात कर चुके हैं। हालांकि, गिरोह के सरगना उत्तराखंड के अल्मोडा जिले के सिमलधार गांव निवासी नवीन चंद्र और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के बहादुरपुर गांव निवासी गौरव मिश्र थे, जिन्हें पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। अब इकोनामिक सेल की तरफ से आरोपित जफर मंसूरी, दीपक और रूबी उर्फ प्रिया को लेकर चार्जशीट पेश की है।

पुलिस ने मांगा 75 सिम कार्ड का रिकार्ड : गिरोह के सरगना नवीन समेत अन्य कई आरोपितों को नैनीताल जिले की कालाढूंगी थाना पुलिस ने भी पकड़ा था, लेकिन आरोपित बच गए थे। उनके पास से जो मोबाइल, सिम कार्ड और क्रेडिट कार्ड बरामद हुए थे उन्हें इकोनामिक सेल ने कब्जे में ले रखा है। अब सेल ने 75 सिम कार्ड का रिकार्ड पत्र लिखकर मांगा है।

चिनाब में बही नाव पहुंची पाकिस्तान, छलांग लगा जवानों ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, जम्मू

▸ नाव के पाकिस्तानी सीमा में जाने से पहले ही कूद गए नदी में, सभी सुरक्षित

जम्मू के सीमावर्ती अखनूर इलाके में सेना की नाव दरिया चिनाब में बहते हुए सीमापार पाकिस्तान पहुंच गई। इस नाव पर सेना के पांच जवान सवार थे, जिन्होंने दरिया के उफान के बीच गोते खा रही नाव से छलांग लगा कर जान बचाई और किसी तरह किनारे पहुंचे।

हादसा सोमवार देर शाम को अखनूर के परगवाल इलाके में सीमा से सटे गांव हमीरपुर कोना में हुआ। यहां पर सेना की 237 इंजीनियरिंग के जवान दरिया चिनाब में नाव को लेकर अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान अचानक नाव पानी में गोते खाने लगी। पिछले कुछ दिन से बारिश के चलते दरिया चिनाब में जलस्तर काफी बढ़ चुका है। उधर, जब नाव पानी में गोते खाने लगी तो पहले जवानों ने उस पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तेज पानी में नाव भी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। जिस जगह जवान अभ्यास कर रहे थे, उससे कुछ ही दूरी पर भारतीय सीमा समाप्त हो जाती है और पाकिस्तानी सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे में जवानों ने नाव को छोड़ कर दरिया में कूदना ही बेहतर समझा। अगर वे कुछ देर और नाव में रहते थे तो पाकिस्तानी इलाके में प्रवेश कर जाते जो उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। जवानों ने दरिया में छलांग लगा दी और किसी तरह से वे दरिया किनारे पहुंचे गए। उधर, इसकी जानकारी मिलते ही सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। सूत्रों के अनुसार, सेना की ओर से दूसरी ओर पाकिस्तान को नाव के बहकर वहां पहुंचने की जानकारी दे दी गई है।

ई-वाहनों के पंजीकरण पर शुल्क नहीं

नई दिल्ली : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र और नवीनीकरण को शुल्क मुक्त करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। बैटरी चालित वाहनों को नए पंजीकरण चिन्हों के शुल्क भुगतान से भी छूट दी गई है। बयान के अनुसार देश में ई-वाहन को बढ़ावा देने के इरादे से यह फैसला किया गया है। (प्रेट्र)

आटो कंपनियां सभी वाहनों में कम से कम छह एयरबैग मुहैया कराएं। वे एक वर्ष में फ्लेक्स फ्यूल वाहन लांच करने पर ध्यान केंद्रित करें।

– नितिन गडकरी, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलोग्राम)	डॉलर	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)
53,823.36	16,130.75	₹ 46,891	₹66,072	₹74.28	$ 73.23
872.73	245.60	₹31	₹372	₹0.06	

एफएमसीजी की बिक्री में दहाई अंकों की बढ़ोतरी

बिक्री बढ़ोतरी में ई-कामर्स का भी रहा योगदान, एचयूएल ने पहली तिमाही में 2,061 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) की बिक्री में दहाई अंकों से अधिक की बढ़ोतरी रही। बिक्री की बढ़ोतरी में ई-कामर्स की भी अहम भूमिका रही। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में डाबर इंडिया के एफएमसीजी कारोबार में पिछले वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले 35.4 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी के मुताबिक सेहत की बेहतरी से जुड़ी वस्तुओं के अलावा पर्सनल केयर की बिक्री में 26, हेयर केयर में 39, होम केयर में 30, ओरल केयर में 21 और स्किन केयर व सैलून से जुड़े उत्पादों के कारोबार में 66 फीसद की बढ़ोतरी रही। इस वर्ष अप्रैल-जून में डाबर इंडिया के शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष के मुकाबले 28 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पहली तिमाही का कंपनी का समग्र शुद्ध लाभ 437 करोड़ का रहा।

देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी एचयूएल ने पहली तिमाही में 2,061 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 10 फीसद अधिक है। कोरोना की दूसरी लहर में भी घरेलू बाजार में कंपनी की एफएमसीजी वस्तुओं की बिक्री 12 फीसद बढ़ी। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 13 फीसद तो होम केयर में 12 फीसद का इजाफा रहा।

इमामी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कर-पश्चात लाभ 77.79 करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में कंपनी ने इस मद में 39.58 करोड़ रुपये हासिल किए थे। कंपनी के मुताबिक इस वर्ष जून के आरंभ से कोरोना संक्रमण की दर में कमी होने से वस्तुओं की मांग फिर से बढ़ने लगी।

पंजाब नेशनल बैंक की 1,000 शाखाओं का इस वर्ष होगा विलय

ओबीसी व यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के विलय के बाद ऐसा करना हो गया था जरूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एसएस मल्लिकार्जुन राव ने कहा है कि बैंक की करीब 1,000 शाखाओं का अन्य में विलय किया जाएगा। इसका मकसद परिचालन खर्च घटाना है। बैंक ने कहा कि ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स (ओबीसी) और युनाइटेड बैंक आफ इंडिया के विलय के बाद ऐसा करना जरूरी हो गया था। हालांकि इससे ग्राहकों को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा और उनके आसपास कम से कम एक शाखा परिचालन में रहेगी।

देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी कर्जदाता पीएनबी की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2021) के नतीजों की घोषणा के अगले दिन मंगलवार को उन्होंने यह जानकारी दी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंक ने 1023.46 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले तकरीबन तीन गुना है। राव अगले नौ महीनों के दौरान पीएनबी का वित्तीय प्रदर्शन और बेहतर रहने की उम्मीद जताई है। उनके अनुसार बाजार से ज्यादा कर्ज की वसूली होगी व अब कर्ज वितरण की रफ्तार भी बढ़ेगी। उनका कहना है कि वर्ष 2021-22 के दौरान पीएनबी का शुद्ध लाभ 4,000 से 6,000 करोड़ रुपये के बीच रह सकता है।

राव ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद शानदार वित्तीय प्रदर्शन की सबसे बड़ी वजह संचालन लागत में कमी और पुराने कर्ज की वसूली रही है। बैंक ने इस दौरान अपनी 500 शाखाओं का या तो अन्य में विलय किया है या उसे बंद कर दिया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,000 शाखाओं को बंद करने या दूसरे में मिलाने की तैयारी है। बैंक को करीब 14,000 करोड़ कर्ज की वसूली की भी उम्मीद है। इसमें से 9,000 करोड़ की राशि ऐसी होगी जिसे फंसा कर्ज (एनपीए) मानते हुए समायोजन किया जा चुका है।

पीएनबीएचएफ की हिस्सेदारी बिक्री में कोई गड़बड़ी नहीं

पीएनबी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस (पीएनबीएचएफ) में हिस्सेदारी एक अमेरिकी वित्तीय संस्थान को बेचने के मामले में किसी तरह की गड़बड़ी को खारिज किया है। एसएस मल्लिकार्जुन राव ने कहा है कि पीएनबीएचएफ के शेयरों के मूल्यांकन को लेकर फैसला पूंजी बाजार नियामक एजेंसी सेबी के नियमों के मुताबिक किया गया है। अब यह मामला कानूनी तौर पर सिक्युरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) के पास है और उसका फैसला सभी पक्षों को मान्य होगा। मामला पीएनबीएचएफ की तरफ से अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फंड कार्लाइल के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को इक्विटी हस्तांतरित कर 4,000 करोड़ रुपये जुटाने से जुड़ा हुआ है। जिस आधार पर अमेरिकी निवेशक को प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी किए थे, उस पर सेबी ने सवाल उठाया था। उसके बाद पीएनबी ने हाउसिंग फाइनेंस शाखा पीएनबीएचएफ को पूंजी जुटाने के इस तरीके पर पुनर्विचार को कहा। जब राव से पूछा गया कि पीएनबी और पीएनबीएचएफ के शीर्ष पदों पर रहते हुए फैसला लेने में उनसे गड़बड़ी हुई, तो उनका कहना था कंपनी के निदेशक बोर्ड ने सेबी के नियमों के मुताबिक ही फैसला किया है।

चौतरफा खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकार्ड पर

53,823.36 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 16,130.75 की रिकार्ड ऊंचाई पर निफ्टी

2.30 लाख करोड़ बढ़ा बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण

मुंबई, प्रेट्र: चुनिंदा बड़े आंकड़ों में तेज आर्थिक रिकवरी के संकेतों को देखते हुए मंगलवार को निवेशकों ने चौतरफा खरीदारी की। इसके दम पर बीएसई का 30-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 872.73 अंकों यानी 1.65 फीसद उछाल के साथ 53,823.36 के रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का 50-शेयरों वाला प्रमुख सूचकांक निफ्टी भी 245.60 अंक यानी 1.55 फीसद उछलकर 16,130.75 की रिकार्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स में इस छलांग के बाद बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 2.30 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 2,40,04,664.28 करोड़ रुपये के अब तक के उच्च स्तर पर जा पहुंचा।

मंगलवार को सेंसेक्स पैक में सबसे ज्यादा 3.89 फीसद का उछाल टाइटन के शेयरों में दर्ज किया गया। एचडीएफसी, नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारती एयरटेल और एसबीआइ में भी निवेशकों ने अच्छी खरीदारी की। सेंसेक्स पैक में सिर्फ बजाज आटो, टाटा स्टील और एनटीपीसी के शेयरों को नुकसान झेलना पड़ा। सेक्टोरल इंडेक्स के मामले में बीएसई मेटल को छोड़कर बाकी सब हरे निशान पर बंद हुए। मिडकैप व स्मालकैप इंडेक्स में भी 0.23 फीसद का उछाल देखा गया। दिन के कारोबार के बारे में केएलपी सिक्युरिटीज के रिसर्च प्रमुख एस. रंगनाथन ने कहा कि जुलाई में देश का निर्यात रिकार्ड मासिक बढ़ोतरी के साथ 35 अरब डालर के पार गया। वहीं, जीएसटी संग्रह भी फिर से एक लाख करोड़ रुपये के ऊपर रहा। यही वजह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली के बावजूद घरेलू शेयर बाजारों में तेजी देखी जा रही है।

निर्यात आधारित इकोनामी की तैयारी

कवायद

- वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों की इसी सप्ताह बैठक प्रस्तावित
- पीएम की उपस्थिति की उम्मीद, कई देशों के प्रतिनिधि भी होंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष 2021-22 में निर्यात में होने वाली भारी बढ़ोतरी की गति को और तेज करने का सरकार कोई मौका नहीं खोना चाहती है। यही वजह है कि निर्यात संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने व बाधाओं को दूर करने के लिए इसी सप्ताह अहम सरकारी बैठक होने जा रही है। बैठक में निर्यात प्रोत्साहन के लिए रेमिशन आफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज आन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स (रोडटेप) लागू करने की अवधि सुनिश्चित करने के साथ नए बाजार तलाशने एवं यूरोप व अमेरिका जैसे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में तेजी लाने जैसे मसलों पर बातचीत होगी। कई देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों के साथ होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं।

चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार महीनों (अप्रैल-जुलाई, 2021) में भारत 130.56 अरब डालर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात कर चुका है। चालू वित्त वर्ष का निर्यात लक्ष्य 400 अरब डालर है, जिसे हासिल करने के लिए शेष आठ माह में हर माह 33.68 अरब डालर का निर्यात करना होगा।

फार्मा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन दिनेश दुआ के अनुसार निर्यात को पंख लगाने का यह बिल्कुल सही अवसर है। अमेरिका व यूरोपीय देशों के अलावा कई अन्य देश चीन की वस्तुओं को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। सरकार निर्यातकों की सुविधा बढ़ाकर इस अवसर का फायदा उठा सकती है। सूत्रों के मुताबिक रोडटेप की दरें तय नहीं होने से निर्यातक असमंजस में हैं और इस वर्ष जनवरी से उनके सभी ड्यूटी ड्राबैक भी बंद हैं। हालांकि पिछले कई महीनों से मंत्रालय की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जल्द ही रोडटेप लागू होगा, लेकिन वित्त मंत्रालय के साथ इस मसले पर सहमति नहीं बनने से इसकी घोषणा नहीं हो सकी है। वहीं, पिछले कुछ दिनों से निर्यातकों को कंटेनर की भी भारी दिक्कत हो रही है। आस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबाट भी छह अगस्त को वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर सकते हैं। एबाट आस्ट्रेलिया के विशेष व्यापारिक दूत के रूप में भारत के दौरे पर हैं। भारत और आस्ट्रेलिया के साथ फिर से कांप्रिहेंसिव इकोनामिक कापरेशन एग्रीमेंट (सीईसीए) वार्ता की शुरुआत हो सकती है।

एक करोड़ टन से अधिक क्षमता के बनेंगे साइलोज

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : आधुनिक टेक्नोलाजी से तैयार गोदामों (साइलोज) की भंडारण क्षमता जल्द बढ़कर 1.08 करोड़ टन पहुंच जाएगी। इसके लिए कुल 249 स्थलों का चयन किया गया है। खाद्य भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए गठित खाद्य प्रबंधन की उच्च स्तरीय समिति की हाल में हुई बैठक में इसके मसौदों पर मुहर लगी है। देश के विभिन्न हिस्सों में फिलहाल 30 लाख टन क्षमता के साइलोज तैयार हैं।

लोकसभा में पूछे एक लिखित सवाल के जवाब में बताया गया कि गेहूं और चावल के भंडारण के लिए तैयार होने वाले स्टील के साइलोज का निर्माण सरकार निजी कंपनियों के सहयोग (पीपीपी) से करेगी। गेहूं और चावल के लिए अलग-अलग तरह के साइलोज बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए कार्य योजना तैयार की है।

राह से भटकी आइबीसी में बड़े बदलाव की जरूरत

- नए दिवालिया कानून को लेकर संसदीय समिति की रिपोर्ट
- 13,000 मामले 180 दिनों की निर्धारित समय सीमा के बाद भी लटके हैं
- इनमें कर्जदाताओं व अन्य पक्षों के नौ लाख करोड़ से ज्यादा फंसे हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: इंसाल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) की सफलता को लेकर जानकारों के एक वर्ग के संदेह को संसदीय समिति की छानबीन ने भी बल दिया है। वित्त मामलों की संसदीय समिति ने एक रिपोर्ट में कहा है, आइबीसी राह से भटक गई है और फंसे कर्ज को वसूलने में आइबीसी वैसा काम नहीं कर पाई है जिसके लिए इसे अस्तित्व में लाया गया था। संसदीय समिति की रिपोर्ट मंगलवार को लोकसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में इसकी बड़ी वजह इसमें हुए संशोधनों को माना गया है।

इस रिपोर्ट में आइबीसी से जुड़े हर तंत्र की खामियां उजागर की गई हैं। इस कानून के मुताबिक फंसे कर्ज से जुड़े मामलों का आइबीसी के तहत अधिकतम 180 दिनों के भीतर निपटारा करने का प्रविधान है। लेकिन करीब 13,000 मामले ऐसे हैं जो इस समय सीमा को बहुत पहले पार कर चुके हैं और लटके हैं। इन मामलों में नौ लाख करोड़ से ज्यादा की राशि फंसी हुई है। ऐसे में संसदीय समिति ने सरकार को कई तरह से व्यापक बदलाव करने की सलाह दी है। हालांकि आइबीसी में पहले ही सरकार कई संशोधन कर चुकी है। लेकिन संसदीय समिति की सिफारिशों को करने की स्थिति में इसमें और कई संशोधनों की दरकार होगी।

वर्ष 2016 में राजग सरकार ने आइबीसी को लागू किया था और इसे जीएसटी की तरह ही एक क्रांतिकारी आर्थिक कदम बताया गया था। संसदीय समिति ने भी स्वीकार किया है कि वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में विश्व बैंक की तरफ से ईज आफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत की स्थिति बेहतर होने के पीछे आइबीसी एक अहम वजह थी। लेकिन उसके बाद से यह कानून अपने उद्देश्यों से काफी भटक गया है। आइबीसी के तहत आए मामले में 95 फीसद राशि की वूसली नहीं होने के लिए भी इसमें हुए संशोधनों को जिम्मेदार बताया गया है।

ये बताई गई कमियां

- आइबीसी की सफलता के लिए इंसाल्वेंसी रिजाल्यूशन प्रोफेशनल्स (आइआरपी) की भूमिका बहुत अहम होती है, लेकिन समिति ने महज स्नातक उत्तीर्ण को भी आइआरपी बना दिए जाने पर हैरानी जताई है।
- आइआरपी की योग्यता व विशेषज्ञता पर संदेह जताते हुए समिति ने कहा है कि इन्हें बड़े जटिल मामलों को निपटाने की जिम्मेदारी दी जा रही है जो अनुचित है
- इंसाल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड आफ इंडिया (आइबीबीआइ) की तरफ से अभी तक 203 आइआरपी के खिलाफ जांच की गई है और 123 के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है

सुधार के लिए सुझाए ये उपाय

- कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लेट) के उत्तरदायित्वों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के कदम उठाने चाहिए
- एनसीएलटी और एनक्लेट में पर्याप्त बहाली होनी चाहिए ताकि आइबीसी के तहत आने वाले मामलों को निपटाने में देरी ना हो।
- समाधान के लिए आने वाली कंपनियों के कर्जदाताओं के अधिकारों को लेकर अधिक स्पष्टता की जरूरत है।

राष्ट्रीय फलक

बिहार में एसडीपीओ ने बेरोजगार पति को वर्दी पहना इंटरनेट मीडिया में फोटो किया पोस्ट

जागरण संवाददाता, भागलपुर

- पीएमओ से की गई शिकायत, एसडीपीओ के अनुसार उनके पति हैं आइपीएस और पीएमओ में हैं तैनात
- पीएमओ ने की जांच, वहां इस नाम का कोई आइपीएस नहीं
- पीएमओ ने मामले को बिहार पुलिस मुख्यालय को भेजा, हो रही जांच

वायरल हुई फोटो में पति के साथ रेशू कृष्णा। इंटरनेट मीडिया

खाकी वर्दी में पति की फोटो लेकर इंटरनेट मीडिया में पोस्ट करना बिहार के भागलपुर जिले के कहलगांव की एसडीपीओ (डीएसपी) रेशू कृष्णा को भारी पड़ गया। किसी ने शिकायत कर दी कि एसडीपीओ के पति पुलिस में नहीं हैं, बावजूद वर्दी में उनकी तस्वीर लगातार एसडीपीओ पोस्ट कर रही हैं, साथ में खुद भी हैं। मामला इतना चर्चित हो गया कि पुलिस मुख्यालय को इसकी जांच करनी पड़ी।

पुलिस मुख्यालय भी अब इस मामले में कुछ बोलने से परहेज कर रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में भागलपुर एसएसपी को भी पत्र भेजा है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इस मामले की रिपोर्ट सौंप दी गई है। वहीं रेशू कृष्णा का कहना है कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। दूसरी तरफ भागलपुर के एसपी (नगर) ने इस संबंध में कहा कि यह उनका निजी मामला है। मुख्यालय से जांच के लिए पत्र आया है। इसकी जांच की जा रही है।

बताया गया कि कहलगांव की एसडीपीओ रेशू कृष्णा पटना की निवासी हैं। रेशू ने बीपीएससी परीक्षा में 13वीं रैंक हासिल की थी। भोजपुर जिले में अपनी तैनाती के दौरान कई मामलों का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर सुर्खियों में आई थीं। इसके बाद महिला बटालियन में तैनात हुईं। फिर कहलगांव में एसडीपीओ के रूप में तैनाती हुई। हाल के दिनों में रेशू कृष्णा अपने पति के साथ फोटो को इंटरनेट मीडिया में पोस्ट करने लगीं।

किसी ने इसकी शिकायत कर दी कि उनके पति रोशन कृष्ण कुछ काम नहीं करते हैं तो उन्होंने पुलिस की वर्दी कैसे पहनी। शिकायत करने वाले ने पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) को भी पत्र भेजा कि एसडीपीओ यह कहती हैं कि उनके पति आइपीएस हैं और पीएमओ में तैनात हैं। इस शिकायत पर पीएमओ ने जांच की। वहां कोई आइपीएस अधिकारी नहीं है। इसके बाद पीएमओ ने मामले को बिहार पुलिस मुख्यालय को भेज दिया। पत्र आते ही मुख्यालय में इस मामले को लेकर कोहराम मच गया। मुख्यालय ने गुपचुप तरीके से जांच की। इसकी जांच भागलपुर एसएसपी कर रहे हैं। मामला इसलिए भी उलझ गया है कि सैन्य और पुलिस पोशाक को आम आदमी के पहनने पर पाबंदी है।

बंगाल में दो भाजपा कार्यकर्ताओं के शव मिले, टीएमसी पर आरोप

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार को भाजपा के दो कार्यकर्ताओं के शव मिले हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से संरक्षण प्राप्त अपराधियों ने उनकी हत्या की। हालांकि, टीएमसी ने इस आरोप को निराधार बताया है।

पुलिस ने कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता इंद्रजीत सूत्रधार का शव बीरभूम जिले के खोइरासोल में एक सुनसान इमारत में कमरे की छत से लटका पाया गया है। इंद्रजीत के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सही कारण और परिस्थितियों की पुष्टि होगी।

स्थानीय भाजपा नेताओं ने कहा कि सूत्रधार की हत्या टीएमसी का आश्रय प्राप्त अपराधियों ने की है। सूत्रधार के परिवार के सदस्यों ने कहा कि वह सोमवार से लापता थे और उनकी कुछ स्थानीय लोगों के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी थी। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाजपा के एक अन्य कार्यकर्ता तपन खटुआ का शव पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में एक तालाब से निकाला गया। भाजपा और खटुआ के परिवार ने उनकी मौत के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। स्थानीय टीएमसी नेतृत्व ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सूत्रधार की हत्या व्यक्तिगत झगड़े के कारण हुई और खटुआ के आत्महत्या करने का संदेह है।

बिहार में सीबीआइ ने जीएसटी के दो अफसरों को रिश्वत लेते दबोचा

राज्य ब्यूरो, पटना : सीबीआइ ने सीजीएसटी महानिदेशक (इंटेलीजेंस) के पटना स्थित जोनल आफिस से जीएसटी के दो अफसरों को 10 हजार रुपये की रिश्वत के साथ दबोचा है। मंगलवार को दोनों को गिरफ्तार करने के बाद उनके कार्यालय की जांच भी की गई।

सीजीएसटी महानिदेशक (इंटेलीजेंस) के पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित जीएसटी अधीक्षक उमेश प्रसाद और इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार सिंह के खिलाफ सीबीआइ को लिखित शिकायत दी गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि दोनों बैंक लेनदेन के एक मामले में उनके फर्म का पक्ष लेने के लिए 50 हजार रुपये की रिश्वत की मांग रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद सीबीआइ ने कार्रवाई की। पेशगी के रूप में दस हजार रुपये लेते दोनों अफसर दबोच लिए गए।

खेल जागरण

भारतीय बल्लेबाजों का टेस्ट लेंगे इंग्लिश गेंदबाज

- भारत व इंग्लैंड के बीच आज शुरू होगा पहला टेस्ट मैच

अभ्यास सत्र के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी • एएनआइ

टीमें

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिषभ पंत, आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मुहम्मद शमी, मुहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, लोकेश राहुल, रिद्धिमान साहा, अभिमन्यु ईश्वरन, पृथ्वी शा और सूर्यकुमार यादव।

इंग्लैंड : जो रूट (कप्तान), जेम्स एंडरसन, जानी बेयरस्टो, डोम बेस, स्टुअर्ट ब्राड, रोरी बर्न्स, जोस बटलर, जैक क्राउले, सैम कुर्रन, हसीब हमीद, डेन लारेंस, जैक लीच, ओली पोप, ओली रोबिनसन, डोम सिब्ले और मार्क वुड।

नाटिंघम, प्रेट्र : विराट कोहली के कप्तानी करियर के सबसे कड़े चार महीनों की शुरुआत बुधवार को होगी। बड़ा सवाल यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट की सीरीज के पहले टेस्ट में वह किस संयोजन संग उतरेंगे। यही नहीं, जेम्स एंडरसन व स्टुअर्ट ब्राड की अगुआई में इंग्लिश गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेना चाहेंगे।

कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए अंतिम एकादश की घोषणा मैच से कुछ दिन पहले ही कर दी थी और परिस्थितियां बदलने के बावजूद टीम नहीं बदलने पर उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था। टीम के पास सिर्फ दो सलामी बल्लेबाज हैं, जिसमें से रोहित शर्मा काफी सक्षम हैं, लेकिन इंग्लैंड की परिस्थितियों में उन्होंने टेस्ट मैचों में पारी का आगाज नहीं किया है। वहीं, लोकेश राहुल बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन पारी की शुरुआत में हिचकिचाते हैं। मयंक अग्रवाल के सिर में चोट लगने के बाद रोहित के जोड़ीदार के रूप में राहुल तार्किक पसंद हैं। देखना होगा कि टीम बंगाल के सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को चुनकर जोखिम उठाएगी या हनुमा विहारी को मौका देगी, जो आस्ट्रेलिया में एक बार नई गेंद का सामना कर चुके हैं। विहारी की आफ स्पिन गेंदबाजी व रविचंद्रन अश्विन की मौजूदगी में टीम में शार्दुल ठाकुर के खेलने का मौका बन सकता है। गेंदबाजी आलराउंडर के रूप में उन्हें रवींद्र जडेजा पर तरजीह मिल सकती है। ट्रेंट ब्रिज की घास वाली पिच पर कोहली और शीर्ष क्रम की राह आसान नहीं होगी। ऐसे में हाल में आलोचना का सामना करने वाले चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को कुछ विशेष करना होगा।

आसान नहीं सिराज की अनदेखी : टीम को हार्दिक पांड्या की कमी खलेगी। दो विशेषज्ञ स्पिनरों की उपयोगिता पर भी सवाल उठ सकते हैं। मुहम्मद शमी व इशांत शर्मा तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ हैं, पर उनकी उम्र बढ़ रही है। जसप्रीत बुमराह पहले जैसी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें पहले टेस्ट में मौका मिल सकता है। कप्तान के लिए भारत के सबसे तेज व फार्म में चल रहे गेंदबाज मुहम्मद सिराज की अनदेखी करना आसान नहीं होगा, जिनकी गेंद हेलमेट में लगने के बाद मयंक टेस्ट से बाहर हो गए।

एंडरसन व ब्राड से मिलेगी चुनौती : भारतीय टीम के सामने एक बार फिर ड्यूक गेंदों से जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्राड का सामना करने से चुनौती होगी। एंडरसन और ब्राड की अनुभवी जोड़ी का साथ दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शामिल मार्क वुड और युवा ओली रोबिनसन देंगे। जो रूट कड़ी टेस्ट सीरीज में ब्राड और एंडरसन को उनकी उम्र को देखते हुए रोटेट कर सकते हैं। इंग्लैंड के कप्तान रूट हालांकि स्वीकार कर चुके हैं कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बेन स्टोक्स की गैरमौजूदगी का बड़ा असर पड़ेगा।

पुजारा को अकेले छोड़ देना चाहिए : कोहली

नाटिंघम, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली का मानना है कि खेल में खामियों को परखने की जिम्मेदारी स्वयं खिलाड़ी की है और चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी के आलोचकों को उन्हें खुद इसका आकलन करने के लिए छोड़ देना चाहिए। मौजूदा भारतीय टीम में कोहली के बाद पुजारा टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 86 मैचों में 6267 रन बनाए हैं, लेकिन उन पर अक्सर जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक रवैया अपनाने के आरोप लगते रहे हैं।

कोहली ने कहा, 'इस बारे में पिछले कुछ समय से बात हो रही है और मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि इस तरह की प्रतिभा और अनुभव वाले खिलाड़ी को खेल की कमियां निकालने के लिए अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं बाहर से कह सकता हूं कि आलोचना अनावश्यक है, लेकिन मैं इस तथ्य को जानता हूं कि पुजारा को इसकी परवाह नहीं है और ऐसी आलोचना उतनी ही प्रासंगिक है जितनी आप चाहते हैं।'

वहीं शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी क्षमता को लेकर कोहली ने कहा, 'हां, उन्हें (शार्दुल को) आलराउंडर बनाया जा सकता है। वह पहले से ही एक बहुआयामी क्रिकेटर हैं और यह अधिक से अधिक आत्मविश्वास हासिल करने के बारे में है। उसके जैसा कोई खिलाड़ी टेस्ट या किसी भी प्रारूप की टीम को संतुलित बनाने में मदद करता है। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो सिर्फ इस सीरीज में नहीं, बल्कि आगे के लिए भी बहुत जरूरी होंगे।'

तेज और उछाल भरी पिच चाहते हैं एंडरसन

नाटिंघम : भारत के खिलाफ सीरीज से पहले इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का मानना है कि जिस तरह से भारत ने इस साल के शुरू में अपनी घरेलू मैदानों पर अनुकूल पिचें बनाई थीं उसी तरह से इंग्लैंड को भी पांच टेस्ट की सीरीज के दौरान तेज व उछाल वाली अच्छी पिचें तैयार करनी चाहिए। एंडरसन ने कहा, 'यदि हम पिच पर थोड़ा घास छोड़ देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई शिकायत हो सकती है क्योंकि भारत के पिछले दौरे में हम निश्चित तौर पर उनके अनुकूल परिस्थितियों में खेले थे। अगर पिच पर थोड़ी घास मौजूद रहती है तो भारत के पास भी अच्छा तेज गेंदबाजी आक्रमण है। तेज गेंदबाज होने के नाते हम तेजी व उछाल चाहते हैं। हम जानते हैं कि गेंद स्विंग होगी व ऐसे में गेंद के बल्ले का किनारा लेने की संभावना बढ़ जाती है। मुझे विश्वास है कि वे पिच पर कुछ घास छोड़ेंगे और रोलर भी चलाएंगे।' वहीं भारतीय बल्लेबाजी और कप्तान विराट कोहली का विकेट लेने के बारे में एंडरसन ने कहा, 'भारत की बल्लेबाजी बेहद मजबूत है और आप किसी एक बल्लेबाज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते।'

बांग्लादेश की आस्ट्रेलिया पर टी-20 में पहली जीत

ढाका, एपी : बायें हाथ के स्पिनर नासुम अहमद (4/19) के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मदद से बांग्लादेश ने पहले टी-20 क्रिकेट मैच में मंगलवार को आस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। यह बांग्लादेश की आस्ट्रेलिया पर टी-20 क्रिकेट में पहली जीत है। बांग्लादेश ने 20 ओवर में सात विकेट पर 131 रन बनाए। जवाब में आस्ट्रेलिया की टीम 20वें ओवर की अंतिम गेंद पर 108 रन बनाकर आलआउट हो गई।

आस्ट्रेलिया के तीन विकेट तीसरे ओवर में ही 11 रन तक गिर गए थे। उसकी ओर से सिर्फ मिशेल मार्श ही कुछ देर टिककर खेल सके, जिन्होंने 45 गेंद में 45 रन बनाए। इससे पहले बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने 33 गेंद में 36 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज मुहम्मद नईम ने 29 गेंद में 30 रन बनाए। आरिफ हुसैन ने भी नाबाद 23 रन बनाए। आस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने 24 रन देकर तीन विकेट झटके।

अहंकार के दमन से ही वास्तविक उन्नति की राह खुलती है

अवसर गंवाता विपक्ष

इस पर हैरानी नहीं कि संसद फिर नहीं चली। ऐसा होने के आसार तभी उभर आए थे, जब राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया था। पता नहीं इस बैठक में क्या तय हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि उसमें संसद को न चलने देने पर ही सहमति बनी। इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ साइकिल मार्च निकाला, ताकि यह दिखा सकें कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम किस तरह एक समस्या बन गए हैं। बेशक इस साइकिल यात्रा ने टीवी कैमरों को मनचाहे दृश्य उपलब्ध कराए, लेकिन जब संसद चल रही हो तब सड़क पर प्रदर्शन करना उचित है या फिर उन मुद्दों पर सदन में बहस करना, जिन्हें ज्वलंत बताया जा रहा है? यह वह सवाल है, जिस पर विपक्ष को चिंतन-मनन करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वह अपने आचरण से अवसर गंवाने का ही काम कर रहा है। यह विचित्र है कि विपक्ष एक ओर यह कह रहा है कि कोविड महामारी, कृषि कानूनों से लेकर महंगाई और पेगासस जासूसी कांड जैसे मसलों पर सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन जब इसके लिए मौका आता है यानी संसद चलने की बारी आती है, तब वह ऐसा कुछ करता है, जिससे संसदीय कामकाज बाधित हो जाए।

बीते दो सप्ताह से विपक्ष संसद के भीतर अपनी बात कहने के बजाय संसद परिसर में अथवा सड़क पर अधिक सक्रिय दिख रहा है। संसद सत्र के समय सड़क की राजनीति करने पर रोक नहीं, लेकिन विपक्ष इस पर विचार करे तो बेहतर कि इससे उसे हासिल क्या हो रहा है? वह सड़क की राजनीति करके सरकार को घेरने और उससे जवाब मांगने के अपने अधिकार का परित्याग ही कर रहा है। आम तौर पर अभी तक यह देखने को मिलता रहा है कि विपक्ष कुछ दिन संसद के भीतर-बाहर हंगामा करता है, फिर अपनी ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर बहस के लिए तैयार हो जाता है। इससे उसकी बात न केवल आम जनता तक कहीं प्रभावी तरीके से पहुंचती है, बल्कि वह संसदीय कामकाज का हिस्सा भी बनती है। संसद के बाहर दिए जाने वाले बयान तो अगले 24 घंटे में ही अपनी महत्ता खो देते हैं। विपक्ष एक तरफ संसद नहीं चलने दे रहा है और दूसरी तरफ इस पर आपत्ति जता रहा है कि वहां विधेयक कैसे पारित हो रहे हैं? निःसंदेह बिना बहस अथवा हंगामे के बीच विधेयक पारित होना आदर्श स्थिति नहीं, लेकिन जब विपक्ष संसद न चलने दे तो फिर सत्तापक्ष के पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों को जैसे-तैसे पारित कराए। ऐसा करना न तो अनुचित है और न ही अवैधानिक।

खुल गए स्कूल

कोरोना संकट के कारण हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से बंद पड़े स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। अब 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेंगी, जबकि पांचवीं और आठवीं के विद्यार्थी परामर्श के लिए स्कूल आ सकेंगे। विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने से पहले प्रदेश सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। कई नियम भी बनाए गए हैं। स्कूल परिसर और कमरों को सैनिटाइज किया गया है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। मास्क पहनना जरूरी किया है, जबकि शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। यह भी व्यवस्था है कि स्कूलों में हाजिरी नहीं लगेगी। यदि कोई विद्यार्थी स्कूल नहीं आना चाहता है तो वह घर पर रहकर ही आनलाइन पढ़ाई कर सकता है। उसे स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। लंबे समय से बंद स्कूल खुलने पर पहले दिन विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। बच्चे और अभिभावक मांग कर रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के कारण स्कूलों को खोला जाना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है कि बच्चे काफी समय से घर पर रहकर अन्य गतिविधियों से दूर हो गए हैं। आनलाइन पढ़ाई के लिए सारा दिन बच्चे मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर पढ़ाई करते रहे। इससे उनकी आंखों पर असर पड़ा है। स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। बेशक स्कूलों में शिक्षक बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर हैं, लेकिन विद्यार्थियों को भी जागरूक होना होगा। उन्हें समझाना होगा कि बेशक अब महामारी का प्रकोप लगभग थमने की कगार पर है, लेकिन किसी तरह की लापरवाही न की जाए। अभिभावक बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें कि अन्य बच्चों के साथ शारीरिक दूरी बनाकर रखें और मास्क अवश्य पहनें। बच्चों को भी चाहिए कि वे बार-बार हाथ धोते रहें और शिक्षकों के दिशानिर्देश मानें। तीसरी लहर आने की आशंका के बीच कोई भी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। ऐसे में कोविड अनुशासन का पालन करना ही होगा ताकि पहली और दूसरी लहर जैसे दौर की पुनरावृत्ति न हो सके।

कोरोना महामारी के खतरे के बीच स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में हर पक्ष को सजग रहने की जरूरत है

संवैधानिक दायरे में सियासी लाभ

ए. सूर्यप्रकाश

मेडिकल में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की पहल कर मोदी सरकार ने जाति केंद्रित दलों के वर्चस्व को उनके ही अखाड़े में मात दी

मोदी सरकार ने मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में आरक्षण को लेकर हाल में एक महत्वपूर्ण पहल की। इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों यानी ईडब्ल्यूएस के लिए इनमें अखिल भारतीय स्तर पर आरक्षण का विस्तार किया जाएगा। यह भाजपा जैसी एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा उठाया गया चतुराई भरा कदम है। इसके माध्यम से उसने अपने मूल मतदाताओं को खुश रखते हुए तमाम क्षेत्रीय दलों के जातिगत समर्थन में सेंध लगाने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में अनुच्छेद 15 में धारा चार जोड़ी गई। इसके अनुसार राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रविधान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह राज्य द्वारा की गई आरंभिक स्वीकारोक्ति थी कि ऐसे नागरिकों के संरक्षण के लिए आरक्षण या ऐसी अन्य नीतियां आवश्यक थीं।

ओबीसी को लेकर आजादी के बाद से ही सुगबुगाहट जारी रही है। इस मसले की पड़ताल के लिए कई आयोग और समितियां गठित की गईं। इनमें काका कालेलकर आयोग प्रमुख था। कालेलकर आयोग ने 1953 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। राज्यों में भी दर्जनों आयोग सक्रिय रहे। सरकार ने कालेलकर आयोग की रपट पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उसमें उसे गंभीर विरोधाभास महसूस हुए। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अर्स ने राज्य में ओबीसी को लेकर हैवनूर आयोग गठित कर उसकी रपट के क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाए। 1978 में बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने अपने राज्य में ओबीसी के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था का एलान किया। वह ओबीसी के उप-वर्गीकरण के भी धुर समर्थक थे। इसके बाद मंडल आयोग की वजह से यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर मुखरित हुआ। मंडल आयोग का गठन 1979 में जनता पार्टी सरकार ने किया था। आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। उसका उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पड़ताल और उनके सुधार के उपाय सुझाना था। मंडल आयोग ने आर्थिक पिछड़ेपन का संज्ञान नहीं लिया। आयोग की दृष्टि में देश की 52 प्रतिशत आबादी ओबीसी के दायरे में आती है, लिहाजा उसके अनुसार सभी नौकरियों में उनका 52 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार बनता था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित कर दी। ऐसे में आयोग ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत कोटे की सिफारिश की। मंडल आयोग ने कहा कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है, लेकिन समता का सिद्धांत एक दोधारी तलवार है। यह जीवन की दौड़ में सशक्त और अशक्त को एक ही पायदान पर रखता है। चूंकि आयोग का उद्देश्य सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पड़ताल करना था, इसलिए आर्थिक पिछड़ेपन को चिन्हित करना उसके एजेंडे में नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि 'किसी समाज की मानवीयता के स्तर का निर्धारण इसी से होता है कि वह अपने कमजोर, अशक्त और साधनहीन सदस्यों को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करता है।'

अवधेश राजपूत

यद्यपि जाति अभी भी पिछड़ेपन को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख कारक है, लेकिन समय के साथ उन गरीब वर्गों के स्वर भी मुखर हुए हैं, जो सामाजिक ढांचे में ओबीसी से ऊंचे स्तर पर माने जाते हैं। उनका कहना है कि ओबीसी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रविधानों ने उनके लिए कोई खास गुंजाइश नहीं छोड़ी है। राज्य ने उन्हें तथाकथित अगड़ी जातियों में आंका और इसी आधार पर उन्हें विशेष संरक्षण का पात्र नहीं माना, लेकिन उनकी दयनीय आर्थिक दशा ने स्वतंत्र भारत में उभरे नए सामाजिक एवं आर्थिक समीकरणों में उनके अस्तित्व पर संकट पैदा कर दिए। यही भावनाएं मंडल आयोग की सिफारिशों के खिलाफ आक्रामक रूप से अभिव्यक्त हुईं।

मंडल के पक्ष-विपक्ष में हुई लामबंदी ने पहले से ही विभाजित हिंदू समाज में विभाजन की खाई को और चौड़ा कर दिया। वीपी सिंह के जनता दल से जुड़े नेता इससे चिंतित नहीं हुए, क्योंकि आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों से उन्हें अपना ओबीसी वोट बैंक मजबूत होता दिखा। इसके बाद जनता परिवार में कई विभाजन हुए। लालू प्रसाद की राजद, नीतीश कुमार की जदयू और एचडी देवगौड़ा के जनता दल सेक्युलर ने ओबीसी कार्ड खेलकर अपने-अपने राज्यों में सत्ता का स्वाद चखा।

एक वक्त देश भर में एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ओबीसी राजनीति के व्यापक प्रभाव का अनुमान लगाने में नाकाम रही। इसी कारण बिहार जैसे राज्यों से उसका सूपड़ा साफ हो गया और उसकी सियासी जमीन पर अन्य पार्टियां काबिज हो गईं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बनी भाजपा ने इन जाति केंद्रित दलों को चुनौती देकर उन्हें उनके ही खेल में मात देने की दिशा में कदम बढ़ाए।

भले ही यह सब वोटरों को लुभाने का खेल हो, लेकिन यहां संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निदेशक तत्वों को नहीं भुलाना चाहिए। उसमें कई ऐसे प्रविधान हैं, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भारतीय राज्य को वंचित वर्गों का उत्थान और बेहतर गुणवत्तापरक जीवन सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और असमानता के निर्मूलन की दिशा में काम करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 लोगों की जीवन गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य से कदम उठाने की अपेक्षा करता है।

जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 15 में संशोधन किया और उसमें धारा छह जोड़कर ईडब्ल्यूएस के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की। इसी प्रकार अनुच्छेद 16 में धारा छह जोड़कर सरकार ने इसी वर्ग के लिए नौकरियों में भी अधिकतम दस प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया। वैसे तो ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के कई पैमाने हैं, लेकिन सबसे मुख्य मानदंड यही है कि सालाना आठ लाख रुपये से कम आमदनी वाले परिवार ही इस श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार मेडिकल में अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की पहल कर मोदी सरकार ने भले ही जाति केंद्रित दलों के वर्चस्व को उनके अखाड़े में मात दी हो, लेकिन यह पूरी तरह राज्य के नीति निदेशक तत्वों की भावना के अनुरूप है।

(लेखक लोकतांत्रिक विषयों के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

पेट पर लात मारने वाला आंदोलन

राजीव सचान

जो लोगों की रोजी-रोटी छीनने का काम करे, वह कुछ भी हो सकता है, पर अन्नदाता हरगिज नहीं हो सकता

कृषि कानूनों के विरोध में जब किसान संगठन अपने लोगों के साथ सड़कों पर उतरे थे, तब उन्हें अन्नदाता कहकर संबोधित किया गया था-न केवल समर्थकों की ओर से, बल्कि सरकार की ओर से भी, लेकिन बीते आठ महीनों में किसान संगठनों ने आम नागरिकों के समक्ष जैसी समस्याएं खड़ी की हैं, उसे देखते हुए उन्हें मुसीबतदाता ही कहा जा सकता है। किसान संगठन न केवल दिल्ली की सीमाओं को घेरकर बैठे हैं, बल्कि उनके धरना-प्रदर्शन दिल्ली की सीमाओं के अलावा भी जारी हैं। उनके कारण भी लोगों को समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। संकट केवल यह नहीं कि लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि यह भी है कि बहुत से लोगों की रोजी-रोटी के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ के उद्योगों के सामने तो कहीं बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हाल की एक खबर के अनुसार बहादुरगढ़ के उद्योगों का कुल टर्नओवर करीब 80,000 करोड़ रुपये का है। किसान आंदोलन की वजह से उन्हें अब तक करीब 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

बहादुरगढ़ के उद्यमियों की मानें तो दिल्ली को जोड़ने वाला टिकरी बार्डर बंद होने से इस क्षेत्र की फैक्ट्रियों के वाहनों को खेतों के कच्चे रास्ते से होकर दिल्ली जाना पड़ता है। इस रास्ते से एमसीडी को टोल देना पड़ता है और रास्ता देने के लिए खेतों के मालिकों को प्रति वाहन सौ-सौ रुपये भी। अब बारिश के कारण खेतों के रास्ते में पानी भर गया है और वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है। बावजूद इसके किसान संगठन सड़क खाली करने को तैयार नहीं। बहादुरगढ़ चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अनुसार किसान संगठनों की रास्ताबंदी के कारण करीब सात लाख लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। करोड़ों रुपये के राजस्व का नुकसान अलग से हो रहा है। इसके अलावा लोगों के लिए टिकरी बार्डर आना-जाना भी दूभर है। यही कहानी सिंघु बार्डर पर भी है। दिल्ली-हरियाणा को जोड़ने वाली यहां की सड़क पर कब्जा होने की वजह से आसपास के लगभग 40 गांवों के लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी तरह उनकी भी नहीं सुनी जा रही, जो गाजीपुर बार्डर यानी यूपी गेट बाधित होने से आजिज आ चुके हैं। सड़कों को बाधित करना गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन क्षोभ और लज्जा की बात यह है कि न तो पुलिस के कान पर जूं रेंग रही है, न सरकार के और न ही उस सुप्रीम कोर्ट के, जिसने कहा था कि सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता।

अदाणी लाजिस्टिक्स के बाहर बैठे प्रदर्शनकारी। फाइल

तथाकथित अन्नदाता किस तरह लोगों के पेट पर लात मारने का काम अन्यत्र भी कर रहे हैं, इसका एक और उदाहरण है लुधियाना में अदाणी समूह की ओर से अपने लाजिस्टिक पार्क को बंद किया जाना। इस पार्क का उद्देश्य पंजाब के उद्योगों को आयात और निर्यात के लिए रेल और सड़क मार्ग से कार्गो सेवा उपलब्ध कराना था। इस साल जनवरी में कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने लाजिस्टिक पार्क के बाहर ट्रैक्टर ट्राली लगाकर रास्ता बंद कर दिया। यह काम इस दुष्प्रचार की आड़ में किया गया कि कृषि कानूनों से तो असल फायदा अदाणी और अंबानी को होगा। प्रदर्शनकारियों की घेराबंदी के कारण लाजिस्टिक पार्क का काम ठप हो गया। कंपनी की तरफ से पंजाब सरकार को कई बार धरना हटाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उकसाने और बरगलाने वाली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में अदाणी समूह ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने अमरिंदर सरकार को इस मामले का हल निकालने के आदेश दिए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। थक-हारकर अदाणी समूह ने अपने इस पार्क को बंद करने का फैसला लिया। आखिर कोई कंपनी कब तक खाली बैठे लोगों को वेतन देती? लाजिस्टिक पार्क बंद करने के फैसले से चार सौ से अधिक लोगों की नौकरी चली गई। इसे इस तरह समझें कि तथाकथित अन्नदाताओं के कारण सैकड़ों लोगों के पेट पर लात पड़ गई। जो दूसरों के पेट पर लात मारने का काम करे, वह कुछ भी हो सकता है, पर अन्नदाता हरगिज नहीं हो सकता।

किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि किसान संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर सड़कों पर बैठे लोग आम किसान हैं। ये किसान नहीं, छुटभैये नेता, फुरसती लोग या फिर आदतन आंदोलनबाज हैं, जिन्हें किसानों का नेता बताया जा रहा है, वे भी वास्तव में किसान नेता नहीं, बल्कि किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने और नेतागीरी का शौक पालने वाले लोग हैं। शायद ही कोई किसान नेता ऐसा हो, जो सचमुच खेती-किसानी का काम करता हो। आखिर योगेंद्र यादव जैसे लोग किसान नेता कैसे हो सकते हैं? किसान नेता और उन्हें हवा दे रहे राजनीतिक दल कुछ भी दावा करें, यह निरा झूठ है कि आम किसान धरने पर बैठा हुआ है। आम किसानों के पास न तो इतना समय है कि वह अपना काम-धाम छोड़कर धरने पर बैठा रहे और न ही वह इतना निष्ठुर-निर्दयी हो सकता है कि जाने-अनजाने औरों की रोजी-रोटी छीनने का काम करे। चूंकि कई लोग और समूह राजनीतिक कारणों अथवा अन्य किसी स्वार्थवश कृषि कानून विरोधी आंदोलन को आर्थिक-मानसिक खुराक देने में लगे हुए हैं, इसलिए लगता नहीं कि उनका धरना-प्रदर्शन आसानी से समाप्त होगा। वह भले ही अनंतकाल तक जारी रहे, लेकिन उसे लोगों को परेशान करने, उनकी दिनचर्या बाधित करने और उनकी रोजी-रोटी छीनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यह सरकारों और उनके प्रशासन का नैतिक-आधिकारिक दायित्व है कि वे किसानों का भेष धारण किए नकली अन्नदाताओं से आम लोगों के हितों की रक्षा करें।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर हैं)

response@jagran.com

खेलों की उपयोगिता

जीवन में शिक्षा के साथ-साथ खेलों का भी अपना महत्व है। खेल मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। उनसे हमारे भीतर अनुशासन एवं परिश्रम जैसे गुण और सामाजिकता एवं देश प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। उनमें होने वाली हार और जीत जीवन में सफलता एवं असफलता के समय संतुलन बनाने की प्रेरणा देती हैं। खेलकूद से संयम, दृढ़ता, गंभीरता और सहयोग की भावना का भी विकास होता है। खेलों से नीरस जीवन सरस बनता है। मस्तिष्क के शरीर से और शरीर के खेल से पारस्परिक संबंधों को देखते हुए कह सकते हैं कि खेलकूद व्यक्ति के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। नेपोलियन को हराने वाले एडवर्ड नेल्सन का कथन खेलों के महत्व को रेखांकित करता है कि 'मैंने वाटरलू के युद्ध में जो सफलता प्राप्त की, उसका प्रशिक्षण ईटन के मैदान में मिला।'

एक सवाल बच्चों के मन में अक्सर आता है कि क्या पढ़ाई और खेलकूद साथ-साथ चल सकते हैं। इसका उत्तर है-हां। खेलों में सक्रियता का यह अर्थ नहीं है कि आप पढ़ाई-लिखाई छोड़ दो और अध्ययन का यह अर्थ नहीं है कि आप खेलना छोड़ दो। लगातार पढ़ाई के दौरान कई बार तनाव की स्थिति बनती है। खेल से तनाव का स्तर कम होता है। जो नित्यप्रति खेल में हिस्सा लेते हैं, उनकी एकाग्रता और अंतर्दृष्टि विलक्षण होती है। खेल से रचनात्मकता को भी बढ़ावा मिलता है।

अमेरिकी बास्केटबाल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का कथन है कि 'खेल एक महान शिक्षक है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया है वह है: मतभेद और विनम्रता और यह भी कि मतभेदों को कैसे हल करें।' आज के परिवेश और जीवन शैली का एक नकारात्मक पहलू यह है कि बच्चे हों या युवा, लगातार मोबाइल पर गेम खेलना उनकी एक आदत बनती जा रही है। ऐसे में नई पीढ़ी की खेलों में रुचि बढ़ाने के लिए अभिभावकों तथा शिक्षण संस्थाओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

कैलाश एम. बिश्नोई

मानव-हाथी टकराव के खतरे

सुधीर कुमार

गत 30 जुलाई को उत्तराखंड के कुंजा गांव में हाथी ने खेत में एक किसान को पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हफ्ते भर पहले झारखंड के लातेहार जिले में दर्जनभर हाथियों के झुंड ने फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाने के बाद एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। इससे पहले 19 जून को झारखंड के ही जामताड़ा में एक जंगली हाथी ने खेत जा रहे पति-पत्नी की जान ले ली। मानव-हाथी टकराव की इस तरह की अनेकों घटनाएं देश के विभिन्न हिस्सों से सामने आती रहती हैं। कई बार झुंड से बिछड़कर हाथी मानव बस्ती में जाकर उत्पात मचाने लगता है। सवाल यह है कि आखिर गजराज को गुस्सा क्यों आता है? वे उत्पात क्यों मचाते हैं? क्या सारा कुसूर उनका है या कुसूरवार हम भी हैं?

दरअसल बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आवास नष्ट होने ने मानव-हाथी टकराव को बढ़ावा दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2014 से 2019 के बीच 500 हाथियों की मौतें हुईं, जबकि इसी अवधि में 2361 लोगों की जानें भी गई हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मानव-हाथी टकराव की वजह से हर साल औसतन 100 हाथियों और 400 से अधिक इंसानों की जानें जा रही हैं। इसके अलावा घर, फसल, पशु और संपत्तियों का नुकसान भी उठाना पड़ता है। वास्तव में मानव-हाथी टकराव अपने-अपने अस्तित्व की लड़ाई है। टकराव की वजह से हाथियों की संख्या लगातार कम हो रही है, जिससे उनके संरक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है। इस टकराव को रोकना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि इससे दोनों पक्षों को केवल नुकसान ही होता है। इस प्रवृत्ति का पारितंत्र और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है।

'सह-अस्तित्व' की भावना से ही मानव और अन्य जीवों के बीच सही सामंजस्य बनेगा और पृथ्वी खुशहाल बन सकेगी

वर्ष 2017 की हाथी जनगणना के मुताबिक देश में एशियाई हाथियों की संख्या 27,312 है, जबकि 2012 में हाथियों की संख्या 29,576 थी। मानव-हाथी टकराव से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य ओडिशा, बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु है। टकराव की 85 फीसद घटनाएं इन्हीं छह राज्यों में होती हैं। 2017-2031 के बीच देश में तीसरी 'राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना' लागू है, जो वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम-1972 तथा संविधान के अनुच्छेद 48 (क) और 51-(क) का सातवां उपबंध भी पर्यावरण संरक्षण तथा जीवधारियों के प्रति दयालुता प्रकट करने का कर्तव्य बोध कराता है। किसी भी जीव-जंतु से मानव का टकराव पर्यावरण के लिए अहितकर है, क्योंकि यह कुछ प्रजातियों के अस्तित्व को ही खत्म कर देता है। लिहाजा 'सह-अस्तित्व' की भावना जागृत करनी होगी। तभी यह पृथ्वी खुशहाल हो पाएगी। इसमें हम मानवों की भूमिका सर्वोपरि है।

(लेखक बीएचयू में शोध अध्येता हैं)

मेलबाक्स

खुद को साबित करती आधी-आबादी

'महिलाओं को कमतर दिखाने की कोशिश' शीर्षक से लिखे आलेख में ऋतु सारस्वत ने यही सार निकाला है कि बेहतर शिक्षा, प्रतिभा और योग्यता के बावजूद महिलाओं को कामकाज के लिए अपेक्षित अनुपात में अवसर नहीं मिल पाते। यदि वह ऐसी टिप्पणी तीन-चार दशक पहले करतीं तो शायद उपयुक्त लगती, किंतु समय के साथ हमारे समाज में आए परिवर्तन के सामयिक संदर्भों में ऐसी बातें बेमानी लगती हैं। महिलाओं की उत्कृष्टता का सबसे सटीक प्रतीक तो टोक्यो में चल रहे ओलिंपिक खेल हैं, जहां भारत के लिए सुनिश्चित हुए तीनों पदक महिला खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। इतना ही नहीं विश्व में खेलों के इस सबसे बड़े महाकुंभ में भारत द्वारा जीते गए अंतिम सात पदकों में से छह महिलाओं की मेहरबानी से ही मिले हैं। यह बताता है कि कला-कौशल से लेकर शारीरिक दमखम तक के पैमाने पर हमारे देश की आधी आबादी स्थापित धारणाओं को ध्वस्त कर नए कीर्तिमान-प्रतिमान गढ़ रही हैं। मात्र खेलों में ही नहीं, अपितु आज लोकजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपनी छाप छोड़ रही हैं। यहां तक कि सेना में महिलाओं को अग्रिम मोर्चे पर भूमिकाएं देने की दिशा में कायम अवरोध दूर कर दिए गए हैं। इस मामले में कुछ स्तरों पर की जा रही आनाकानी को अदालती हस्तक्षेप ने दूर कर दिया है। निःसंदेह आज अंतरिक्ष से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर खेलों की दुनिया में महिलाएं अपनी महारत सिद्ध कर रही हैं, लेकिन यह सब रातोंरात नहीं हुआ है। बीते दो-तीन दशकों में इस स्थिति में नाटकीय सुधार हुआ है। इसके लिए देश में आर्थिक सुधारों के बाद सृजित हुए अवसरों की भी अहम और निर्णायक भूमिका रही। जब बीते तीन दशकों के दौरान स्थिति में इतना सुधार हो सकता है तो हमें अपेक्षित और तार्किक सुधार के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। स्मरण रहे कि किसी भी प्रकार की समानता स्थापित होने में कुछ समय तो लगता ही है।

गुंजन शर्मा, नई दिल्ली

खिलाड़ियों की सुध ले सरकार

हमारी पुरुष हाकी हाकी सेमीफाइनल में बेल्जियम से हारने के बाद भी कांस्य पदक की रेस से बाहर नहीं हुई है। वहीं भारतीय महिला हाकी टीम द्वारा आस्ट्रेलिया की ताकतवर महिला हाकी टीम को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाना निःसंदेह अविश्वसनीय, अविस्मरणीय और भावविभोर कर देने वाले पल थे जिसके लिए भारतीय महिला हाकी टीम बधाई की पात्र है। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, शटलर पीवी सिंधू, महिला बाक्सर लवलीना बोरगोहेन, डिस्कस थ्रोअर कमलजीत कौर, दीपक पुनिया आदि को देश के बेशकीमती नगीने कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन खिलाड़ियों की निष्ठा, जुझारूपन व मेहनत नई पीढ़ी को प्रेरित करेगी। भारत सरकार को भविष्य की नई खेल नीतियों के निर्माण के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और मनोबल बढ़ाने के लिए उनकी सुख-सुविधाओं के प्रति और गंभीर होना पड़ेगा। महिला हाकी खिलाड़ियों की माली हालत किसी से छिपी नहीं है।

दीपक गौतम, सोनीपत

गैर-जिम्मेदार विपक्ष

बहस, चर्चा और असहमति किसी भी लोकतंत्र के तीन सबसे जरूरी पहलू हैं और किसी भी मजबूत विपक्ष का यह कर्तव्य बनता है कि सत्ता पक्ष की गलत नीतियों का विरोध करे और लोगों की आवाज उठाएं, लेकिन इस प्रक्रिया में अगर संसद का लगभग पूरा सत्र ही हंगामे की भेंट चढ़ जाए तो फिर यह दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद के मानसून सत्र में इस बार कई ऐसे गंभीर मुद्दे थे, जिन पर गहन चर्चा होनी चाहिए थी, जैसे वैक्सीन की आपूर्ति, पेगासस इत्यादि। मगर ऐसा नहीं होने दिया गया। इसके बाद अब विपक्ष के पास कोई भी हक नहीं है कि वह सरकार को बिना बहस के कोई बिल पारित करने के लिए घेरे। संसद को सुचारु रूप से चलाने के लिए दोनों ही पक्ष बराबर के जिम्मेदार हैं। विपक्ष को अपना हठी व्यवहार छोड़ना ही पड़ेगा। अन्यथा उसका रवैया गैर जिम्मेदाराना ही कहा जाएगा। लगातार गतिरोध बनाकर विपक्षी दल देश की जनता के सामने कोई अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रहे हैं।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

आजकल

साइबर जासूसी का फैलता जाल

अब स्मार्टफोन लोगों के लिए खास जरूरत बन गए हैं। हालांकि ये एक चिंता की वजह भी बने हुए हैं। चिंता यह है कि कहीं ये स्मार्टफोन उनकी जासूसी करने में मददगार तो साबित नहीं हो रहे हैं? खुद सरकार भी इसे लेकर चिंतित रही है कि दुनिया के साइबर गुप्तचर हमारी सुरक्षा और नीतिगत जानकारियों में सेंध तो नहीं लगा रहे हैं? हाल में जासूसी का यह मुद्दा निगरानी साफ्टवेयर 'पेगासस' के इस्तेमाल से दुनिया भर के लोगों के स्मार्टफोन की हैकिंग से उठा है

देश में इंटरनेट के देसीकरण के प्रयासों को बढ़ावा मिले तो इलेक्ट्रानिक जासूसी की आशंकाओं को काफी हद तक खत्म किया जा सकेगा। फाइल

मोबाइल फोन खास तौर से स्मार्टफोन और कंप्यूटर जीवन का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। अब लोगों के लिए स्मार्टफोन और इनमें मौजूद रहने वाले एप्लिकेशंस यानी एप्स के बिना रहना कठिन हो गया है। हालांकि इधर तमाम लोगों को ये स्मार्टफोन एक अन्य कारण से चिंता की वजह भी लग रहे हैं। चिंता यह है कि कहीं ये स्मार्टफोन उनकी जासूसी करने में मददगार तो साबित नहीं हो रहे हैं? खुद सरकार भी इसे लेकर चिंतित रही है कि दुनिया के अंधेरे कोनों में बैठे साइबर गुप्तचर हमारे स्मार्टफोन और विभिन्न इलेक्ट्रानिक उपकरणों में किए गए प्रबंधों के बल पर हमारी सुरक्षा और नीतिगत जानकारियों में सेंध तो नहीं लगा रहे हैं। कारोबार खासतौर से बैंकिंग व्यवसाय तो अरसे से ऐसी खुफियागिरी से प्रताड़ित रहा है। हाल में जासूसी का यह मुद्दा निगरानी टूल बनाने वाली इजरायल की कंपनी-एनएसओ द्वारा निर्मित जासूसी साफ्टवेयर 'पेगासस' के इस्तेमाल से दुनिया भर के लोगों के स्मार्टफोन की हैकिंग से उठा है।

कुछ समय पहले कुछ मीडिया समूहों में यह खबर प्रकाशित की गई कि पूरी दुनिया के पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कुछ सरकारी अधिकारियों-नेताओं के फोन जासूसी या निगरानी के साफ्टवेयर 'पेगासस' की मदद से हैक किए गए। उल्लेखनीय है कि इस साफ्टवेयर की निर्माता कंपनी-एनएसओ ने दावा किया है कि वह अपना यह जासूसी साफ्टवेयर चुनिंदा सरकारों को बेचती है। यह भी सूचना आई कि निगरानी का यह साफ्टवेयर निशाने पर लिए गए व्यक्ति के स्मार्टफोन में घुसपैठ करने के बाद उसके कैमरे और माइक्रोफोन पर कब्जा कर लेता है। इसका पता उस व्यक्ति को भी नहीं हो पाता है कि उसका फोन हैक हो गया है। असल में यह साफ्टवेयर एक तरह के कंप्यूटर वायरस (ट्रोजन) की तरह काम करता है जिसमें स्मार्टफोन रखने वाले व्यक्ति की मोबाइल और इंटरनेट से जुड़ी हर गतिविधि दूसरों के नियंत्रण में चली जाती है। मामला सिर्फ भारत का नहीं है, बल्कि कई देश, सरकारी खुफिया एजेंसियां और सेनाएं वर्ष 2009 में स्थापित हुई इस इजरायली कंपनी के ग्राहक हैं और उन देशों में भी लोगों की जासूसी का मुद्दा गर्माया हुआ है।

क्यों होती है जासूसी : सरकारों और उनकी जासूसी एजेंसियों का पक्ष यह है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आतंकवादी घटनाओं समेत विभिन्न गैरकानूनी व राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर अंकुश रखने के मकसद से ऐसा करती हैं। इस बारे में भारत सरकार का पक्ष यह है कि हमारे देश में इसकी एक स्थापित प्रक्रिया है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से या किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना होने पर या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्यों की एजेंसियां किसी व्यक्ति, समूह या संगठन के इलेक्ट्रानिक संचार को इंटरसेप्ट करती हैं। कानूनी तौर पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा-5(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा-69 के प्रविधानों के तहत इलेक्ट्रानिक संचार के वैध इंटरसेप्शन के लिए अनुरोध किए जाते हैं, जिनकी अनुमति सक्षम अधिकारी देते हैं। यही नहीं, वर्ष 2019 में पूर्व संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री दयानिधि मारन ने लोकसभा में जब पूछा था कि क्या सरकार देश में वाट्सएप काल और मैसेज की टैपिंग करती है और क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए इजरायल के पेगासस साफ्टवेयर का उपयोग करती है? तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा-69 केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मानिटर या डिक्रिप्ट करने का अधिकार देती है। उन्होंने यह भी बताया था कि ये अधिकार भारत की संप्रभुता या अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या इनसे जुड़े किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए या किसी अपराध की जांच के लिए दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए जिन दस एजेंसियों को अधिकृत किया है, उनमें इंटेलीजेंस ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, कैबिनेट सचिवालय (रा), सिग्नल इंटेलीजेंस निदेशालय (जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्व और असम की सेवा क्षेत्रों के लिए) और पुलिस आयुक्त, दिल्ली शामिल हैं। हालांकि इस व्याख्या में यह जवाब तब भी नहीं मिला था कि भारत सरकार इंटरसेप्शन के लिए पेगासस का प्रयोग करती है या नहीं।

पर क्या पेगासस दुनिया का पहला ऐसा निगरानी साफ्टवेयर या टूल है, जो फोन हैक करके जासूसी कर सकता है? दुनिया में गुप्तचरी शासन व्यवस्था या राजकाज के संचालन की सबसे प्राचीन रीति है। हालांकि बीते दशकों में इसके कई इलेक्ट्रानिक रास्ते खुल गए हैं। इसमें भी ज्यादा समस्या दुश्मन देशों द्वारा विविध तरीकों से कराई जाने वाली जासूसी है। पिछले ही वर्ष भारत सरकार ने पबजी, शेयरइट सरीखे चीन के दर्जनों मोबाइल गेम्स और एप्लिकेशंस पर इसी आरोप के तहत प्रतिबंध लगाया था कि ये भारतीय नागरिकों की जासूसी कर जरूरी डाटा चीनी कंपनियों और चीन सरकार के हवाले कर रहे हैं। यह आशंका वर्ष 2017 में भी उठी थी। तब इंटेलीजेंस ब्यूरो के हवाले से यह आशंका जताई गई कि चीन के 40 से ज्यादा एप्लिकेशन हमारे स्मार्टफोन को हैक कर सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों को सलाह दी गई थी कि वे वीचैट, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, ट्रू-कालर और शेयरइट आदि एप्स को अपने स्मार्टफोन से हटा दें। माना गया था कि ये एप्लिकेशन असल में चीन की तरफ से विकसित किए गए जासूसी के एप हैं और इनकी मदद से जो भी सूचनाएं, फोटो, फिल्में एक-दूसरे से साझा की जाती हैं, उनकी जानकारी चीन के सर्वरों तक पहुंच जाती है। एप्स ही नहीं, कई स्मार्टफोन को भी हमारी सरकार संदेह के घेरे में ले चुकी है। अगस्त 2017 में केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली चीन समेत कई अन्य देशों की 21 कंपनियों को इस बारे में नोटिस जारी किया था। सरकार ने संदेह जताया था कि ओप्पो, वीवो, शाओमी और जियोनी के स्मार्टफोन के जरिये चीनी खुफिया एजेंसियां भारतीय ग्राहकों की पर्सनल जानकारियां चुरा रही हैं।

चीन के एप्स और फेसबुक-गूगल : सिर्फ चीनी स्मार्टफोन या एप्लिकेशंस से लोगों की जासूसी हो रही है, ऐसा नहीं है। जानकारी चुराकर उसे बेचने के आरोप फेसबुक पर भी लग चुके हैं। असल में फेसबुक या गूगल को यह पता रहता है कि कोई व्यक्ति किसी समय में आनलाइन क्या गतिविधियां करता रहा है। इनमें एक व्यक्ति के एक स्थान तक आने-जाने, समय, खरीदारी आदि के ट्रेंड की जानकारियां होती हैं। फेसबुक तो यह कहता भी है कि वह अपने यूजर्स के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारियां जुटाता है। प्रोपब्लिका के मुताबिक ऐसा करना एक व्यक्ति की निजी सूचनाओं को बिना उसकी जानकारी के चुराने जैसा है।

बात चाहे आम लोगों की निजी जिंदगी से जुड़ी सूचनाओं की हो या देश की जासूसी की, स्मार्टफोन और एप्लिकेशंस का संदेह में आना एक बड़ी चिंता की बात है। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के मुताबिक ऐसी जासूसी का कृत्य दंडनीय हो सकता है, पर समस्या यह है कि इसे साबित करना दिनोंदिन कठिन होता जा रहा है। देश में करोड़ों मोबाइल फोन धारक हैं और ज्यादातर के पास अब स्मार्टफोन हैं। इन पर वे कौन-कौन से एप्लिकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, इसकी जानकारी लेना भी आसान नहीं है, क्योंकि कई तो सीधे विदेश स्थित सर्वरों से सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। ऐसे में दो ही रास्ते हैं-एक, या तो फेसबुक, गूगल से लेकर हर प्रमुख वेबसाइट से कहा जाए कि वे भारत में ही अपना सर्वर स्थापित करें। दूसरा रास्ता है कि देश में फेसबुक-गूगल आदि के विकल्प पैदा किए जाएं। उल्लेखनीय है कि चीन ने ऐसा ही किया है। उसने इन सभी के बेजोड़ विकल्प बनाकर विदेशी आनलाइन दासता व जासूसी की आशंकाओं को धता बताया है। कथित सरकारी जासूसी के संबंध में आरोपों को कैसे साबित किया जाएगा? यह बड़ा सवाल है। भले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी ओर से इसकी जांच बैठा दी है, पर क्या यह जांच कुछ ठोस सामने ला पाएगी? इसमें भरपूर संदेह है। हालांकि निजी इंटरनेट कंपनियों द्वारा की जाने वाली इलेक्ट्रानिक जासूसी के संबंध में सबक यही है कि हमारे देश में भी गूगल, वाट्सएप, वीचैट और फेसबुक-इंस्टाग्राम के देसी विकल्प पैदा किए जाएं। अगर देश में इंटरनेट के देसीकरण के प्रयासों को बढ़ावा मिलता है तो इलेक्ट्रानिक जासूसी की आशंकाओं को काफी हद तक खत्म किया जा सकेगा।

काफी कीमती हैं जासूसी करने वाले साफ्टवेयर

स्मार्टफोन के जरिये निगरानी के लिए फिलहाल जो साफ्टवेयर पेगासस चर्चा में है, उसे खरीदने में भारी-भरकम पूंजी लगती है। दावा है कि इसके लिए सरकारों और विभिन्न एजेंसियों को करोड़ों रुपये की फीस चुकानी पड़ती है। असल में अत्यंत उन्नत तकनीक वाले इस जासूसी साफ्टवेयर की खरीद उसी तरह होती है, जैसे देश अपने लिए लड़ाकू विमान या युद्धपोत खरीदते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि एक बार बिक्री हो जाने के बाद इजरायली कंपनी का इस साफ्टवेयर से नियंत्रण हट जाता है। और यह उन सरकारों-एजेंसियों के पास चला जाता है, जो इसका दाम चुकाती हैं। आशय यह है कि खरीदने के बाद एजेंसियां जासूसी साफ्टवेयर का मनचाहा इस्तेमाल कर सकती हैं।

विशेषज्ञों का मत है कि पेगासस की कार्यप्रणाली किसी कंप्यूटर वायरस जैसी हो सकती है। इसके लिए वांछित व्यक्ति यानी टारगेट को पहले कोई करप्ट मैसेज या फाइल भेजी जाती है। जैसे ही वह व्यक्ति किसी प्रलोभन के तहत उस संदेश या फाइल को अपने फोन पर खोलता है, उसकी डिवाइस (फोन) को तुरंत हैक कर लिया जाता है। फिर यह साफ्टवेयर उसके फोन में घुस जाता है और बिना कोई व्यवधान पैदा किए जारी गतिविधियां रिकार्ड कर आगे पहुंचाता रहता है। इसकी मदद से बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन कुछ खास लोगों की निगरानी की जा सकती है।

खरी-खरी

मथनी जी, बूढ़ा हाथी और 51 फीसद माखन

जवाहर चौधरी

मथनी की तरह घूम-घूमकर वे दिल्ली को मथ रही थीं। विश्वास यह कि माखन निकलेगा। दिल्ली को मथने से माखन निकलता है। जिसने ठीक से मथा, नवनीत उसे ही मिला। इसलिए 'मथनी जी' आत्मविश्वास से भरी दिल्ली पहुंच गईं और पुरातन दल के नवांकुरित दलपति से मिलीं। 'देखिए, विपक्ष की एकता का विचार अच्छा है, पर माखन कैसे बंटेगा, इस पर चर्चा नहीं हुई।'-पुरातन दल के नवांकुरित दलपति ने अपनी बात रखी। 'ये बताइए कि सारा माखन आपको दे दें तो आप हजम कर लोगे?'-मथनी जी ने फायरब्रांड सवाल दागा। 'दो मिनट रुको, मम्मी से पूछकर बताता हूं।'-दलपति ने कहा। 'ऐसी कौन सी मम्मी है, जो दुनिया का सारा माखन अपने बच्चू को नहीं देना चाहेगी? वो तो हां ही कहेंगी।'-मथनी जी ने कहा। 'फिर किससे पूछूं!' 'मैं हूं ना। मुझसे पूछो। देखो हम पिरामिड बनाएंगे और मिलकर मटकी फोड़ेंगे तो माखन सबको मिलेगा।' 'मिटकी फोड़ में गोविंदा किसको बनाओगे?' 'मैं दिल्ली मथ रही हूं तो साफ है कि गोविंदा मैं बनूंगी।' 'लेकिन हमारा दल राष्ट्रीय है और सबसे बड़ा व पुराना है इसलिए गोविंदा तो हमारा ही होगा और सबसे ज्यादा माखन भी हमें देना होगा।' 'सच्चाई को देखिए दलपति। आपका दल बूढ़ा हाथी है, खाता ज्यादा, हिलता कम है। ऐसे में खेला कैसे होगा?' 'मथनी जी...माइंड योर लैंग्वेज, हम जानते हैं अपने हाथी को।' 'पक्का आप ठीक से जानते हैं? तो अच्छा बताइए कि हाथी की सूंड किधर होती है और पूंछ किधर होती है?'

इस बीच मम्मी आ जाती हैं। उन्हें भी सामूहिक प्रयास के बारे में बताया जाता है। 'माखन का इशू साल्व करना पड़ेगा। यू नो 60 परसेंट माखन हमारे गुड्डू के लिए जरूरी है।'-मम्मी बोलीं। 'देखिए मैडम, एक बार मटकी फूट जाए। माखन का इशू तो बाद में भी हल हो जाएगा।'-मथनी जी ने कहा। 'चलिए 51 परसेंट हमें दीजिए।'-मम्मी ने कहा। 'जितनी भी पार्टियों से मिली हूं, सारे 51 परसेंट मांगते हैं! और मुझे भी 51 परसेंट होना है। आखिर दिल्ली तो मैं ही मथ रही हूं।'-मथनी जी ने कहा। तो दिल्ली आपके बस की नहीं है मैडम...नमस्कार।

ट्वीट-ट्वीट

ताकत, पैसा, भूख, लालच, प्रेम, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा या अभिमान जैसी हर वह चीज जो जीवन में आवश्यकता से अधिक है, वही जहर है।
अरुण गोविल@arungovil12

पहले खिलाड़ियों का धर्म देखो। फिर जाति देखो। फिर क्षेत्र। फिर भाषा। केवल यह क्यों नहीं देख लेते कि वह इन सबसे ऊपर और सबसे पहले भारतीय है। उसके सीने का तिरंगा ही उसकी पहचान है...और हमारी भी।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

कोई भी देश तब तक समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि वह वास्तव में उत्कृष्टता प्राप्त किए जाने वाले प्रयासों और किसी फिल्म में ऐसा करते हुए दिखाए जाने के बीच अंतर करना नहीं जानता हो।
संजीव सान्याल@sanjeevsanyal

सोमवार को जब कमलप्रीत कौर डिस्कस थ्रो मुकाबले में भाग ले रही थीं तो भारत में तमाम लोग उन्हें देख रहे थे। वे इस खेल की बारीकियों और नियमों को लेकर जिज्ञासा व्यक्त करते दिखे। कमलप्रीत ने भले ही पदक न जीता हो, लेकिन उनकी यह कामयाबी भी कम बड़ी नहीं। वह व्यापक प्रभाव छोड़ने में सफल रहीं।
प्रो. शमिका रवि@ShamikaRavi

क्रिकेट के हजारों प्रायोजक हैं। वहीं भारत के राष्ट्रीय खेल हाकी के महिला और पुरुष टीम का प्रायोजक ओडिशा जैसा राज्य है। देश का हर राज्य कम से कम एक खेल पर ऐसे ही ध्यान दे तो स्थिति जरूर सुधरेगी।
अतुल कुमार राय@AuthorAtul

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या कोरोना संक्रमण के बीच स्कूलों का खुलना सही है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या ओलिंपिक में भारत का अब तक का प्रदर्शन संतोषजनक कहा जा सकता है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

देते रहते बोलकर सहयोगी को टीस,
आखिर किसके साथ हो बोलो चचा नितीश।
बोलो चचा नितीश आप हो किसके बाजू,
किसके घर में भोज और किसके घर काजू?
जब आ जायं चुनाव एक ही धारा बहते,
पर सीएम बन आप चिकोटी देते रहते!!
- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तराखंड डायरी

चार-चार कार्यकारी अध्यक्ष : जरूरी या मजबूरी

कुशल कोठियाल
राज्य संपादक, उत्तराखंड

पंजाब कांग्रेस की सांगठनिक समस्या का हल निकालने में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत (हरदा) पर पंजाब का ऐसा रंग चढ़ा कि उन्होंने गृह राज्य (उत्तराखंड) में भी नए अध्यक्ष को चार-चार कार्यकारी अध्यक्षों से लदवा दिया। साथ में दस प्रांतीय प्रवक्ता भी नियुक्त किए गए हैं। यह जरूरत थी या मजबूरी, कांग्रेस में भी विमर्श का बिंदु बना हुआ है।

कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सांगठनिक फेरबदल को अंजाम दिया है। गणेश गोदियाल ने शक्ति प्रदर्शन के साथ प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाल लिया और पिछले चार वर्षों तक इस पद पर रहे प्रीतम सिंह ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से समझौता कर लिया है। इसके साथ ही जीत राम, भुवन कापड़ी, तिलक राज बेहड़ और रंजीत रावत ने भी कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली है। पूरी कसरत के पीछे खड़े हरीश रावत को हाईकमान ने तीन सदस्यीय प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया है। जाहिर है चुनाव अभियान की कमान रावत के पास ही रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष उनका अपना होने के कारण टिकटों के बंटवारे से लेकर अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका निर्णायक ही होगी। अब राज्य के राजनीतिक पंडित इस बात को लेकर सिर धुन रहे हैं कि छोटे से राज्य में युवा व सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष को संगठन चलाने के लिए चार-चार कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत क्यों आन पड़ी? यह जरूरत थी या मजबूरी। पंजाब में कांग्रेस की गुत्थी सुलझाते-सुलझाते हरीश रावत यहां भी वही क्यों करवा बैठे जो पंजाब में किया? खास तौर पर जबकि प्रदेश में कांग्रेस के पास पहले से ही 260 सदस्यीय जम्बो कार्यकारिणी मौजूद है। इस बेड़े में 31 महामंत्री, 22 उपाध्यक्ष और 79 प्रदेश सचिव मौजूद हैं। हालांकि यह सीधे-सीधे कांग्रेस का आंतरिक मामला है और पार्टी चाहे तो कितने भी कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन इस सांगठनिक अधिकार पर क्यों लगाने वाले भी तो कांग्रेस के ही हैं और उनके भी अपने अधिकार हैं। पहला प्रश्न तो यह उठाया जा रहा है कि जब कांग्रेस को सात माह बाद राज्य में चुनाव में उतरना है तो चार साल से चले आ रहे अध्यक्ष को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? कांग्रेस उन्हें अध्यक्ष के रूप में चला कर अब तक गलती कर रही थी या अब गलती कर रही है? कांग्रेस के धड़े अपनी-अपनी सुविधा के हिसाब से इसका उत्तर चुन रहे हैं। कुछ कांग्रेसी तो यह भी दावा कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर गोदियाल को लाकर पार्टी ने भाजपा को भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को फिर से बदलने को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। गौरतलब है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से हैं व वह भी ब्राह्मण हैं। चुनाव से पहले प्रदेश में संगठन की कमान में परिवर्तन करने के दो कारण जाहिर हैं। पहला, पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह प्रदेश में हरीश रावत धड़े को सूट नहीं कर रहे थे। गोदियाल को प्रीतम के मुकाबले ज्यादा सक्रिय और वफादार समझा गया। दूसरा, पहाड़ में ब्राह्मण वोट बैंक को पार्टी फोल्ड में लाने के लिए पहाड़ के ब्राह्मण को संगठन का नेतृत्व सौंपना उचित समझा गया। कांग्रेस के इस दांव को भाजपा सरकार में बनाए गए उत्तराखंड चारधाम देवास्थानम बोर्ड एवं पंडा-पुरोहितों के खुले विरोध के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। अब दूसरा सवाल यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जब सक्षम, सक्रिय और तुलना में युवा नेता को लाया गया है तो चार-चार कार्यकारी अध्यक्ष उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? यहां जरूरत से ज्यादा मजबूरी दिखाई दे रही है। हालांकि यह पंजाब के स्तर की मजबूरी या व्यावहारिकता नहीं कही जा सकती। कांग्रेसी ही इस सच को बयां करने से गुरेज नहीं कर रहे कि राज्य में आधी कांग्रेस के भाजपा में विलय हो जाने के बाद से पार्टी अब इस स्थिति में नहीं है कि किसी को नाराज कर सके। इसी सच को चार-चार कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति का आधार माना जा रहा है।

उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं गणेश गोदियाल (बाएं), चुनाव प्रचार समिति की बागडोर संभालेंगे पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह (दाएं) को बनाया गया है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। फाइल

पुराने कांग्रेसियों का भी मानना है कि पार्टी संगठन में अनुशासन जिस पायदान पर खड़ा है, उसमें यही एकमात्र हल था। इसीलिए प्रदेश में हरीश रावत के विरोधियों को भी थामे रखने की खासी कोशिशें हुई हैं। कभी उनके खास व अब मुखर विरोधी रंजीत रावत को भी कार्यकारी अध्यक्ष का ओहदा मिला है। अध्यक्ष पद से हटाए गए प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष के ओहदे से नवाजा गया है। कोषाध्यक्ष के पद पर आर्येंद्र शर्मा की नियुक्ति को भी इसी कोण से देखा जा सकता है।

हरियाणा डायरी

खाली पड़े पंडाल, नेपथ्य में आंदोलनकारियों के नेता

जगदीश त्रिपाठी
प्रभारी, हरियाणा स्टेट डेस्क

तीनों कृषि सुधार कानून विरोधी आंदोलनकारियों के तंबू खाली हैं। तंबू खाली हैं तो पंडाल भी खाली हैं। चाहे कुंडली बार्डर हो या दिल्ली बार्डर, आंदोलन में जो ग्लैमर था, वह पंजाब से था। पंजाब से लोग बड़ी लग्जरी गाड़ियां, मसाज मशीनें और विलासिता की ढेर सारी वस्तुएं लेकर आते थे। अब कुछ नहीं दिखता। खालिस्तान समर्थक तत्व भिंडरांवाले की तस्वीर लगी टी-शर्ट पहने विचरण करते थे। हरियाणा वाले भी खीर, दूध, दही लेकर पहुंचते थे, अब इन पर भी विराम लग गया है। आंदोलनकारियों के बड़े नेता फिलहाल नेपथ्य में हैं। आंदोलन को संचालित करने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित किए जा चुके भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के गुरनाम सिंह चढ़ूनी का निलंबन काल बीत गया अथवा वापस ले लिया गया, इसकी कोई घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन वे अपने समर्थकों सहित टीकरी बार्डर से कुंडली बार्डर पर पहुंचकर अपनी ताकत दिखा चुके हैं और यह भी स्पष्ट कर चुके हैं कि वह अपने मिशन पंजाब पर अडिग हैं। मिशन पंजाब यानी पंजाब के किसान संगठन पंजाब में विधानसभा का चुनाव लड़ें और अपना शासन लाएं। एक रोचक बात यह भी है कि इस बयान को देने के कारण गुरनाम सिंह चढ़ूनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने भले ही निलंबित कर दिया हो, लेकिन पंजाब में आंदोलन के एक प्रमुख नेता बलबीर सिंह राजेवाल की फोटो वाले बड़े-बड़े पोस्टर लगाकर पूछा जा रहा है (पंजाबी में) कि आप राजेवाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? स्पष्ट है कि चढ़ूनी ने जो चिंगारी सुलगाई थी, वह अब भड़कने लगी है।

कृषि सुधार कानून विरोधी आंदोलन की असलियत सामने आने के बाद आम किसान संयुक्त किसान मोर्चा से विमुख होने लगे हैं। फाइल

उधर हरियाणा के लोग अब आंदोलन में शामिल पंजाब के नेताओं से विमुख होने लगे हैं। पहले भी हरियाणा के लोग राकेश टिकैत को ही महत्व देते थे। चढ़ूनी के बाद हरियाणा के एक अन्य नेता जोगेंद्र नैन को निलंबित कर संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। चढ़ूनी के निलंबन से वे पहले ही क्षुब्ध थे। यद्यपि ऐसा नहीं कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अब तक केवल हरियाणा के नेताओं को ही निलंबित किया हो, पंजाब के एक संगठन के नेता रुलदु सिंह मानसा भी निलंबित हुए हैं। मानसा के निलंबन का जो कारण है, उसने हरियाणा के लोगों का गुस्सा और बढ़ाया है। मानसा का निलंबन इसलिए किया गया, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानी तत्वों और विदेश से फोन कर आतंक को बढ़ावा देने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू की आलोचना की थी। इन सब बातों को देखते हुए राकेश टिकैत और शिवकुमार शर्मा जैसे नेताओं ने स्वयं को नेपथ्य में कर लिया है। चढ़ूनी अकेले चीख रहे हैं कि यदि आंदोलन के नेताओं के बीच फूट पड़ी तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि आंदोलन के नेताओं के बीच फूट तो इसके आरंभ से ही पड़ गई थी। अब तो वह खुली किताब की तरह हो गई है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। पन्ने पलटने की जरूरत भी नहीं। आंदोलन स्थल पर दुष्कर्म, जलाकर हत्या जैसी वीभत्स वारदातें हो चुकी हैं। इसलिए वहां अब लोग जाना भी नहीं चाहते। धरनास्थलों पर खाली पंडाल देख कुछ लोग मंच से बार-बार युवाओं को लाने के लिए अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील खारिज हो जाती है। जो अभी हैं भी, वे अब वापस जाने की सोच रहे हैं। पहले उनको राशन, पानी, सब्जियां पहुंचाने में हरियाणा के लोगों में होड़ लगी रहती थी। अब उनकी ये सुविधाएं बंद हो चुकी हैं।

दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन (मान) के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर गुणीप्रकाश को भी उन किसानों का समर्थन मिलने लगा है, जो इस कथित किसान आंदोलन के विरोधी हैं। चढ़ूनी और राकेश टिकैत उनकी चुनौती को आज तक नहीं स्वीकार कर पाए हैं। गुणीप्रकाश ने चढ़ूनी और टिकैत से कहा था कि वे खालिस्तान मुर्दाबाद, भिंडरांवाले मुर्दाबाद बोलकर दिखाएं। गुणीप्रकाश के इस चैलेंज को स्वीकार करना तो दूर आंदोलनस्थल पर अप्रत्यक्ष रूप से खालिस्तानी समर्थकों की आलोचना करने पर रुलदु सिंह मानसा को निलंबित कर दिया गया। राकेश टिकैत, चढ़ूनी, योगेंद्र यादव इसके विरोध में आवाज उठा ही नहीं सके तो खालिस्तान मुर्दाबाद कैसे बोलेंगे। एक बात और। आंदोलन के नेता भले स्वीकार न करें, लेकिन वे समझते हैं कि आंदोलन मर रहा है। मध्य हरियाणा में कहीं-कहीं भाजपा नेताओं का जो विरोध हो रहा है, उसका कारण एक वर्ग विशेष है, जो यह चाहता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री केवल उनके समुदाय का हो और यह अगले विधानसभा चुनाव के पहले संभव नहीं है। भाजपा की रणनीति उस पहलवान जैसी है, जो अखाड़े में खुद आक्रामक होने के बजाय अपने प्रतिस्पर्धी को थकाकर हराने में विश्वास रखता है। और उसकी यह रणनीति सफल होती दिख रही है।

24 राज्यों के 2.96 करोड़ स्कूली छात्रों के पास डिजिटल उपकरण नहीं हैं। ऐसे छात्रों में सबसे ज्यादा बिहार के हैं। उपरोक्त राज्यों में दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ शामिल नहीं हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 4 अगस्त, 2021

उत्तराखंड

पहाड़ में उद्योग लगाने की कवायद

बढ़ती बेरोजगारी और पलायन की समस्या से जूझ रहे उत्तराखंड में सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को जमीन चिन्हित करने को कहा है। सरकार इसके लिए लैंड बैंक तैयार करने की कवायद में जुटी है। दरअसल उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद से ही प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के प्रयास होते रहे हैं। बीते 21 वर्ष में प्रत्येक सरकार ने उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर प्रयास किए और विशेष पैकेज देने की घोषणा भी की।

यहां तक कि खंडूड़ी सरकार के कार्यकाल में पहाड़ों के लिए बाकायदा औद्योगिक नीति भी बनाई गई। शुरुआती दौर में इस पर काम भी हुआ और रुद्रप्रयाग जिले में सिमली को औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर विकसित भी किया गया। खंडूड़ी सरकार की योजना थी पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके तहत औद्यानिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक उत्पाद, सगंध और औषधीय पादप आदि से जुड़े उद्योगों को पहाड़ में स्थापित किया जाना था। विडंबना ही है कि सिस्टम की उपेक्षा के चलते यह नीति परवान नहीं चढ़ पाई। जाहिर है उद्यमियों की रुचि मैदानी क्षेत्रों देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर तक ही सीमित है। इसकी वजह भी है, उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड के मैदानी इलाकों तक आवाजाही सुगम है। मूलभूत सुविधाएं होने के कारण उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी और श्रमिक वर्ग के लिए भी ये क्षेत्र मुफीद हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट पर गौर करें तो पहाड़ों से पलायन एक बड़ा कारण रोजगार ही है। रोजी-रोटी की तलाश में देश के बड़े शहरों का रुख करने वाले युवा फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। रोजगार के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का मयस्सर न हो पाना, गुणवत्तापरक शिक्षा की जरूरत, कुछ ऐसे कारक हैं, जिनके कारण गांव खाली होते जा रहे हैं।

> पहाड़ों में उद्योगों की स्थापना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। एक बार फिर इस दिशा में कवायद शुरू की गई है। उम्मीद है यह मुकाम तक पहुंचेगी

जाहिर है सरकार यदि उद्योगों को पहाड़ चढ़ाने में सफल रहती है तो पलायन की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ लैंड बैंक बनाना ही पर्याप्त नहीं है। जो भी उद्योग पहाड़ों में स्थापित हों उनके लिए वर्ष भर कच्चे माल की आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा वितरण के लिए सुगम आवागमन भी जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इन मुद्दों पर गौर कर पहाड़ में उद्योगों की राह आसान कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश

मानवीय पुलिसिंग की जरूरत

कानपुर में एक बुजुर्ग दंपती को मारपीट कर घर से निकाल देने वाले उनके बेटे-बहू को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जेल भेजकर उचित ही कड़ा सबक सिखाया है। बुजुर्ग दंपती की जुबानी बेटे-बहू की करतूतों को सुनकर व्यथित हुए पुलिस कमिश्नर असीम अरुण न सिर्फ उन्हें कार में बैठाकर उनके घर पहुंचे, बल्कि बेटे-बहू के कब्जे से उनके कमरे भी मुक्त कराए। उन्हें अपना मोबाइल फोन नंबर नोट कराते हुए जरूरत पर तुरंत फोन करने के लिए भी कहा। दुष्टता दिखाने वाले बेटे-बहू को अदालती आदेश पर तीन दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। यद्यपि कमिश्नर की संवेदनशीलता के बाद पुलिस जितनी सक्रिय दिख रही है, वह सात दिन पहले तक खामोश बैठी थी। चकेरी थाने में बेटे-बहू के खिलाफ दंपती की रिपोर्ट पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्पीड़न का क्रम नहीं थमने पर डीसीपी पूर्वी से भी शिकायत हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहरहाल पुलिस कमिश्नर ने दो महीने की प्रताड़ना को दो घंटे में खत्म करा दिया।

यूं तो बुजुर्ग माता-पिता के हितों के संरक्षण को लेकर कई कानून पहले से हैं, लेकिन राज्य विधि

कानपुर में एक प्रताड़ित बुजुर्ग दंपती को उनके घर ले जाते पुलिस कमिश्नर। फाइल

> कानून बुजुर्गों की लाठी तभी बन पाते हैं, जब कानपुर पुलिस कमिश्नर की तरह दूसरे अधिकारी भी उन्हें संवेदनशीलता से लेते हैं

आयोग ने सरकार को भेजी सिफारिश में कहा है कि जो बच्चे बुजुर्ग मां-बाप की सेवा नहीं करें, उन्हें संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाए। इसके लिए बुजुर्ग नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया है। वहीं कोरोना काल में बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कुछ प्रविधान किए गए हैं। हालांकि ऐसे कानून बुजुर्गों की लाठी तभी बन पाते हैं, जब कानपुर पुलिस कमिश्नर की तरह दूसरे अधिकारी भी उन्हें संवेदनशीलता से लेते हैं। यद्यपि मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस महानिदेशक तक मित्र-पुलिस बनने का अक्सर पाठ पढ़ाते रहते हैं। थाना स्तर की शिकायतें वहीं निपटाने पर जोर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं पा रहा। पिछले दिनों गोरखपुर के मुख्यमंत्री जनता दरबार में आईं शिकायतों में से आधी थाना स्तर की थीं। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, लेकिन कार्यशैली में व्यापक सुधार अपेक्षित ही है।

हरियाणा

समझें अपनों की पीड़ा

हरियाणा सरकार ने यह ठीक किया है कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को अगर अपने बेटे-बेटियों या आश्रितों को आरक्षण का लाभ दिलाना है तो उन्हें सरकार को शपथपत्र देकर बताना होगा कि वे क्रीमीलेयर में नहीं हैं। क्रीमीलेयर यानी आठ लाख रुपये वार्षिक आय। यद्यपि प्रदेश सरकार अब इसे 12 लाख रुपये करने की तैयारी में है। यदि आरक्षण पाने के लिए कोई आवेदन करता है और माता-पिता में से अगर कोई भी प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी का अधिकारी है तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा।

चूंकि सरकार को पता है कि इस तरह के शपथ पत्र कूटरचित भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए झूठे शपथपत्र पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत विधिक कार्रवाई भी की जाने का प्रविधान है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि जो लोग क्रीमीलेयर में हैं, वे स्वतः आरक्षण का लाभ लेने से परहेज करें। यह तो उनको स्वयं विचार करना चाहिए कि सक्षम और समर्थ होने के बाद भी वे अपने बच्चों को

जो लोग क्रीमीलेयर में हैं, उन्हें स्वतः आरक्षण का लाभ लेने से परहेज करना चाहिए। प्रतीकात्मक

> सच तो यही है कि जिन लोगों ने आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठाया है, वे अपने वर्ग के अगड़े बन गए हैं

आरक्षण का लाभ दिलाते हैं तो उन्हीं के वर्ग के जो वंचित परिवार हैं, उनके बच्चों को कभी आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं पाएगा। उनकी स्थिति सदैव वैसी ही बने रहेगी, जैसी है। सच तो यही है कि जिन लोगों ने इस व्यवस्था का लाभ उठाया, वे अपने वर्ग के अगड़े बन गए। अब वही पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसका लाभ ले रहे हैं। यदि इस पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो जो वास्तव में वंचित हैं, पिछड़े हैं, उनको तो आरक्षण का लाभ मिलने में सदियां लग जाएंगी। एक बात और, सरकार ने अभी तक क्रीमीलेयर की परिभाषा में आठ लाख रुपये वार्षिक आय तय कर रखी है, जिसे वह 12 लाख रुपये वार्षिक करने जा रही है, यानी एक लाख रुपये प्रतिमाह कमाने वाले व्यक्ति की संतानें आरक्षण का लाभ लेने में सक्षम होंगी। ऐसी स्थिति में तीन सौ रुपये की दिहाड़ी करने वाले मजदूर के बच्चे क्या आरक्षित वर्ग में एक लाख रुपये आय वाले परिवार के बच्चे के समान प्रदर्शन कर पाएंगे, इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है।

बिहार

तस्करों पर कार्रवाई से दूर होगा बालू का संकट

प्रदेश में बालू का संकट बना हुआ है। आमजन ही नहीं बड़े-बड़े बिल्डरों ने भी अपने प्रोजेक्ट को लंबित कर दिया है। सरकार बारिश के मौसम में बालू का खनन बंद करा देती है। तीन महीने तक स्टाक किए गए बालू को ही बिक्री के लिए दिया जाता है। इस साल बालू माफिया इतना ज्यादा हावी रहे कि सरकार को इनके खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई करनी पड़ रही है। इनसे मिलीभगत कर बालू की तस्करी कराने वाले दर्जनों सरकारी मुलाजिमों पर निलंबन और बर्खास्तगी की गाज गिर चुकी है। कार्रवाई की जद में दो आइपीएस भी हैं।

बहरहाल सरकार की कड़ी कार्रवाई से सरकारी मुलाजिम तो बालू माफिया से कन्नी काटने लगे हैं, परंतु रात के अंधेरे में बालू घाटों पर तस्कर आज भी काबिज हैं। रोजाना इनके अवैध बालू लदे ट्रक-ट्रैक्टर पकड़े जा रहे हैं। माफिया नावों से खनन करवा रहे हैं जिन्हें रोक पाने में पुलिस-प्रशासन इसलिए सक्षम नहीं हो पा रहा, क्योंकि रात के अंधेरे में होने वाले काले कारनामे की सूचना उन तक नहीं पहुंचती। खनन विभाग बालू माफिया पर और सख्ती की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक साथ दो स्तर पर कवायद शुरू होगी। विभाग अवैध खनन करने वालों की सूचनाएं लेने के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेगा और घाटों पर रात्रि प्रहरियों की तैनाती भी कराई जाएगी।

> बालू माफिया पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों का सहयोग लेना उचित है। इनकी पहचान अगर गुप्त रहती है तो एक बड़ा सूचना तंत्र तैयार हो सकता है

बालू सरकार की आय का बड़ा स्रोत भी है। इससे सालाना 1200 करोड़ रुपये का राजस्व सरकार को प्राप्त होता रहा है। इधर डेढ़ वर्षों में अवैध खनन तेजी से बढ़ा है। 24 जिलों में सरकारी बंदोबस्ती के आधार पर खनन होता था। परंतु 16 जिलों के घाटों पर बालू माफिया का काबिज होना हैरत की बात है। जब जनभागीदारी से माफिया पर अंकुश लगाने की योजना बन रही है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इसे अपनी सहूलियत मानें। आखिर सरकार की इस कवायद से सस्ते दर पर बालू हमें ही मिलने का रास्ता साफ होगा। जब यह काम गुपचुप तरीके से करते हुए पुलिस और खनन विभाग को सूचना देनी है कि रात्रि में घाटों पर अवैध खनन हो रहा है तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह जरूर है कि खनन विभाग और पुलिस अफसर निगरानी विभाग की तर्ज पर ईमानदारी से काम करें। इससे अवैध बालू खनन पर रोक लगेगी। जब बालू खनन का काम सुचारू रूप से चलने लगेगा तो इसका संकट दूर होगा और फिर इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे इसकी कीमत में तर्कसंगत होगी। यह सबके हित में है।

सात साल के बच्चे के कारण बंगाल में टला बड़ा ट्रेन हादसा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

सात साल के एक बच्चे की सूझबूझ के कारण बंगाल में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। दरअसल, रेललाइन में पड़ी दरार को देखकर उसने तुरंत मां को खबर दी तो मां ने भी बिना समय गंवाए आसपास के लोगों के साथ मिलकर ट्रेन को रुकवा लिया। अब रेलवे बच्चे को सम्मानित करेगा।

जानकारी के अनुसार मुकुंदपुर का रहने वाला दीप नस्कर सोमवार दोपहर अपने घर के सामने रेल लाइन के किनारे खेल रहा था। अचानक उसकी नजर रेललाइन में पड़ी दरार पर गई। खतरे को भांपकर दीप तुरंत घर की तरफ भागा और अपनी मां सोनाली नस्कर को सूचना दी। सोनाली ने भी देर न करते हुए आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कई लोग लाल कपड़े लेकर रेल लाइन पर आ गए। कुछ देर बाद वहां से सियालदहगामी कैनिंग स्टाफ स्पेशल गुजरने वाली थी। ट्रेन को आता देख सभी लाल कपड़ा हाथ में लेकर हिलाने लगे। ट्रेन चालक ने दूर से लोगों को लाल कपड़ा हिलाते देख लिया और ट्रेन रोक दी। ट्रेन रुकने के बाद विद्याधरपुर बुकिंग सुपरवाइजर से संपर्क किया गया। वहां से इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी पहुंचे और लाइन की मरम्मत शुरू की। 40 मिनट चली मरम्मत के बाद ट्रेन को रवाना किया गया।

सियालदह के डीआरएम एसपी सिंह ने बताया कि जिस रेल लाइन में दरार पड़ी थी, वह वेल्डिंग की हुई थी, जो खुल गई थी। सात साल के बच्चे की वजह से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। मैंने रेलवे कर्मचारियों से उस बच्चे के परिवार से संपर्क करने को कहा है। उसने बहुत बड़ा काम किया है। उसे 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। दीप सही मायने में सम्मान का हकदार है। हमें उम्मीद है कि इस घटना से दूसरे बच्चे व आम लोग भी प्रेरित होंगे।

बच्चे का उत्साह बढ़ाने के लिए रेलवे की तरफ से कदम उठाया जाएगा। महज दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले छोटे से बच्चे की समझ की सभी दाद दे रहे हैं।

शाबाश दीप
- रेललाइन में पड़ी दरार को देखकर तुरंत मां को दी खबर
- मां ने आस-पास के लोगों के साथ मिलकर ट्रेन को रोका

सम्मान का हकदार दीप नस्कर। इंटरनेट मीडिया

मप्र में मिलावटी शराब से मौत पर दोषी को फांसी के प्रविधान पर कैबिनेट की मुहर

नईदुनिया, भोपाल

- विस के मानसून सत्र में आबकारी अधिनियम में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी सरकार
- जिम्मेदार पाए जाने पर आबकारी कर्मचारी को तीन साल की होगी सजा

मध्य प्रदेश में मिलावटी (जहरीली) शराब के मामले और इससे मौत की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए शिवराज सरकार ने आबकारी अधिनियम में सजा के प्रविधान को कठोर करने का निर्णय लिया है। अब मिलावटी या जहरीली शराब से मौत होने पर दोषी को फांसी और 25 लाख रुपये जुर्माना की सजा हो सकेगी। ऐसी शराब से शारीरिक क्षति पहुंचने की स्थिति में 10 से लेकर 14 साल का कारावास और न्यूनतम दस लाख रुपये जुर्माना का प्रविधान किया गया है। इन्हें लागू करने के लिए सरकार विधानसभा के नौ अगस्त से प्रस्तावित मानसून सत्र में आबकारी अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में संशोधन विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है।

राज्य सरकार के प्रवक्ता व गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अवैध शराब से जुड़े ऐसे अपराध, जिनके बारे में अधिनियम में उल्लेख नहीं है, उनमें जुर्माने की राशि एक हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार की गई है। कारावास की अवधि छह माह ही रहेगी। मादक द्रव्य में हानिकारक, रंगीन व अन्य तत्व मिलाने पर जुर्माना की राशि तीन सौ रुपये से लेकर दो हजार तक को बढ़ाकर न्यूनतम तीन हजार से अधिकतम दो लाख रुपये प्रस्तावित की गई है। शराब में मिलावट करने और उसके सेवन से शारीरिक क्षति या मृत्यु होने संबंधी अपराध में शामिल होने पर पहली बार और बार-बार इस तरह के काम को अंजाम देने के दोषी को न्यूनतम छह माह से लेकर फांसी (मृत्युदंड) तक की सजा हो सकती है।

विधानसभा में पेश होगा विधेयक। फाइल फोटो

पंजाब में मृत्युदंड, बिहार में उम्रकैद का प्रविधान

पंजाब में भी मिलावटी शराब बेचे जाने पर मृत्युदंड का प्रविधान है। बिहार सरकार ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की हुई है। इसके बावजूद वहां कोई शराब बेचता है और उससे जनहानि होती है तो अधिकतम उम्र कैद की सजा है।

अब ये होंगे प्रविधान

- मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित मदिरा सेवन से शारीरिक क्षति पर पहली बार अपराध करने वाले को न्यूनतम चार माह और अधिकतम चार साल तक कारावास की जगह न्यूनतम दो साल और अधिकतम आठ साल का कारावास, न्यूनतम दो लाख रुपये जुर्माना। दूसरी बार या बार-बार अपराध करने पर न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम छह वर्ष का कारावास के स्थान पर न्यूनतम दस वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक कारावास, न्यूनतम दस लाख रुपये तक जुर्माना।
- मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त अपमिश्रित मदिरा सेवन से मृत्यु होने पर पहली बार अपराध करने वाले को न्यूनतम दो वर्ष और अधिकतम दस साल तक के कारावास के स्थान पर न्यूनतम दस वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास, न्यूनतम पांच लाख रुपये जुर्माना। दूसरी बार या बार-बार अपराध करने पर आजीवन कारावास या न्यूनतम पांच वर्ष से अधिक दस वर्ष तक के कारावास के स्थान पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड, न्यूनतम 25 लाख रुपये जुर्माना।

श्रीमद्भगवद्गीता पर अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल के पहले अंक का विमोचन
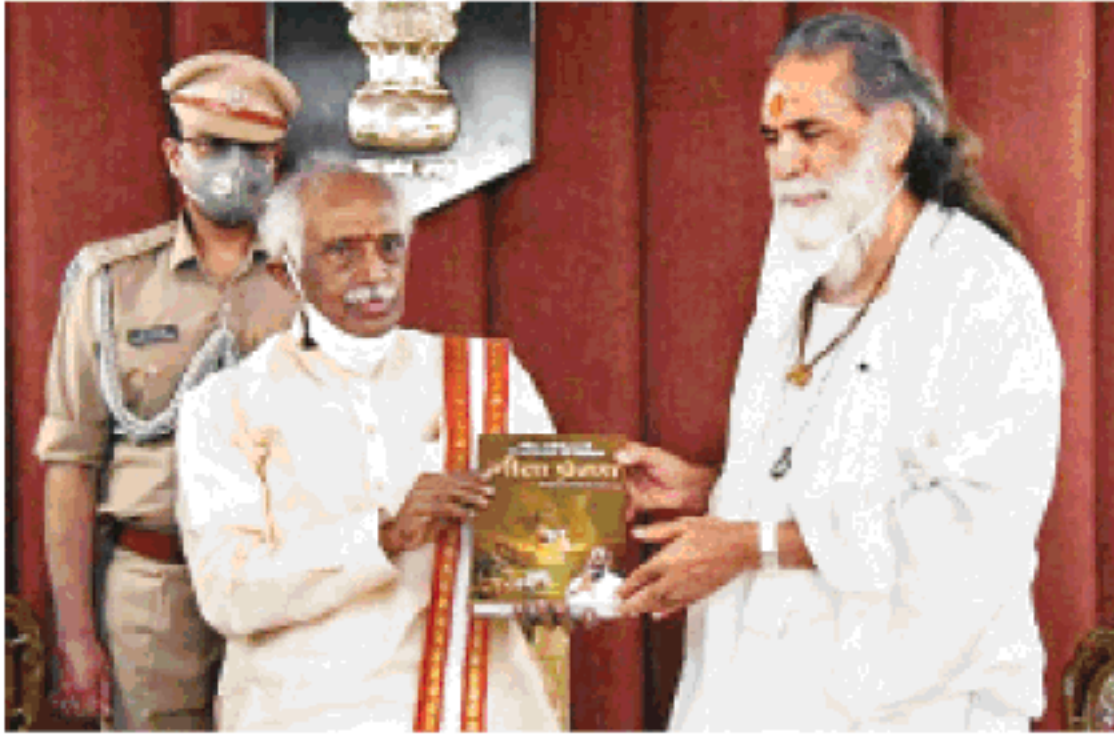
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को श्रीमद्भगवद्गीता भेंट करते स्वामी ज्ञानानंद महाराज। राजभवन

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता ने कोरोना काल में भी मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास व मनोबल बढ़ा कर सिद्ध कर दिया है कि वह मात्र एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। मंगलवार को राजभवन में जियो गीता व गुरुग्राम विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल के प्रथम अंक व काफी टेबल बुक के लोकार्पण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मैं खुद प्रतिदिन गीता पढ़ता हूं, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता। उन्होंने कहा कि वर्ष 1976 में जब मैं जेल में था, तब भी गीता मेरे विश्वास को बरकरार रखने में कारगर सिद्ध हुई थी। इस मौके पर उन्होंने जर्नल के पहले अंक और काफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस मौके पर राज्यपाल ने श्रीमद्भगवद्गीता के प्रचार-प्रसार के लिए जियो गीता संस्थान व स्वामी ज्ञानानंद का विशेष रूप से धन्यवाद किया। जियो गीता के माध्यम से विश्वभर में लोग गीता के उपदेश को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे विश्व में शांति-सद्भाव व भाईचारे का माहौल कायम करने में सफलता मिली है। समारोह में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डा. मारकंडे आहूजा सहित कई हस्तियां मौजूद थीं।

श्रद्धा का महासावन

ऊर्जा के स्रोत हैं शिव

शिव सृष्टि के रचयिता हैं। निराकार हैं, परमदयालु हैं और प्रकाश बिंदु हैं। इस प्रकाश बिंदु से निकलने वाली ऊर्जा से ही संसार चलायमान है। हम शिव के उत्सव को ही शिवरात्रि कहते हैं। आज मनुष्य सांसारिक सुख व शांति के लिए भटक रहा है और उसकी प्राप्ति न होने पर परेशान हो रहा है। यदि वह शिवरात्रि का सत्य परिचय जान ले तो समाज से विषमता दूर हो जाएगी, लेकिन सही रास्ते की जानकारी न होने पर भी व्यक्ति अनेक मतों में उलझता है। व्यक्ति ऊर्जाहीन, तेजहीन हो रहा है, लेकिन भगवान शिव की कृपा से समस्त ऊर्जाओं की प्राप्ति हो सकती है। परमपिता परमात्मा शिव अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न देखना चाहते हैं। शिव का संदेश है कि दूसरों को परेशान करके कोई भी व्यक्ति स्वयं प्रसन्न नहीं रह सकता। शिव मानव को पवित्र होने का संदेश दे रहे हैं। जब-जब मानव परेशान होता है, तब-तब शिव जीवों की परेशानी को हरते हैं। वह प्रजापिता ब्रह्मा को इस धरती पर भटक रहे मानव को प्रेरित करने के लिए भेजते हैं। वह इस धरा पर मनुष्य की आत्मिक ज्योति जगाते हैं और सहज ज्ञान व राजयोग द्वारा दुखों से छुड़ाकर मुक्ति प्रदान करते हैं। शिव में ध्यान लगाने से हम दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता से मन-बुद्धि बल से जुड़ जाते हैं, जिससे वह हमें सही विवेक प्रदान करती है।

ब्रह्माकुमारी उषा
संचालिका, प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विवि केंद्र, फरीदाबाद

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

उमस खत्म कर भरपूर आक्सीजन दे सकेंगी घर की दीवारें

जागरण विशेष

बीएचयू के विज्ञानियों ने बनाई हवा में मौजूद नमी सोख लेने वाली जेली, पेटेंट की मंजूरी मिली

हिमांशु अस्थाना • वाराणसी

ज्यादा समय नहीं गुजरा जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने हमें अपने दफ्तरों और घरों का एयरकंडीशनर (एसी) बंद करने पर मजबूर कर दिया था। शुद्ध आक्सीजन का महत्व भी हमें तभी समझ में आया। ऐसे समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के विज्ञानियों को एक ऐसी जेली (इलेक्ट्रोलाइट) बनाने में सफलता मिली है जो बिजली की बेहद कम खपत में न सिर्फ भीषण गर्मी और उमस से निजात दिलाएगी बल्कि कमरे में आक्सीजन की आपूर्ति भी बढ़ा देगी।

भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत टेक्नोलाजी इंफारमेशन फारकास्टिंग एंड एसेसमेंट कौंसिल ने गत 22 जुलाई को इसके पेटेंट को मंजूरी दी है। इस टेक्नोलाजी के जमीन पर उतरने में अभी थोड़ा समय है, लेकिन बीएचयू ने पर्यावरण के लिए नुकसानदेह और अत्यधिक बिजली खर्च करने वाले एसी पर निर्भरता कम करने के साथ अधिक आक्सीजन सुनिश्चित कराने की राह तो दिखाई ही है।

चला स्टार्च और नमक के घोल का जादू : गर्मी के दिनों में हवा जितनी अधिक नम होती है, उमस उतनी ही अधिक बेचैन करने वाली होती है। बीएचयू के महिला महाविद्यालय की भौतिक विज्ञानी प्रो. नीलम श्रीवास्तव की अगुआई में शोध टीम ने स्टार्च (स्वाद व गंध रहित पाली सैकेराइड कार्बोहाइड्रेट) और नमक (सोडियम आयोडाइड पर क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में कोई एक) को घोलकर जेली तैयार की जो हवा में मौजूद नमी को सोख लेती है। स्टार्च के प्रमुख स्रोत आलू, गेहूं, मक्का, अरारोट, ब्राउन राइस आदि होते हैं।

सीलन से भी मिलेगी मुक्ति: प्रो. नीलम ने पाया कि इलेक्ट्रोड (धातु प्लेट या छड़) और विद्युत प्रवाह के लिए 0.2 वोल्ट का उपकरण लगाने पर जेली में अवशोषित पानी हाइड्रोजन और आक्सीजन में टूट जाता है। इससे कमरे में आक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और वातावरण में नमी खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रोड लगाकर जेली को दीवार पर लगाने से आक्सीजन बढ़ने के साथ उमस से भी राहत मिलेगी। दीवारों पर लगने वाली सीलन से भी मुक्ति मिलेगी। इससे दीवार के पेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लंबे समय तक टिकाऊ होगी और एसी की तुलना में बेहद सस्ती होगी।

लैब में जार में तैयार स्टार्च और नमक का घोल • जागरण

रूटीन प्रयोग के दौरान सूझा यह विचार

रूटीन प्रयोग के दौरान प्रो. नीलम के शोध छात्र मानिंद्र ने देखा कि उच्च आर्द्रता वाले डेसीकेटर (शीशे का पात्र) से निकालने के बाद जेली गीली हो गई है। बाहर निकालने के बाद 24 घंटे में जेली सूख गई। डेसीकेटर से भी नमी खत्म हो गई। प्रो. नीलम ने पाया कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की क्रिया से डेसीकेटर की नमी जेली में आकर खत्म हो जा रही है। शोध टीम में डा. मानिंद्र कुमार, डा. तुहिना तिवारी, डा. माधवी यादव और डा. दीप्ति यादव शामिल हैं।

प्रो. नीलम श्रीवास्तव

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

हरियाणा के शहरी निकाय निदेशालय को ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इसकी मदद से 18 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मानचित्र तैयार किए जाएंगे।

एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को बताया गया कि मंत्रालय ने मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम-2021 से निदेशालय को एक साल के लिए सशर्त छूट दी है। सरकार ने घरों में जलापूर्ति, सीवर व शहरी परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास का खाका खींचा है। इन सुविधाओं के विकास से सभी वर्गों, खासकर गरीब व वंचित तबके के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। मंत्रालय के अनुसार, 'यह छूट अमृत शहरों के विकास के लिए डाटा संग्रह, मैपिंग व वेब आधारित जीआइएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) प्लेटफार्म तथा हिसार, पंचकुला व अंबाला में संपत्ति कर सर्वे के लिए दी गई है।' जिन 18 शहरों की मैपिंग के लिए इजाजत दी गई है, उनमें अंबाला, बहादुरगढ़, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, थानेसर व यमुनानगर शामिल हैं।

2020 में अमेरिका में दो करोड़ बंदूकें बेची गई थीं। यह 2019 की तुलना में 58 फीसद ज्यादा है। खरीदारों में 84 लाख ने पहली बार बंदूक खरीदी। कुल खरीदारों में से 40 फीसद महिलाएं थीं।

भारतीय अमेरिकी बच्ची नताशा दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा

- 11 साल की पेरी ने अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ विवि की परीक्षा एसएटी व एसीटी में बेहतरीन प्रदर्शन किया
- जान्स हापकिन्स सेंटर फार टैलेंटेड यूथ टैलेंट (वीटीवाई) सर्च में भी लाई 90 परसेंटाइल

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका में रहने वाली 11 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी बच्ची नताशा पेरी को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक माना गया है। एसएटी और एसीटी मानकीकृत टेस्ट में असाधारण प्रदर्शन के आधार पर ये तय किया गया है। 'स्कालैस्टिक असेसमेंट टेस्ट' (एसएटी) और 'अमेरिकन कालेज टेस्टिंग' (एसीटी) दोनों ही मानकीकृत टेस्ट हैं, जिनके जरिये कालेज ये निर्धारित करते हैं कि किसी छात्र को एडमिशन दिया जाना है या नहीं। कुछ मामलों में कंपनियां और विश्वविद्यालय भी इन अंकों के जरिये छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं।

एक बयान में कहा गया है कि न्यूजर्सी के थेल्मा एल सैंडमीयर एलीमेंट्री स्कूल की छात्रा नताशा पेरी को एसएटी, एसीटी या जान्स हापकिन्स सेंटर फार टैलेंटेड यूथ टैलेंट (वीटीवाई) सर्च के हिस्से के रूप में लिए गए समान टेस्ट में उसके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। वह 84 देशों के लगभग 19,000 छात्रों में से एक थी, जिसने 2020-21 टैलेंट सर्च ईयर में सीटीवाई में हिस्सा लिया। सीटीवाई दुनियाभर के प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करने और उनकी वास्तविक अकेडेमिक क्षमताओं का पता लगाने के लिए ग्रेड-स्तरीय टेस्टिंग का इस्तेमाल करता है।

कमाल की प्रतिभा : 11 वर्षीय भारतीय अमेरिकी नताशा पेरी (फाइल फोटो इंटरनेट मीडिया)

अच्छा करने को प्रेरित करेगा अवार्ड : पेरी

नताशा पेरी ने 2021 के बसंत में जान्स हापकिन्स टैलेंट सर्च टेस्ट दिया। इस दौरान वह कक्षा पांच में थी। मौखिक और गुणात्मक क्षेत्र में उसके नतीजे कक्षा आठ के स्तर पर 90 परसेंटाइल के साथ थे। इस तरह पेरी ने जान हापकिन्स वीटीवाई में 'हाई आनर्स अवार्ड' के लिए रास्ता बनाया. पेरी ने कहा कि ये मुझे और अच्छी तरह करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि डूडलिंग और जेआरआर टाल्किन के उपन्यास को पढ़ना उसके लिए काम कर सकता है। जान हापकिन्स नीति के रूप में अवार्ड हासिल करने वाले की जानकारी को उम्र या नस्ल के आधार पर विभाजित नहीं किया जाता है। ऐसा करना अभिभावकों के हाथ में होता है।

सीटीवाई में सालाना होते हैं 15.5 हजार से अधिक नामांकन

सीटीवाई टैलेंट सर्च प्रतिभागियों में से 20 फीसद से भी कम सीटीवाई हाई आनर्स अवार्ड्स के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। अवार्ड हासिल करने वाले लोग सीटीवाई के आनलाइन व गर्मियों के कार्यक्रम के लिए भी क्वालिफाई हुए हैं। इसके जरिये प्रतिभाशाली छात्र दुनियाभर के अन्य उज्जवल छात्रों के साथ मिलकर सीखने का काम करते हैं। सीटीवाई आनलाइन कार्यक्रम पाठ्यक्रमों में हर साल 15,500 से अधिक नामांकन होते हैं। इसके अलावा अमेरिका और हांगकांग में लगभग 20 साइटों पर प्रतिभाशाली छात्रों के लिए सीटीवाई के इन-पर्सन समर प्रोग्राम की पेशकश की जाती है।

गुलाम कश्मीर में चुनावी धांधली पर विपक्ष करेगा देशव्यापी प्रदर्शन

- नवाज शरीफ बोले, इमरान की पार्टी की संदिग्ध जीत की जल्द खुलेगी पोल
- भारत ने कहा, अवैध कब्जे वाली जमीन पर चुनाव मात्र नाटक

इस्लामाबाद, एएनआइ : गुलाम कश्मीर (गिलगिट-बाल्टिस्तान) के प्रांतीय चुनावों पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि यह पूरी चुनावी प्रक्रिया और इमरान की पार्टी की जीत संदिग्ध है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनकी पार्टी के छह विजयी प्रत्याशियों को पांच लाख वोट मिले हैं। वहीं इमरान की पार्टी के जीते सभी 25 प्रत्याशियों को कुल छह लाख वोट मिले। ऐसी स्थिति में इस जीत पर कोई कैसे विश्वास करेगा। जल्द ही यह धांधली पूरी तरह जनता के सामने आ जाएगी। नवाज शरीफ की पार्टी ने चुनाव में धांधली के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन का फैसला किया है।

इस बीच भारत ने गुलाम कश्मीर के चुनावों को नाटक बताया है। भारत ने सवाल किया है कि जब कश्मीर की भूमि पर पाक का अवैध कब्जा है, ऐसी स्थिति में वहां चुनाव कराने की क्या वैधता है। भारत ने पाकिस्तान से इस अवैध कब्जे को तुरंत खाली करने के लिए कहा है।

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाले कश्मीर के क्षेत्र में चुनाव कराए थे। इसमें पुलिस, सेना और चुनाव आयोग ने मिलकर धांधली की और इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने जमकर हिंसा और अराजकता का माहौल बना दिया। चुनावों में सैकड़ों लोग घायल हो हुए। जनता ने सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विपक्षी दल के एक नेता से भारत से मदद लेने की बात तक कही है।

अफगान युद्ध में फिर कूदा अमेरिका, तालिबान के ठिकानों पर बरसाए बम

सत्ता संघर्ष ▶ 24 घंटे में 375 तालिबान आतंकी किए ढेर

हेरात, कंधार, लश्कर गाह में चल रहा भीषण संघर्ष

काबुल, एएनआइ : अफगानिस्तान में प्रांतीय राजधानियों पर कब्जे को लेकर जंग और तेज हो रही है। हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्कर गाह में घुस रहे तालिबान आतंकियों को रोकने के लिए अमेरिका ने जमकर बम बरसाए। सेना ने ऐसे सभी तालिबान ठिकानों को निशाना बनाया, जहां से वे शहरों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अफगान सेना ने भी पूरी ताकत लगा दी है। सैकड़ों तालिबान आतंकियों को मार गिराने का सरकार ने दावा किया है।

सरकार के अनुसार सेना ने आतंकियों के खिलाफ कंधार, हेरात, हेलमंद, जौजान, बल्ख, उरुजगन, कपिसा आदि प्रांतों में अभियान को जारी रखते हुए कई स्थानों पर बढ़त बनाई है। सेना ने गत 24 घंटे में 375 तालिबान आतंकियों को मार दिया और 193 आतंकी घायल हुए हैं।

लश्कर गाह में तालिबान आतंकियों के घुसने से पहले अमेरिका ने कई हवाई हमले किए, जिसमें 40 आतंकी मारे गए। अमेरिका ने ऐसे सभी स्थानों पर बम बरसाए, जहां तालिबान आतंकी अफगान सेना पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे। हवाई हमलों और जमीन पर हो रही लड़ाई में लश्कर गाह समेत अन्य स्थानों पर 75 से ज्यादा आतंकी मारे गए, 22 घायल हुए हैं। मृतकों में तालिबान के तीन शीर्ष आतंकी भी हैं। कंधार में भी संघर्ष जारी है। यहां आतंकियों ने 15 नागरिकों की हत्या कर दी, 120 से ज्यादा घायल हुए हैं। हेरात में भी तीन नागरिकों की हत्या हो गई है।

अफगानिस्तान के हेलमंद प्रांत की राजधानी लश्कर गाह में मंगलवार को तालिबान के खिलाफ मोर्चा संभालता अफगान सुरक्षाकर्मी। एपी

संयुक्त राष्ट्र ने कहा, लश्करगाह में 40 नागरिकों की हत्या : एएनआइ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि लश्करगाह में चल रही लड़ाई में गत 24 घंटे में 40 नागरिकों की हत्या कर दी गई। यहां 118 लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जंग को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। नागरिकों की हत्या को रोकना जरूरी हो गया है।

अफगान सेना में भर्ती के लिए लड़कियों में भी जोश : एएनआइ के अनुसार अफगान सेना में भर्ती के लिए युवाओं में जबर्दस्त जोश है। काबुल के राष्ट्रीय मिलिट्री अकादमी में चल रही भर्ती प्रक्रिया में पांच हजार से ज्यादा युवा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लड़कों के साथ ही लड़कियां भी भर्ती के लिए उतने ही उत्साह से शामिल हो रही हैं। यहां सेना के चीफ आफ स्टाफ जनरल वली मोहम्मद अहमदजई भी मौजूद हैं। उन्होंने हिंसाग्रस्त देश की सेवा में आने वाले युवाओं के जोश की सराहना की।

अफगानिस्तान को तबाही से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र कदम उठाए : आइएएनएस के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान में राजदूत रहे काई आइड व तदामिची यामामोटो ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र को अफगान युद्ध रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। यही वह समय है, जब अफगान नागरिकों को तबाही से बचाया जा सकता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक बुलानी चाहिए।

अफगान सहयोगियों के लिए ब्लिंकन ने प्रायर्टी 2 योजना शुरू की : रायटर के अनुसार, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगान सहयोगियों के लिए सोमवार को प्रायर्टी 2 योजना की घोषणा की। इसके तहत वीजा बनाने में श्रेणियों का विस्तार किया गया है। पिछले 13 वर्षों में अफगानिस्तान से 70 हजार अफगान सहयोगियों को विशेष प्रवासी वीजा दिए गए हैं। प्रायर्टी 2 योजना में 50 हजार से ज्यादा लोगों के वीजा बनने की संभावना है

हेरात में सड़कों पर उतरी जनता, लगे पाकिस्तान के खिलाफ नारे

काबुल, एएनआइ : हेरात शहर में पिछले छह दिनों से भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। तालिबान आतंकी शहर के करीब आकर लड़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ही यहां की जनता भी सड़कों पर उतर आई है। जनता आतंकियों के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। यहां तालिबान आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सेना की अतिरिक्त टुकड़ी भेजी गई हैं। अफगानिस्तान के उप राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट किया- हेरात में आतंकियों के खिलाफ जनता भी सड़क पर उतर आई है। आतंकियों के साथ ही जनता पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही है। यहां नारे लग रहे हैं, 'अल्लाह पाकिस्तान का बनाया हुआ नहीं है।' हेरात में स्थिति ऐसी है कि हर कोई नागरिक अपने घर से बाहर है। कोई सड़कों पर उतरा हुआ है तो कोई छत पर डटा है। अफगान सेनाओं के समर्थन में नारे लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है।

अमेरिका और ब्रिटेन ने तालिबान पर लगाए युद्ध अपराध के आरोप : रायटर के अनुसार, अमेरिका और ब्रिटेन ने तालिबान पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। दोनों देशों के काबुल स्थित दूतावास ने ट्वीट किया है कि तालिबान निर्दोष नागरिकों की हत्या कर रहा है, जबकि तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने इसका खंडन किया है।

पाक के हित में अफगानिस्तान का बर्बाद होना जरूरी : पाकिस्तान के पूर्व आइएसआइ प्रमुख हामिद गुल के पुत्र अब्दुल्लाह गुल ने दक्षिण वजीरिस्तान में एक सभा में कहा, अफगानिस्तान को बर्बाद कर देना चाहिए। यह देश भविष्य में पाक से मुकाबला करने के काबिल न रहे।

पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक कदम उठाए : तिरुमूर्ति

कड़ा रुख

- सुरक्षा परिषद में अध्यक्ष भारत ने दिए पड़ोसी देश को सख्त संदेश
- तिरुमूर्ति ने कहा-सामान्य संबंधों के लिए वातावरण पूरी तरह आतंक मुक्त हो

संयुक्त राष्ट्र, आइएएनएस : संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर दोनों देशों के बीच पड़ोसी वाले संबंध चाहता है तो उसे अपने नियंत्रण वाली जमीन का किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं करने के प्रामाणिक कदम उठाने होंगे।

एएनआइ के मुताबिक तिरुमूर्ति ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत शांतिपूर्ण और सामान्य संबंधों की इच्छा रखता है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब वातावरण पूरी तरह से आतंकवाद से मुक्त हो। पाकिस्तान शांति चाहता है या हिंसा यह उस पर ही निर्भर करता है। पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में कोई भी आतंकी गतिविधि नहीं होने देने के लिए विश्वसनीय और सत्यापित करने योग्य कदम उठाने होंगे।

सोमवार को सुरक्षा परिषद की पहली बार अध्यक्षता करते हुए तिरुमूर्ति ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी कथनी और करनी को साबित करना होगा। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बदलाव भारतीय संविधान के दायरे में आते हैं। और यह फैसला भारत की संसद का संवैधानिक अधिकार है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

टीएस तिरुमूर्ति। फाइल/ इंटरनेट मीडिया

उन्होंने कहा कि भारत हर हाल में आतंकवाद पर ही ध्यान केंद्रित करेगा। वह सुरक्षा परिषद में अपनी अध्यक्षता की अवधि में आतंकवाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि भारत की चिंता सिर्फ सीमा पार आतंकवाद की नहीं है बल्कि इस बात की भी है कि आतंकियों के हाथों में अब अत्याधुनिक हथियार और युद्ध प्रणालियां पहुंच चुकी हैं। साथ ही आतंकवाद का वित्त पोषण भी बेहद गंभीर समस्या है और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए इसे सिरे से खत्म करना होगा। उन्होंने पड़ोसी देश म्यांमार में भी लोकतंत्र हटाकर सैन्य शासन लगाए जाने पर चिंता जताई और कहा कि भारत म्यांमार में और अस्थिरता जारी रहने देने के पक्ष में नहीं है।

अमेरिका ने 24 रूसी राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका ने 24 रूसी राजनयिकों को वीजा अवधि समाप्त हो जाने के कारण 3 सितंबर तक देश छोड़ने के लिए कहा है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव के दौरान इस आदेश पर रूसी राजदूत अनातोली एंतोनोव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ये सभी राजनयिक महज इसलिए देश छोड़ देंगे, क्योंकि अमेरिका ने रूस के लिए वीजा नियम कड़े कर दिए हैं।

उन्होंने कहा, हमें 24 राजनयिकों की सूची मिली है। हमारे लिए अब वीजा की अवधि तीन साल कर दी गई है। ऐसा नियम अन्य देशों के लिए नहीं है।

रूसी राजदूत ने यह बात वाशिंगटन में एक मीडिया साक्षात्कार में कही। वहीं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एंतोनोव के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बताई गई जानकारी सही नहीं है। रूसी नागरिकों के लिए वीजा की अवधि तीन साल कोई नई बात नहीं है। वीजा की अवधि समाप्त हो जाने पर इसको बढ़ाने के लिए आवेदन देना होता है या देश छोड़कर जाना होता है। इससे पहले अप्रैल माह में रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावासों में रूस या अन्य देशों के नागरिकों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

विमानों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध कल से हटाएगा यूएई

दुबई, रायटर : संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) गुरुवार से भारत व पाकिस्तान समेत अन्य सभी जगहों के लिए विमानों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटाने जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा एवं संकट प्रबंधन प्राधिकार (एनसीईएमए) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारत व पाकिस्तान अमीरात, एतिहाद एयरवेज एवं अन्य यूएई कैरियर फ्लाईदुबई और एयर अरबिया के लिए महत्वपूर्ण बाजार हैं। एक बड़े अंतरराष्ट्रीय यात्रा केंद्र खाड़ी देश ने कोरोना के कारण इस साल कई दक्षिण एशियाई और अफ्रीकन देशों से यात्रियों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

'दूर-दूर तक होगा अफगान संकट का असर'

- ब्रिक्स के एकेडमिक फोरम में विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में विस्तार की मांग उठाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने मंगलवार को आगाह किया कि अफगानिस्तान के संकट का असर ना केवल पड़ोस पर बल्कि उससे बाहर तक होगा। साथ ही कहा कि बड़े पैमाने पर हिंसा, डराने-धमकाने या छिपे हुए एजेंडे के जरिए 21वीं सदी में वैधता प्राप्त नहीं की जा सकती।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के शैक्षणिक मंच के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया कि अफगानिस्तान की जंग ने आतंकवाद की चुनौती बढ़ा दी है। सभी हितधारकों को इससे निपटने के लिए स्पष्ट, समन्वित और एक समान रुख अपनाना होगा। कहा कि ढांचागत जड़ता, असमान संसाधन जैसे मुद्दों ने बहुपक्षीय संस्थानों को नुकसान पहुंचाया है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ खाई पैदा होती है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ अंतराल में आतंकवाद पनपता है। इसकी नर्सरी संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में है जो दुर्भावनापूर्ण मंसूबे वाली ताकतों द्वारा कट्टरवाद को प्रश्रय देने से और फलती फूलती है। उन्होंने कहा कि आज अफगानिस्तान में हम संक्रमण काल देख रहे हैं। वहां छिड़ी जंग ने फिर से वहां के लोगों के लिए चुनौतियां पैदा कर दी हैं। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ना केवल अफगानिस्तान के पड़ोस में बल्कि उससे बाहर भी इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। सभी पक्षों को इन चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 21वीं सदी में बड़े पैमाने पर हिंसा, डराने-धमकाने या छिपे हुए एजेंडा के जरिए वैधता प्राप्त नहीं की जा सकती। प्रतिनिधित्व, समावेश, शांति और स्थिरता का अटूट संबंध है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू होने के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान की हिंसा बढ़ गई है। भारत अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता में बड़ा हितधारक है। देश में सहायता और अन्य कार्यक्रमों में भारत तीन अरब डालर से ज्यादा का निवेश कर चुका है। भारत एक राष्ट्रीय शांति और सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है जो अफगान-नेतृत्व वाली, अफगान-स्वामित्व वाली और अफगान-नियंत्रित हो। जयशंकर ने बहुपक्षीय निकायों में सुधार का आह्वान करते हुए कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार को आगे नहीं टाला जा सकता। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का विस्तार करना जरूरी है, लेकिन यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। ब्रिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक नया विकास ढांचा तैयार करने के लिए कदम उठाने की जरूरत थी, जिसके तहत इसकी शुरुआत की गई।

चीन में भारतीय छात्र की हत्या में एक गिरफ्तार

बीजिंग, प्रेट्र : चीन में अध्ययन करने गए भारतीय छात्र अमन नागसेन की मौत का मामला खुल गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार, अमन की हत्या की गई थी। इस हत्या में शामिल एक अन्य विदेशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्यारोपी किस देश का है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

बिहार के गया जिले का निवासी 20 वर्षीय अमन तियानजिन फारेन स्टडीज यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कर रहा था। वह कोरोना महामारी के दौरान भी चीन में ही रुक गया था। 29 जुलाई को उसका शव कमरे में पड़ा मिला।

चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हत्याभियुक्त से पूछताछ चल रही है। भारतीय दूतावास को भी जानकारी दे दी गई है। मंगलवार को पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम कराया है। बीजिंग से तियानजिन सौ किमी दूर है। दूतावास के अधिकारी तियानजिन गए हैं।

भारत को हार्पून मिसाइल बेचने पर अमेरिका ने लगाई मुहर

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने भारत को हार्पून मिसाइल और इससे जुड़े उपकरण बेचने पर मुहर लगा दी है। इसकी अनुमानित कीमत 8.2 करोड़ डालर (करीब 600 करोड़ रुपये) है। अमेरिका ने कहा कि इस फैसले से द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारी भी बढ़ेगी। यह माना जा रहा है कि इस एंटी-शिप मिसाइल के मिलने से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी।

अमेरिकी सरकार के बयान के अनुसार, रक्षा विभाग पेंटागन की डिफेंस सिक्यूरिटी कोआपरेशन एजेंसी (डीएससीए) ने इस बिक्री के बारे में सोमवार को संसद को अधिसूचित किया। डीएससीए के अनुसार, भारत सरकार ने एक हार्पून ज्वाइंट कामन सेट की खरीद के लिए आग्रह किया था। इस प्रस्तावित खरीद से भारत-अमेरिका रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी और अहम रक्षा साझेदार की सुरक्षा बेहतर होगी। हिंद-प्रशांत और दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति के लिए यह महत्वपूर्ण है। जबकि अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इस प्रस्तावित खरीद से मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने में भारत की क्षमता बढ़ेगी।

इस एंटी-शिप मिसाइल से नौसेना की बढ़ेगी मारक क्षमता

फाइल फोटो/इंटरनेट मीडिया

हार्पून मिसाइल की खासियत

- हार्पून एक एंटी-शिप मिसाइल है, इसकी पहली तैनाती 1977 में हुई थी
- रडार निर्देशित यह मिसाइल सभी मौसम में मार करने में सक्षम है
- यह दुनिया की सबसे सफल एंटी-शिप मिसाइल बताई जाती है
- 30 से ज्यादा देशों के सशस्त्र बलों में इसकी तैनाती है

अमेरिका बोला, हमारी दोस्ती भारत के साथ अटूट

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने कहा है कि भारत संग हमारे अटूट संबंध हैं। दोनों देशों के आर्थिक, व्यापारिक और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी हित व चिंताएं साझा हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने हाल ही में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे के बाद पत्रकार वार्ता में यह बात कही। प्राइस ने कहा कि विदेश मंत्री के दौरे में वार्ता का एजेंडा विस्तृत था। इसमें अर्थव्यवस्था, व्यापार, जलवायु के साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी वार्ता हुई है। दोनों ही देश क्वाड के सदस्य हैं, इस पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों ने कोरोना महामारी में वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने पर भी विचार किया है। नेड प्राइस ने भारत दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका और भारत के संबंध सरकार के ही स्तर पर नहीं हैं। दोनों देशों की जनता के आपसी संबंध भी बहुत गहरे हैं। भारत के लोगों से हमारे लोगों के पारिवारिक रिश्ते हैं। दोनों ही देश के लोग एक-दूसरे की संस्कृति और विरासत का सम्मान करते हैं। ज्ञात हो कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत यात्रा के दौरान अपने समकक्ष एस जयशंकर के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे।

नेड प्राइस। फाइल

2030 तक दुनिया के हर क्षेत्र में आगे होगा भारत

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारत 2030 तक दुनिया के सभी क्षेत्रों में आगे होगा। युवा देश को आगे ले जाने में सक्षम हैं। अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक रिचर्ड वर्मा ने भारत में भविष्य की संभावनाओं को लेकर यह बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र हैं और मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। मैं 2030 की तरफ देख रहा हूं, जब भारत हर क्षेत्र में आगे होगा। यह देश अधिक आबादी वाला है, यहां सबसे ज्यादा मध्यमवर्गीय लोग हैं। स्नातकों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। सबसे ज्यादा सेलफोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। 60 करोड़ आबादी 25 साल से कम उम्र की है। कह सकते हैं कि यह देश युवाओं का है। ऐसी स्थिति में देश पूरी तरह संभावनाओं से भरा हुआ है। भारत में अमेरिकी राजदूत रहे वर्मा जिंदल यूनिवर्सिटी स्कूल आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, भारत की युवा आबादी के बल पर आप 2050 तक सभी लक्ष्य बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। वर्मा ने कहा कि मैंने भारत के हर राज्य की यात्रा की है, इन राज्यों में असीमित संभावनाएं हैं। यही कारण है कि मैं आप जैसे युवाओं को लेकर बहुत ही उत्साहित हूं।

रिचर्ड वर्मा (फाइल)। जागरण आर्काइव

अमेरिका में 70 फीसद लोगों को लगी वैक्सीन

न्यूयार्क टाइम्स से

वाशिंगटन : अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वैरिएंट के बढ़ते कहर के बीच 70 फीसद लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगाने का लक्ष्य एक माह की देरी से हासिल कर लिया गया। राष्ट्रपति जो बाइडन ने चार जुलाई तक इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही थी। इधर, देश में संक्रमण बढ़ने के बावजूद अमेरिकियों में टीकाकरण और मास्क पहनने को लेकर भ्रम की स्थिति है। इसके लिए व्हाइट हाउस और स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

न्यूयार्क टाइम्स अखबार के डाटा के अनुसार, अमेरिका में कोरोना के दैनिक औसत मामले रविवार को बढ़कर करीब 80 हजार हो गए। यह आंकड़ा जुलाई की शुरुआत तक सिर्फ 12 हजार था। कुछ विशेषज्ञों ने संक्रमण बढ़ने के लिए सीडीसी को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि सीडीसी ने गत मई में कहा था कि वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग बगैर मास्क के बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद पिछले हफ्ते हर किसी को मास्क पहनने की सलाह दी। इधर, बाइडन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, प्रशासन ने सोमवार को माना कि विरोधाभाषी सूचना से कुछ अमेरिकी भ्रम की स्थिति में हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा, बाइडन इस सप्ताह देश को संबोधित करेंगे और विभिन्न बिंदुओं पर स्थिति साफ करेंगे। लोगों से यह कहेंगे कि वैक्सीन सुरक्षित है और टीका लगवा चुके लोगों के लिए भी मास्क पहनना जरूरत है।

अमेरिकी में कोरोना संक्रमण की गत बढ़ने के साथ ही वैक्सीनेशन और जांच के काम में भी तेजी आ गई है। फ्लोरिडा के पालमेट्टो में जांच के लिए बच्चे का स्वैब सैंपल लेता हेल्थकेयर वर्कर। रायटर

टीका लगवाने के बाद सीनेटर ग्राहम पाजिटिव : अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम संक्रमित पाए गए। उन्होंने बताया कि दस दिन तक क्वारंटाइन में रहेंगे। टीका नहीं लगा होता तो स्थिति खराब हो सकती थी।

जर्मनी में वैक्सीन बूस्टर लगाने का एलान : जर्मनी में भी डेल्टा वैरिएंट को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसके खतरे को देखते हुए जर्मन सरकार ने सोमवार को सितंबर से वैक्सीन की बूस्टर लगाने का एलान किया। सबसे पहले जोखिम वाले लोगों को बूस्टर लगाया जाएगा।

वुहान के सभी निवासियों का होगा टेस्ट

बीजिंग, एएनआइ : चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस फिर पांव पसार रहा है। संक्रमण पर अंकुश पाने के लिए शहर के सभी निवासियों का कोरोना टेस्ट कराने का निर्णय लिया गया है। 1.1 करोड़ की आबादी वाले इसी शहर में दिसंबर, 2019 में कोरोना का पहला केस मिला था और यही से वायरस पूरी दुनिया में फैल गया।

वुहान में सोमवार को कोरोना के सात मामले पाए गए। गत जून से यहां कोई मामला नहीं मिला था। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि देशभर में 90 नए संक्रमित पाए गए। एक दिन पहले 61 मामले मिले थे। इनमें से कई मामले डेल्टा के पाए गए हैं। ज्यादातर मामले जिआंगसु प्रांत में मिल रहे हैं। प्रांतीय राजधानी नानजिंग के एयरपोर्ट से संक्रमण की शुरुआत बताई जा रही है। यहां से 105 किमी दूर स्थित यांगझोउ शहर तक कोरोना फैल गया है।

टोक्यो में मिले 3,709 मामले : समाचार एजेंसी रायटर के अनुसार, जापान की राजधानी टोक्यो में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,709 नए मामले पाए गए। ओलिंपिक की मेजबानी कर रहे इस शहर में एक दिन पहले 4,058 केस मिले थे।

बड़ा उलटफेर करने उतरेगी महिला हाकी टीम

भारतीय महिलाएं आज सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हराकर पहली बार पाना चाहेंगी फाइनल का टिकट

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय महिला हाकी टीम पहले ही इतिहास रच चुकी है और अब उसका लक्ष्य टोक्यो ओलिंपिक खेलों के सेमीफाइनल में बुधवार को अर्जेंटीना को हराकर अपनी उपलब्धियों को चरम पर पहुंचाना होगा। आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला टीम ने सोमवार को तीन बार की चैंपियन आस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर पहली बार ओलिंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

फिर गोल करो गुरजीत : ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में भारत को मिले एकमात्र पेनाल्टी कार्नर को गोल में बदला जो आखिर में निर्णायक साबित हुआ। इस मैच से पहले सभी परिस्थितियां रानी रामपाल की अगुआई और शोर्ड मारिन की कोचिंग वाली टीम के खिलाफ थी। गुरजीत से फिर से गोल की उम्मीद रहेगी।

महिलाओं से आस : भारतीय महिला हाकी टीम का ओलिंपिक में इससे पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मास्को ओलिंपिक 1980 में रहा था जब वह छह टीमों में चौथे स्थान पर रही थी। महिला हाकी ने तब ओलिंपिक में पदार्पण किया था और मैच राउंड रोबिन आधार पर खेले गए थे जिसमें शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें फाइनल में पहुंची थी। बुधवार को भारतीय महिलाएं उस उपलब्धि से आगे निकलकर पहली बार ओलिंपिक फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेंगी। भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल से आगे बढ़ने में नाकाम रही और अब सभी की निगाहें महिलाओं पर टिकी हैं। पुरुष टीम अंतिम-चार के मैच में बेल्जियम से हार गई।

सविता ने किले को संभाला : गोलकीपर सविता ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और आस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने टीम को गोल नहीं खाने दिया था। भारतीय रक्षापंक्ति ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाया और अपने एकमात्र गोल का अच्छी तरह से बचाव भी किया। गुरजीत, दीप ग्रेस एक्का, मोनिका और उदिता को लैस लियोंस जैसी खिलाड़ियों को रोकने के लिए इसी तरह के प्रयास जारी रखने होंगे।

मजबूत अर्जेंटीना : अर्जेंटीना ने सिडनी 2000 और लंदन 2012 में रजत पदक जीता था, लेकिन अभी तक स्वर्ण पदक हासिल नहीं कर पाई है। भारतीय टीम ने हालांकि लगातार तीन हार के बाद लगातार तीन जीत दर्ज की हैं और वह आत्मविश्वास से भरी है।

2-0 (जीत-हार) से आगे है अर्जेंटीना की महिला टीम भारत के खिलाफ

2016 रियो ओलिंपिक में अर्जेंटीना ने भारत को 5-0 से रौंदा था

2017 में महिला विश्व लीग में भी अर्जेंटीना ने भारत को 3-0 से हराया था

रवि और दीपक को अच्छा ड्रा, यूरोपीय चैंपियन से भिड़ेंगी अंशू

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय पहलवान रवि दाहिया को मंगलवार को ओलिंपिक की पुरुष 57 किग्रा फ्रीस्टाइल स्पर्धा में अच्छा ड्रा मिला जहां वह अपने अभियान की शुरुआत बुधवार को कोलंबिया के टिगरेरोस उरबानो के खिलाफ करेंगे। मौजूदा फार्म को देखते हुए रवि को कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। पुरुष फ्रीस्टाइल 86 किग्रा में दीपक को पहले दौर में नाईजीरिया के एकरेकेम एगियोमोर से भिड़ना है जो अफ्रीकी चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता हैं। इस बीच, 19 साल की अंशू मलिक को मुश्किल ड्रा मिला है और उन्हें पहले दौर में ही यूरोपीय चैंपियन इरिना कुराचिकिना से भिड़ना है। अंशू जीत दर्ज करती हैं तो उनका सामना रियो की रजत विजेता वालेरिया कोबलोवा और मेक्सिको की अल्मा जेन के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता से होगा।

टोक्यो ओलिंपिक में दोनों टीमों का प्रदर्शन

	कुल मैच	हार	जीत
भारत	6	3	3
अर्जेंटीना	6	2	4

विश्व रैंकिंग

07 भारत

02 अर्जेंटीना

अर्जेंटीना दौरे पर जीत के लिए तरसे थे भारतीय

हाल के रिकार्ड को देखा जाए तो अर्जेंटीना का पलड़ा भारी लगता है। ओलिंपिक से पहले भारतीय महिलाओं ने अर्जेंटीना का दौरा किया था। भारत ने वहां सात मैच खेले। इनमें से अर्जेंटीना की युवा टीम के खिलाफ उसने दोनों मैच 2-2 और 1-1 से ड्रा कराए। भारत इसके बाद अर्जेंटीना की बी टीम से खेला जिसमें उसे 1-2 और 2-3 से हार झेलनी पड़ी। अर्जेंटीना की सीनियर टीम के खिलाफ उसने पहला मैच 1-1 से ड्रा खेला, लेकिन अगले दो मैच 0-2 और 2-3 से हार गया। भारतीय कप्तान रानी ने आस्ट्रेलिया पर जीत के बाद कहा था कि हमने सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास बना दिया और अब हम सेमीफाइनल से आगे के बारे में सोच रहे हैं।

भारतीय महिला हाकी टीम • प्रेट्र

आज उम्मीदों का भाला फेंकेंगे नीरज चोपड़ा

टोक्यो : ओलिंपिक में एक के बाद एक भारतीय एथलीटों के बाहर होने के बाद स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा बुधवार को देशवासियों की उम्मीदों का भार लेकर भाला फेंकने उतरेंगे। चक्का फेंक खिलाड़ी कमलप्रीत कौर ही एथलेटिक्स में पदक की कुछ आस जगा पाई थी जब वह फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वह भी फाइनल में छठे स्थान पर रहीं। नीरज ने टोक्यो ओलिंपिक के लिए ज्यादातर अभ्यास विदेश में ही किया है और वह भारत के पदक के दावेदारों में शामिल हैं। वह क्वालीफिकेशन में ग्रुप-ए में उतरेंगे और उम्मीद है कि वह देश को निराश नहीं करेंगे। वहीं, अन्य भाला फेंक एथलीट शिवपाल सिंह क्वालीफिकेशन में ग्रुप-बी में उतरेंगे और वह अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे।

भाला फेंकते हुए नीरज चोपड़ा • फाइल फोटो रायटर

एक जीत बदल देगी मुक्केबाज लवलीना के पदक का रंग

टोक्यो, प्रेट्र : लवलीना बोरगोहाई (69 किग्रा) ओलिंपिक में पहले ही पदक सुरक्षित कर चुकी हैं, लेकिन बुधवार को वह तुर्की की मौजूदा विश्व चैंपियन बुसेनाज सुरमेनेली के खिलाफ जीत दर्ज करके ओलिंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनने की कोशिश करेंगी।

असम की 23 वर्षीय लवलीना इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी हैं। वह पदक पक्का करके पहले ही विजेंद्र सिंह (2008) और एमसी मेरी कोम (2012) की बराबरी कर चुकी है। लवलीना का पदक पिछले नौ वर्षों में भारत का मुक्केबाजी में पहला पदक होगा, लेकिन उनका लक्ष्य अब फाइनल में पहुंचना होगा जहां अभी तक कोई भारतीय नहीं पहुंचा है। राष्ट्रीय कोच मुहम्मद अली कमर ने इस महत्वपूर्ण मुकाबले की पूर्व संध्या पर कहा, 'यह मुकाबला दोपहर बाद होगा और इसलिए हम पिछले दो दिनों से दोपहर बाद ही अभ्यास कर रहे हैं। ये दोनों मुक्केबाज इससे पहले एक-दूसरे से नहीं भिड़े हैं और वे दोनों एक-दूसरे के खेल के बारे में नहीं जानते हैं। लवलीना अच्छे प्रदर्शन के प्रति आत्मविश्वास से भरी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगी। वह अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट हैं।' उन्होंने पिछले दौर में चीनी ताइपे की पूर्व विश्व चैंपियन नीन चिन चेन को हराया था। उन्होंने इस मुकाबले के बाद कहा था कि पदक तो बस स्वर्ण होता है, पहले मुझे उसे हासिल करने दो। लवलीना ओलिंपिक में पदार्पण कर रही हैं, लेकिन उन्होंने सहज होकर अपने मुकाबले लड़े हैं। तुर्की की शीर्ष वरीयता प्राप्त मुक्केबाज के खिलाफ भी वह बिना किसी दबाव के रिंग में उतरेंगी।

वहीं, सुरमेनेली भी 23 साल की हैं और इस साल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने दो स्वर्ण पदक जीते हैं। लवलीना भी इस खेल में नई नहीं हैं और उन्होंने अभी तक अपने करियर में विश्व चैंपियनशिप के दो कांस्य पदक अपने नाम किए हैं।

लवलीना बोरगोहाई • एएनआइ

पूर्व क्रिकेटर के बेटे ने जीता रजत पदक

ओलिंपिक डायरी

टोक्यो, एपी : ओलिंपिक में जबसे खेलों की रानी कही जाने वाली एथलेटिक्स स्पर्धा शुरू हुई है तबसे एक से बढ़कर एक एथलीट ट्रैक एंड फील्ड में जलवा दिखा रहे हैं। इसमें वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर विंस्टन बेंजामिन के बेटे राय बेंजामिन भी छाए हुए हैं। राय ने ने मंगलवार को पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में सिर्फ 46.17 सेकेंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इस दौरान बेंजामिन ने नार्वे के कार्स्टन वारहोम के विश्व रिकार्ड से भी बेहतर समय निकाला, लेकिन ये रिकार्ड उनके नाम नहीं हो पाया, क्योंकि इस रेस में खुद कार्स्टन हिस्सा ले रहे थे, जिन्होंने सभी रिकार्ड तोड़ते हुए 45.94 सेकेंड के नए विश्व रिकार्ड के साथ स्वर्ण जीता।

राय दिग्गज विंडीज तेज गेंदबाज विंस्टन बेंजामिन के बेटे हैं, जिन्होंने 1980-90 के दौर में वेस्टइंडीज के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला। विंस्टन तो कैरेबियाई द्वीप एंटीगा के रहने वाले हैं और राय का जन्म भी वहीं हुआ, लेकिन वह अपनी मां के साथ न्यूयार्क में रहने लगे और वहीं की नागरिकता हासिल कर ओलिंपिक में अमेरिका का प्रतिनिधत्व करने लगे। वह 400 मीटर बाधा दौड़ में अमेरिका के सबसे तेज धावक हैं। विंस्टन बेंजामिन ने वेस्टइंडीज के लिए 21 टेस्ट मैचों में 61 विकेट हासिल किए, जबकि 85 वनडे में उनके नाम 100 विकेट हैं। उन्होंने 1985 में टेस्ट पदार्पण किया था और 1995 में अंतिम टेस्ट मैच खेला था।

62 साल की उम्र में पदक जीतने वाले पहले आस्ट्रेलियाई बने होय : 62 साल की उम्र मे टोक्यो ओलिंपिक की घुड़सवारी टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतने के साथ ही आठ बार के ओलिंपियन एंड्र्यू होय आस्ट्रेलिया के लिए पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। होय के साथ टीम में शेन रोज और केविन मैकनाब भी शामिल थे। स्वर्ण पदक की दौड़ में आस्ट्रेलिया के घुड़सवार ब्रिटेन से पीछे रहे और उन्हें रजत से संतोष करना पड़ा। कुछ ही समय बाद होय ने इवेंट जंपिंग व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक भी अपने नाम किया। जिससे आठ ओलिंपिक में भाग लेने वाले होय के कुल पदकों की संख्या छह हो गई। इनमे तीन स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक शामिल है। इस तरह पदक जीतने के बाद होय ने यह भी साफ कर दिया कि यह उनका अंतिम ओलिंपिक नहीं है।

बाइल्स ने बैलेंस बीम में जीता कांस्य पदक

टोक्यो : अमेरिका की दिग्गज जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स ने मानसिक बीमारी से वापसी करते हुए मंगलवार को टोक्यो ओलिंपिक की बैलेंस बीम स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण और रजत चीन के खिलाड़ियों के नाम रहा। गुआन चेनचेन ने स्वर्ण जबकि तैंग शिजिंग ने रजत पदक जीता। एक सप्ताह पहले मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का हवाला देते हुए स्पर्धाओं से हटने का फैसला करने के बाद उन्होंने मंगलवार को वापसी का मन बनाया। बाइल्स ने कुल 14 अंक प्राप्त किए जो कांस्य जीतने के लिए काफी था। शीर्ष के दोनों जिम्नास्टों ने क्रमश : 14.633 और 14.233 अंक हासिल किए।

भारत के आज के मैच

पदक के मुकाबले

- **मुक्केबाजी :** सेमीफाइनल, सुबह 11.00 बजे से
  खिलाड़ी (महिला) : लवलीना बोरगोहाई

अन्य मुकाबले

- **एथलेटिक्स :** भाला फेंक (पुरुष वर्ग) : क्वालीफिकेशन
  खिलाड़ी : नीरज चोपड़ा, सुबह 5:35 बजे से, शिवपाल सिंह, सुबह 7:05 बजे से
- **गोल्फ :** महिला व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड 1, सुबह 4:00 बजे से
  खिलाड़ी : अदिति अशोक और दीक्षा डागर
- **हाकी (महिला) :** सेमीफाइनल, दोपहर 3:30 बजे से, बनाम अर्जेंटीना
- **कुश्ती :** अंतिम-16, सुबह 8:00 बजे के बाद, **खिलाड़ी (पुरुष) :** रवि कुमार और दीपक पूनिया, **खिलाड़ी (महिला) :** अंशू मलिक

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

सोनम ने आखिरी 45 सेकेंड में की गलती

साक्षी मलिक कलम से

मंगलवार को 2016 रियो ओलिंपिक खेलों को याद करने से खुद को रोकना बेहद मुश्किल था जहां भारत को आखिरी कुछ दिनों तक एक भी पदक नहीं मिला था। हमें पता है कि कई खेलों में हमारे पास शानदार एथलीट हैं लेकिन निराशा का माहौल पूरे दल को अपनी चपेट में ले लेता है। मैं जानती हूं कि इससे उन खिलाड़ियों पर कितना अधिक दबाव बढ़ जाता है जो अंत में अपनी-अपनी स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे होते हैं। मुझे विनेश फोगाट के साथ हुई अपनी बातचीत याद है जब उनसे पदक का सफर तय करने की उम्मीद की जा रही थी लेकिन तभी उन्हें दिल तोड़ देने वाली चोट लग गई। मैं ये बात कह सकती हूं कि हम अतिरिक्त दबाव से बच नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि ऐसे में जबकि तीन पदक निश्चित हो चुके हैं और हॉकी टीम भी पदक की दौड़ में है, टोक्यो में मौजूद भारतीय दल में एनर्जी और सकारात्मकता का संचार होगा।

सोनम मलिक आसानी से अपना मुकाबला जीत सकती थी, अगर उन्होंने आखिरी 45 सेकेंड में गलतियां न की होती तो। हो सकता है कि वह विपक्षी खिलाड़ी के दांव से हैरान रह गईं हों लेकिन आखिरी लम्हों में उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। हो सकता है कि मंगोलियाई खिलाड़ी ने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि सोनम ने थोड़ा सीधा खड़ा होना शुरू कर दिया है यानी कि या तो वह थक गईं हैं या फिर तेज आक्रमण के लिए तैयार नहीं हैं। ये वो गलती है जो अधिकतर भारतीय पहलवान करते हैं जब वे बढ़त पर होते हैं। बढ़त के बाद हम रक्षात्मक हो जाते हैं। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि अपने करियर में मैंने भी कई बार ऐसा रवैया अपनाया है जबकि इसके बजाय हमें बढ़त लेने के बाद और अंक बटोरने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है कि हमारे कोच युवा उम्र से पहलवानों की इस सोच को प्रोत्साहन देंगे।

अगर हमने किसी रणनीति की बदौलत अच्छा प्रदर्शन किया है तो हमें उसे पूरे छह मिनट तक बरकरार रखना चाहिए। अगर अटैक करके हमें सफलता मिली है तो हमें आक्रामक ही रहना चाहिए। सोनम अपने खेल की योजना पर कायम रहती तो और भी अंक बटोर सकती थीं, लेकिन उन्होंने 2-0 की बढ़त के बाद पर्याप्त अटैक नहीं किया। अप्रैल में एशियन ओलिंपिक क्वालीफायर के सेमीफाइनल में सोनम चोटिल हो गई थीं। मुझे नहीं पता कि इसका उनकी मैच फिटनेस पर असर पड़ा है या नहीं। (टीसीएम)

स्वतंत्रता दिवस समारोह में मौजूद रहेगा ओलिंपिक दल

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरोः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को देश के सामने जब नए भारत की अपनी सोच रखेंगे तो इस मौके पर टोक्यो ओलिंपिक में भाग लेने वाला पूरा भारतीय दल मौजूद रहेगा। भारतीय दल लाल किले पर होने वाले समारोह में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद होगा। बाद में प्रधानमंत्री अपने आवास पर सबके साथ बातचीत कर उनका अनुभव भी पूछेंगे।

ओलिंपिक के लिए दल के रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों व उनके परिजन से वर्चुअल बातचीत की थी और उत्साह बढ़ाते हुए सुझाव दिया था कि अपेक्षाओं के दबाव में आने की बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें कई खिलाड़ियों ने अपेक्षाओं से आगे बढ़कर प्रदर्शन किया है। महिलाओं ने विशेषतौर पर गौरवान्वित किया है। परोक्ष रूप से यह संदेश होगा कि महिलाओं को कमतर नहीं आंकना चाहिए।

सोना-चांदी हारे, कांसे पर निगाहें

- बेल्जियम ने तोड़ा भारत का स्वर्णिम सपना
- सेमीफाइनल मुकाबले में पुरुष हाकी टीम हारी
- कांस्य पदक की उम्मीद अभी भी बरकरार

टोक्यो, प्रेट्रः भारतीय हाकी टीम का 41 साल बाद ओलिंपिक स्वर्ण पदक जीतने का सपना मंगलवार को यहां बेल्जियम के हाथों अंतिम-चार में 2-5 से करारी हार के साथ टूट गया, लेकिन टोक्यो खेलों में टीम अब भी कांस्य पदक की दौड़ में बनी हुई है।

भारतीय टीम एक समय बढ़त पर थी, लेकिन अंतिम 11 मिनट में तीन गोल गंवाने और एलेक्सांद्र हैंड्रिक्स (19वें, 49वें और 53वें मिनट) की हैट्रिक उस पर भारी पड़ गई। विश्व चैंपियन बेल्जियम की तरफ से हैंड्रिक्स के अलावा लोइक फैनी लयपर्ट (दूसरे) और जान जान डोहमेन (60वें मिनट) ने भी गोल किए। भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह ने सातवें और मनदीप सिंह ने आठवें मिनट में गोल किए थे। बेल्जियम की टीम रियो ओलिंपिक का रजत पदक विजेता है और उसने इस तरह से लगातार दूसरी बार ओलिंपिक फाइनल में जगह बनाई है जहां उसका सामना आस्ट्रेलिया से होगा जिसने अन्य सेमीफाइनल में जर्मनी को 3-1 से हराया। भारत ने आखिरी बार मास्को ओलिंपिक 1980 में फाइनल में जगह बनाई थी और तब टीम ने अपने आठ स्वर्ण पदकों में से आखिरी स्वर्ण पदक जीता था। सेमीफाइनल में हार के लिए भारतीय टीम ही दोषी रही क्योंकि बेल्जियम ने चार गोल पेनाल्टी कार्नर पर किए। विश्व चैंपियन टीम ने भारतीय रक्षापंक्ति पर लगातार दबाव बनाए रखा और 14 पेनाल्टी कार्नर हासिल किए जिसमें से चार को उसने गोल में बदला। बेल्जियम की शुरू से ही रणनीति स्पष्ट थी कि भारतीय सर्कल में घुसकर पेनाल्टी कार्नर हासिल करना है क्योंकि उसके पास हैंड्रिक्स और लयपर्ट के रूप में दो पेनाल्टी कार्नर विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपनी इस रणनीति पर अच्छी तरह से अमल किया तथा हैंड्रिक्सि और लयपर्ट ने भी उन्हें निराश नहीं किया। भारत ने भी पांच पेनाल्टी कार्नर हासिल किए, लेकिन इनमें से वह केवल एक पर ही गोल कर पाया। भारतीय टीम 49 वर्ष बाद ओलिंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची थी। भारत ने धीमी शुरुआत की जबकि बेल्जियम ने शुरू में ही मैच पर नियंत्रण बना दिया और इस बीच एक गोल भी दागा। बेल्जियम अपने पहले आक्रमण पर ही पेनाल्टी कार्नर हासिल करने में सफल रहा जिसे लयपर्ट ने ताकतवर फ्लिक से गोल में बदला।

भारतीयों ने हालांकि दमदार वापसी और दो मिनट के अंदर दो गोल करके मैच के समीकरण बदल दिए। भारत ने सातवें मिनट में दो पेनाल्टी कार्नर हासिल किए जिनमें से दूसरे को हरमनप्रीत ने बड़ी खूबसूरती से गोल में बदला। यह उनका टूर्नामेंट में पांचवां गोल है। अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण दबाव झेल रहे मनदीप ने इसके एक मिनट बाद मैदानी गोल दागकर भारत को बढ़त दिला दी। मनदीप को अमित रोहिदास से दायें छोर से पास मिला और उन्होंने ताकतवर रिवर्स हिट से उसे गोल के रूप में बदल दिया। बेल्जियम के गोलकीपर विंसेंट वनास्च देखते ही रह गए।

भारत को पहले क्वार्टर में एक और मौका पेनाल्टी कार्नर के रूप में मिला, लेकिन विंसेंट ने रूपिंदरपाल का शाट रोक दिया। एक गोल से पिछड़ने के बाद बेल्जियम ने दूसरे क्वार्टर में लगातार हमले किए व भारतीय रक्षापंक्ति को दबाव में रखा। भारत ने इस बीच चार पेनाल्टी कार्नर गंवाए जिनमें से आखिरी को हैंड्रिक्स ने गोल में बदलकर स्कोर बराबर किया। कुछ मिनट बाद श्रीजेश ने डोकियर का प्रयास नाकाम किया।

मैच	टीमें	समय
स्वर्ण पदक मैच	आस्ट्रेलिया बनाम बेल्जियम	दोपहर 3:30 बजे
कांस्य पदक मैच	भारत बनाम जर्मनी	सुबह 7:00 बजे
नोट : दोनों मैच गुरुवार को होंगे।		

"मेरे लिए अभी चीजें आसान नहीं हैं क्योंकि हम जीतने की मानसिकता के साथ आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से हम मैच जीत नहीं पाए। अब हमें कांस्य पदक के मुकाबले पर ध्यान लगाने की जरूरत है और हमें यह पदक जीतने की जरूरत है।
मनप्रीत सिंह, कप्तान, भारत

निराश, लेकिन हमारे पास इस बारे में चिंतित होने का समय नहीं है। आपको इस बारे में भूलना होगा और भविष्य के बारे में सोचना होगा। हमारे पास अब भी पदक जीतने का मौका है।"
पीआर श्रीजेश, गोलकीपर, भारत

पदक तालिका

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
चीन	32	21	16	69
अमेरिका	24	28	21	73
जापान	19	6	11	36
आस्ट्रेलिया	14	4	15	33
आरओसी	13	21	18	52
ग्रेट ब्रिटेन	13	17	13	43
जर्मनी	8	8	14	30
फ्रांस	6	10	8	24
नीदरलैंड्स	6	7	7	20
द. कोरिया	6	4	9	19
भारत	0	1	1	2

नोट : भारत तालिका में 64वें स्थान पर है। आरओसी (रूसी ओलिंपिक समिति)

बेल्जियम से मिली हार के बाद भारतीय हाकी खिलाड़ी निराश होकर कुछ इस अंदाज मे लेटे हुए नजर आए • प्रेट्र

एनआरएआइ के कारण टोक्यो नहीं जा सके जसपाल राणा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआइ) ने जब ओलिंपिक के लिए अपनी एक्रीडेशन (मान्यता) सूची को अंतिम रूप दिया था तब उसने कोच जसपाल राणा को आवश्यक श्रेणी में शामिल नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप वह अपने निशानेबाज अभिषेक वर्मा के साथ टोक्यो नहीं जा सके। इस अनुभवी पिस्टल कोच और पूर्व निशानेबाज को राष्ट्रीय महासंघ की प्राथमिकता सूची में नहीं रखा गया था। मनु भाकर के साथ विवाद के बाद इन खेलों से पहले सिर्फ वर्मा ही राणा से प्रशिक्षण ले रहे थे। राणा को क्रोएशिया में टीम के प्रशिक्षण-सह-प्रतियोगिता दौरे के बाद टोक्यो में उनकी मदद के लिए उनके साथ रहना था। वर्मा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल और मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में भाग लिया था। राष्ट्रीय शाटगन कोच मनशेर सिंह को स्कीट निशानेबाजों अंगद वीर सिंह बाजवा और मैराज अहमद खान के लिए आवश्यक श्रेणी में शामिल किया गया था, जबकि विदेशी राइफल कोच ओलेग मिखाइलोव को इलावेनिल और अपूर्वी चंदेला के लिए आवश्यक श्रेणी में रखा गया था।

ओलिंपिक से बाहर तूर और अनु

टोक्यो : भारतीय गोला फेंक एथलीट तजिंदर पाल सिंह तूर और भाला फेंक खिलाड़ी अनु रानी ओलिंपिक में अपनी-अपनी प्रतिस्पर्धा में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे और इस खेल महाकुंभ से बाहर हो गए। फाइनल के प्रबल दावेदार माने जा रहे तूर ओलिंपिक क्वालीफिकेशन में ग्रुप-ए में 13वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह नहीं बना पाए। वहीं, अनु रानी भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई और 54.04 मीटर के निराशाजनक प्रदर्शन के साथ 14वें स्थान पर रहीं। वह भी ओलिंपिक से बाहर हो गई। अनु ने 50.35 मीटर भाला फेंककर शुरुआत की और अपने दूसरे प्रयास में 53.19 मीटर की दूरी तय की।

बुधवार, 4 अगस्त, 2021

कोरोना काल में परिवार की सामूहिक देखभाल

डॉ. राम आश्रय साहु
वरिष्ठ चिकित्सक तथा अध्यक्ष, स्वास्थ्य आयाम-सेवा भारती, कानपुर

कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका हर किसी को घेरे हुए है। ऐसे में काम तो रोका नहीं जा सकता मगर कोरोना संक्रमण से बचाव में घर के सदस्यों की सामूहिक देखभाल में ये बातें हो सकती हैं मददगार...

बीते करीब दो साल से लगभग हर कोई सेहत के प्रति सजग हो चुका है। घर की रसोई से ही बना पौष्टिक भोजन सबकी पसंद बन गया है। आयुर्वेद में बताए गए नुस्खे बखूबी काम आए। हर्ड इम्युनिटी की बातें हुईं तो समझ आया कि साथ मिलकर ही सेहत को बेहतर बनाया और कोरोना संक्रमण को दूर रखा जा सकता है। तो ऐसे में कुछ आवश्यक बातों का पालन करने से कोरोना व अन्य संक्रमणों से आपके जरिए आपके परिवार का हर सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ्य रहेगा।

सही दिनचर्या यानी सही शुरुआत: शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति (इम्युनिटी) की कमी से कोरोना या अन्य संक्रमण आसानी से शरीर में घर कर जाते हैं। यदि इम्युनिटी मजबूत रहे तो हर रोग दूर रहते हैं। इम्युनिटी मजबूत करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को समय पर जागें। आयु के अनुसार एक से तीन गिलास गुनगुना पानी घूट-घूटकर पीएं। निवृत्त होने के बाद आठ से दस ग्रीन लीफ टी, एक काली मिर्च, पांच से आठ ग्राम अदरक कूटकर दो कप पानी में उबालें, आधा रह जाने पर छानकर पिएं। स्वाद के लिए थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं। यह सेहत के लिए फायदेमंद खुराक है। इसके अतिरिक्त आप अमृता चाय का सेवन भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 इंच अमृता (गिलोय) की डंठल, पांच ग्राम सोंठ, पांच ग्राम दालचीनी कूटकर दो कप पानी में डालकर उबालें, आधा रह जाने पर छानकर पीएं। अमृता सैकड़ों मर्जों में लाभदायक औषधि है। अब योग, हल्का व्यायाम व 30 से 45 मिनट टहलें। उक्त सभी एंटी आक्सीडेंट, बेहतर इम्युनिटी बूस्टर हैं। रात में सोने से पूर्व सभी सदस्य गर्म दूध में 100-200 ग्राम हल्दी मिलाकर सेवन करें।

दाम नहीं गुणवत्ता पर रखें नजर: कहा गया है कि 'जैसा खाओ अन्न, वैसा होए तन'। भोजन का सीधा असर व्यक्ति के स्वास्थ्य और बीमारियों से होता है। कुछ अतिरिक्त खर्च में मिलने वाले खाद्य पदार्थ सस्ते खाद्य पदार्थों की तुलना में पौष्टिकता में काफी कम होते हैं, जिनकी जानकारी शायद हर किसी को नहीं होती है। ऐसे में खाद्य वस्तुओं का चयन उनकी कीमत के बजाय उससे मिलने वाले पौष्टिक गुणों के अनुसार करें।

जीवन के स्रोत से लें आशीर्वाद: सूर्य शक्ति और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन एवं वनस्पतियां असंभव है। सूर्य की रोशनी से शरीर में विटामिन-डी का निर्माण होता है। सेरोटोसिन तथा मेलोटोनिन हार्मोन उत्सर्जित होते हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं। रक्त कोशिकाओं तथा इम्युनिटी का संवर्धन होता है। सुनिश्चित करें कि हर सदस्य प्रातःकालीन कुछ वक्त 20-30 मिनट धूप अवश्य ले।

लगाएं आक्सीजन उत्सर्जक पौधे: तुलसी, मनीप्लांट, एलोवेरा, लेडी पाम, रबर प्लांट आदि कोई भी गमलों में लगाएं। बेहद कम मशक्कत से उगने वाला सहजन उत्तम स्तर का प्रोटीन, समस्त विटामिन्स एवं मिनरल्स का स्रोत होता है। इंग्लैंड में इसे 'न्यूट्रीशन डायनामाइट' और अफ्रीका में 'बेस्टफ्रेंड आफ वीमेन' कहा जाता है। सर्वोत्तम एंटी आक्सीडेंट एवं इम्युनिटी बूस्टर जैसे गुणों से युक्त सहजन डायबिटीज, कोलेस्ट्राल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध की कमी, बच्चों में सूखा रोग जैसी अनेक समस्याओं में भी यह काफी फायदेमंद होता है।

सुरक्षित जीवन के सरल उपाय

1. पांच माह से 11 वर्ष के बच्चों की सरसों के तेल से मालिश करें।
2. फ्रिज में रखे पानी या खाद्य पदार्थ को सामान्य तापमान पर आने के बाद ही इस्तेमाल करें।
3. फास्टफूड व शीतल पेय का प्रयोग कम से कम करें।
4. बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। एन-95 मास्क लगाएं व दो गज की दूरी बरतें। घर लौटने पर संभव हो तो गुनगुने पानी से स्नान करें अन्यथा अच्छे से हाथ-पैर धोएं।

इन दिनों

पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत
निदेशक, एम्स, ऋषिकेश

बरस रही बीमारियों से बचना जरा

कोरोना को हराना है

मानसून के दौरान संक्रमण फैलाने में दूषित जल व दूषित खाद्य पदार्थ काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा संबंधी तमाम तकलीफें भी घर कर जाती हैं। इस मौसम में अतिरिक्त सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस दौरान होने वाली बीमारियों और कोरोना के लक्षणों में अंतर बड़ा बारीक है। ऐसे में संक्रमण के साथ ही कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए करने होंगे विशेष उपाय...

मनुष्य में आधी से अधिक बीमारियां दूषित पानी पीने से ही पैदा होती हैं। दूषित पानी पीने से बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा दूषित भोजन के सेवन से भी इन बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। इनमें डेंगू, मलेरिया, कालरा और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां प्रमुखता से शामिल हैं। बरसात में पेयजल के दूषित होने की सर्वाधिक आशंका होती है। इसके अलावा दूषित पानी के संपर्क में आने से त्वचा रोग व खुजली जैसी कई अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं।

समझें मौसमी बीमारियों को: इस मौसम में भारी बारिश से जगह-जगह पानी इकट्ठा होना आम बात है। यह स्थिति मच्छरों के प्रजनन के लिए अनुकूल होती है। ये मच्छर मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों को जन्म देते हैं। मानसून में सड़क किनारे खुले में बिकने वाले भोजन का सेवन भी इन दिनों हानिकारक होता है।

डेंगू: जलजनित यह रोग बहुत घातक होता है। समय पर इलाज न होने पर जान तक जा सकती है। इस रोग में प्लेटलेट्स लगातार गिरने लगती हैं। इससे रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तेज बुखार, जी मिचलाना और नाक या मुंह से खून आना इसके प्रमुख लक्षण हैं।

मलेरिया: एनाफिलीज मच्छर के काटने से होने वाली इस बीमारी में कंपकंपी व ठंड लगकर तेज बुखार, जी मिचलाना, उल्टी, सिरदर्द, सर्दी-जुकाम, सांस फूलना जैसे लक्षण शामिल हैं।

चिकनगुनिया: यह रोग मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। साफ पानी में पैदा होने वाले इन मच्छरों पर सफेद धारियां होती हैं। तेज बुखार, शरीर में लाल रंग के चकत्ते उभरना और हाथ-पैर की हड्डियों में तेज दर्द होना इसके प्रमुख लक्षण हैं।

फ्लू: इस मौसम में सबसे आम वायरल बीमारियों में से एक है सर्दी, जुकाम और फ्लू। कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों में संक्रमण जल्दी पनपता है।

हैजा: इस जलजनित रोग में मरीज को गंभीर उल्टी-दस्त से जूझना पड़ता है। ध्यान रहे कि इसका इलाज संभव है, लेकिन यदि समय पर इलाज न हो तो यह जानलेवा भी हो सकता है।

टायफाइड: इस संक्रमण के फैलने का एक मुख्य कारण गंदगी है। लंबे समय तक बुखार रहना, उल्टी, कमजोरी, सिरदर्द और लिवर में गड़बड़ी इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। इससे बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि साफ पानी पिएं और अपने आसपास सफाई रखें।

जांच से हो जाएं निश्चिंत: यह कहना फिलहाल मुश्किल है कि बरसात के मौसम में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि मौसम में नमी ज्यादा होने के चलते कोविड-19 वायरस को पनपने के लिए अनुकूल अवसर मिलता है। मौसमी बीमारी के दौरान कोरोना संक्रमण का भ्रम होने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जाना चाहिए। कारण यह है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और कोरोना के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। यदि कोविड रिपोर्ट निगेटिव आए तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो जाता है कि तकलीफ मौसमी बीमारियों से हुई है। इसके उपरांत सही उपचार किया जा सकता है।

अस्पतालों में डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी बरसाती बीमारियों की जांच की भी पर्याप्त सुविधाएं मौजूद रहती हैं।

उचित भोजन रखेगा सुरक्षित: इस मौसम में गरिष्ठ भोजन के बजाय हल्का भोजन करें। मौसम ठंडा होने के कारण प्यास कम लगती है, ऐसे में भरपूर पानी पीना सुनिश्चित करें। इम्युनिटी बढ़ाने के लिए भोजन में सलाद का उपयोग करने के साथ ही सुपाच्य सब्जियों (लौकी, तोरई आदि) और ताजे फलों का सेवन करें। दूषित जल और दूषित भोजन का सेवन करने से बचें। इसके अलावा बरसात के मौसम में खाद्य पदार्थों में फफूंद लगने का ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में बाहर से लाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में एक्सपायरी डेट जरूर देखा जाना चाहिए। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, शिशु और डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारी वाले लोगों की इम्युनिटी अन्य लोगों की अपेक्षा कमजोर होती है। इसलिए ऐसे लोगों को इस मौसम में बीमार होने का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे लोगों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। इसके साथ ही शुगर, ब्लड प्रेशर, थायरायड और यूरिक एसिड की तकलीफ से ग्रसित व्यक्तियों को संबंधित दवाओं का समय पर सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही भोजन में चीनी व नमक की संतुलित मात्रा लेनी चाहिए।

तीसरी लहर और हर्ड इम्युनिटी: राष्ट्रीय स्तर पर हुए शोध बताते हैं कि हर्ड इम्युनिटी की स्थिति में संभावित तीसरी लहर से बचा जा सकता है। देश के 60-70 प्रतिशत व्यक्तियों में एंटीबाडी पाई गई है यानी हर्ड इम्युनिटी की वजह से अधिकांश लोग अस्पताल जाने से बच गए या वे कोरोना संक्रमण से शीघ्र ठीक हो गए। हालांकि एक बात तो तय है कि कोरोना वैक्सीन संक्रमण की दर कम करने और संक्रमण रोकने में बहुत सहायक है। इसलिए जरूरी है कि आप न सिर्फ वैक्सीन लें, बल्कि सही समय पर इसकी दूसरी डोज भी लगवाएं, क्योंकि सिर्फ एक डोज से पर्याप्त प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो सकती। इससे आपकी इम्युनिटी मजबूत रहेगी और आप न सिर्फ कोरोना, बल्कि अन्य संक्रमणों से भी बचेंगे।

प्रस्तुति: हरीश तिवारी

मौसमी बीमारियां और कोरोना

डेंगू में प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना, मलेरिया में कंपकपी व ठंड लगकर तेज बुखार आना और चिकनगुनिया में तेज बुखार के साथ हाथ-पैर और शरीर के जोड़ों में दर्द होना प्रमुख लक्षण हैं। मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से होने वाली इन बीमारियों के इतर कोविड-19 वायरस सार्स-2 के कारण होता है, जो मुख्य रूप से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। शरीर में प्रवेश करने के बाद जहां डेंगू वायरस तीन से 10 दिन के भीतर लक्षण उत्पन्न करता है तो कोविड वायरस दो से 14 दिन के भीतर लक्षण उत्पन्न करता है। हालांकि दोनों बीमारियां गंभीर होने पर मौत का कारण बन सकती हैं। डेंगू के लक्षणों में लगातार उल्टी आना, नाक से रक्तस्राव होना, सांस लेने में कठिनाई, लीवर में सूजन और हेमेटोक्रिट में लगातार वृद्धि होना शामिल है, जबकि कोविड-19 में सांस लेने में कठिनाई, तेज बुखार, लगातार दर्द या छाती में दबाव, जागने या जागते रहने में असमर्थता, होंठ या चेहरा नीला दिखाई देना जैसे गंभीर लक्षण शामिल हैं।

ये सावधानियां जरूर बरतें

- डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए आसपास कहीं पानी इकट्ठा न होने दें।
- जमा हुए पानी में दवा का छिड़काव करें ताकि मच्छर के लार्वा नष्ट हो जाएं।
- मच्छरों से बचने के लिए रात में मच्छरदानी का उपयोग करें व पूरी बांह के कपड़े पहनें।
- आसपास स्वच्छता बनाए रखें साथ ही स्वच्छ जल और साफ भोजन का ही सेवन सुनिश्चित करें।
- संक्रमित व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वस्थ व्यक्ति से उचित दूरी बनाए रखे और नियमित रूप से मास्क अवश्य पहने।
- रोजाना करीब 30 मिनट तक योग, प्राणायाम अथवा व्यायाम अवश्य करें।

हेल्थ फाइल

डा. अखिलेश यादव
अस्थिरोग विशेषज्ञ, गाजियाबाद
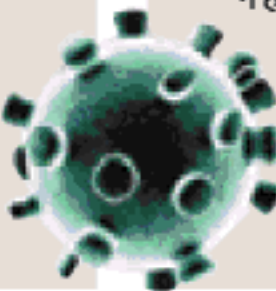
सक्रिय रहने से कम होगा जोड़ों में दर्द

जीवनशैली में परिवर्तन के कारण पिछले कुछ सालों से जोड़ों में दर्द के मामले बढ़े हैं। कोरोना काल में यह समस्या और तेजी से बढ़ी है। कोविड के कारण लोगों का संपूर्ण स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है, क्योंकि इस संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति होम क्वारंटाइन या अस्पताल में भर्ती होने के कारण लंबे समय तक निष्क्रिय हो जाता है। इसके अलावा वायरस के दुष्प्रभावों के कारण भी मांसपेशियों और जोड़ों में कमजोरी के मामले बढ़े हैं। उम्र संबंधी परेशानियां, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, र्‍यूमेटाइड अर्थराइटिस, आस्टियोपोरोसिस तथा सूजन संबंधी बीमारियों के कारण भी जोड़ों के दर्द के मामले बढ़ रहे हैं। विटामिन डी-3 और बी-12 समेत अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण जोड़ों को मजबूती देने वाली हड्डियों और कार्टिलेज पर बुरा असर पड़ता है।

पहले से किसी तरह की समस्या से ग्रस्त व्यक्तियों में भी कोविड के बाद के दौर में जोड़ों का दर्द, सूजन, मांसपेशियों और जोड़ों में अकड़न, चलने-फिरने में दिक्कत आदि की आशंका रहती है। यह समस्या मामूली से लेकर गंभीर भी हो सकती है।

बहुत से लोगों को वर्क फ्राम होम के कारण भी जोड़ों के दर्द से प्रभावित होना पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वर्क फ्राम होम के दौरान ज्यादातर कामकाजी प्रोफेशनल्स घर पर गलत तरीके से बैठकर काम करते हैं या फिर आरामदायक स्थिति में काम करते हैं। इस कारण से भी जोड़ों संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं।

इसके साथ ही जंक फूड और फ्रोजन फूड के अधिक इस्तेमाल से अर्थराइटिस और जोड़ों संबंधी अन्य समस्याएं अधिक हो रही हैं। हाई फैट वाले जंक फूड में मौजूद बैक्टीरिया शरीर में सूजन बढ़ाते हैं। इससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली प्रभावित होने लगती है। इसके साथ ही बैक्टीरिया जोड़ों की कार्टिलेज और कोशिकाओं पर भी हमला करने लगते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है।

इन समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन कुछ देर व्यायाम किया जाए, उठते-बैठते समय सावधानी बरती जाए, भोजन में पोषक तत्व अवश्य शामिल हों। कहने का आशय यह कि सही जीवनशैली रखने से बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। हालांकि सक्रिय जीवनशैली अपनाने वाले जो लोग कोविड के दौरान थोड़ा सा भी लापरवाह हुए हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है। बैठने-सोने की खराब मुद्रा, आराम करने के लिए कहीं पर लेटने और शरीर को कम सक्रिय रखने के कारण शरीर अकड़ सा जाता है। इस अकड़न और इससे जुड़ी समस्याओं से बचने तथा लंबे समय तक जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए खुद को सक्रिय रखना सबसे अच्छा उपाय है। इसके साथ हल्का-फुल्का व्यायाम भी दर्द से छुटकारा दिलाने में मददगार हो सकता है।

जोड़ों संबंधी समस्याएं होने पर लगातार दर्द बना रहता है। दर्द के कारण शारीरिक क्षमता कम होने लगती है और दूसरी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

मानसून फाइल

त्वचा की समस्याओं में राहत देंगे यह तेल

बारिश के मौसम में कई लोगों में फोड़े-फुंसी, स्किन रैशेज और तमाम तरह की त्वचा संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। ऐसे मौसम में कई लोग स्किन एलर्जी से भी ग्रस्त रहते हैं। दरअसल मानसून में स्किन एलर्जी एक आम समस्या है, जिसे कुछ खास किस्म के सुगंधित कुदरती तेलों के जरिए आसानी से ठीक किया जा सकता है...

टी ट्री आयल: यह स्किन एलर्जी से निपटने का एक आसान घरेलू नुस्खा है। इस तेल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं। त्वचा संबंधी समस्याएं होने पर आप इसे सीधे अपनी त्वचा पर लगा सकते हैं। यह त्वचा के चकत्ते, संक्रमण और त्वचा संबंधी अन्य विकारों को दूर करने में मददगार होता है। टी ट्री आयल त्वचा की खुजली और सूजन को भी दूर करता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप इसे किसी अन्य एसेंशियल आयल के साथ मिलाएं और प्रभावित हिस्से पर लगाएं।

अरंडी का तेल: इस तेल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह स्किन एलर्जी को कम करने में मददगार तो है ही, साथ में खुजली और सूजन आदि से भी राहत दिलाने में मदद करता है। इसके लिए आप अरंडी का तेल यानी कैस्टर आयल रूई या फिर किसी कपड़े में लेकर शरीर के प्रभावित हिस्से पर लगाएं।

पुदीने का तेल: पुदीने का तेल यानी पिपरमेंट आयल त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया आदि से राहत दिलाने के साथ ही स्किन रैशेज और एलर्जी से भी राहत दिलाने में मददगार हैं। इस्तेमाल के लिए एसेंशियल आयल के साथ मिलाएं और त्वचा पर लगाएं।

तुलसी का तेल: तुलसी के तेल में एलर्जी, स्किन रैशेज और त्वचा संबंधी अन्य समस्याएं दूर करने के लिए एंटी इंफ्लेमेट्री प्रापर्टीज पाई जाती हैं। यह दाने और खुजली आदि पर जल्दी प्रतिक्रिया करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी त्वचा के लोच को बढ़ाने में मददगार होता है।

नीलगिरी का तेल: नीलगिरी का तेल त्वचा संबंधी समस्याओं को ठीक करने में अहम भूमिका निभाता है। नीलगिरी यानी यूकेलिप्टस आयल में पाई जाने वाली एंटी इंफ्लेमेटरी प्रापर्टीज आपकी त्वचा को एक ठंडा एहसास दिलाती हैं। इसमें पेन रिलीविंग प्रापर्टीज भी पाई जाती हैं, जो एलर्जी में होने वाले दर्द और स्किन रैशेज आदि को कम करने में सहायक होती हैं।

दैनिक जागरण
राष्ट्रीय संस्करण
बुधवार 4 अगस्त, 2021
आजकल
14
www.jagran.com

भारत में पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का परिचालन

1956 में आज ही मुंबई के ट्रांबे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का परिचालन शुरू हुआ था। इसके संचालन के लिए ब्रिटेन से ईंधन की सप्लाई होती थी। इसकी क्षमता एक मेगावाट बिजली उत्पादन की थी। 2009 में इसे बंद कर दिया गया।

विश्व के सबसे बड़े चिनाई बांध नागार्जुन सागर का उद्घाटन

1967 में आज ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नागार्जुन सागर बांध में पानी छोड़कर उद्घाटन किया था। यह तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बना है। 1966 में इसका निर्माण पूरा हुआ था। यह पत्थरों की चिनाई कर बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा बांध माना जाता है।

अभिनय से शुरुआत कर गायकी में छा गए किशोर कुमार

सुरीली आवाज से लोगों के दिल पर राज करने वाले किशोर कुमार का जन्म आज ही 1929 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। बड़े भाई और अभिनेता अशोक कुमार उन्हें फिल्मों में लाए थे। 1946 में फिल्म शिकारी से अभिनेता के रूप में किशोर ने शुरुआत की। 1948 में फिल्म जिद्दी में पहला गाना गाया। बतौर गायक आठ फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। 1961 में फिल्म झुमरू में निर्देशक, निर्माता, गीतकार, संगीतकार और अभिनेता के रूप में काम किया। उन्होंने करीब 1500 गाने गाए थे। 1987 में मुंबई में उनका निधन हो गया।

हमारे कदमों पर टिका है धरती का भविष्य

हमने कई साइंस फिक्शन वाली फिल्में देखी हैं, जिनमें आज से कुछ दशक या कुछ सदी बाद की कल्पना की जाती है। ऐसी फिल्मों को देखकर मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि कुछ सौ साल बाद दुनिया कैसी होगी। निश्चित तौर पर इसका ठीक-ठीक जवाब दे पाना किसी के लिए संभव नहीं है। दरअसल, धरती की चाल और मनुष्य व अन्य प्रजातियों की गतिविधियां हमारे ग्रह के भविष्य को निर्धारित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। अमेरिका की बिंघमटन यूनिवर्सिटी के माइकल ए लिटिल और विलियम डी मैकडोनाल्ड ने 500 साल बाद धरती के हालात से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दिए हैं।

पृथ्वी की चाल पर लगी है नजर

पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है, साथ ही एक कक्षा में चलते हुए लगातार सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। असल में भूविज्ञान के हिसाब से देखें तो 500 साल बहुत कम समय है। हजारों साल में धरती के झुकाव और उसकी कक्षा में थोड़ा बदलाव होता है। यह बदलाव सूर्य से इसकी दूरी को प्रभावित करता है, जिससे यहां जीवन खत्म हो सकता है। फिलहाल कई हजार साल तक विज्ञानियों को ऐसे किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है।
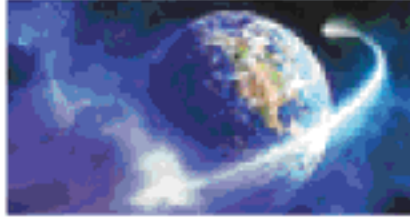
ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बन रहे लोग

इंसानी गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का कारण भी बन रही हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने से बड़े पैमाने पर ग्रीनहाउस गैसें पर्यावरण में मुक्त हो रही हैं। आमतौर पर ग्रीन हाउस गैसों का काम होता है सूर्य से आने वाली गर्मी को धरती के वातावरण में बांधकर रखना। धरती पर जीवन संभव होने में इनकी बड़ी भूमिका है, लेकिन पर्यावरण में इनकी मौजूदगी बढ़ना घातक है। ग्रीनहाउस गैसों की अधिकता से तापमान बढ़ता है। इससे ग्लेशियर पिघलने और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा रहता है। फिलहाल धरती इसका सामना कर रही है। अगर स्थिति ऐसी बनी रही, तो 500 साल बाद की पृथ्वी कल्पना से बहुत अलग होगी। फिलहाल यह मनुष्य की समझ पर निर्भर करेगा।

इंसान ने बदल दी है दुनिया

मनुष्य की गतिविधियां कई तरह से धरती को बदल रही हैं। लोगों ने शहर बसाने और खेती करने के लिए बड़े-बड़े जंगल काट दिए हैं। कई जंगली जीवों के रहने के ठिकाने खत्म हो गए हैं, जिससे पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुआ है।

पिछले 500 साल के इतिहास में देखने को मिले हैं कई नाटकीय बदलाव

पिछले 500 साल में धरती पर जीवन के मामले में नाटकीय बदलाव आया है। मनुष्य की आबादी 50 करोड़ से 750 करोड़ हो गई है। इंसानी गतिविधियों के कारण 800 से ज्यादा पेड़ों व जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। आबादी बढ़ने से अन्य जीवों के रहने की जगह कम हुई है। समुद्र का स्तर बढ़ने से स्थल क्षेत्र घटा है और बढ़ता तापमान कई प्रजातियों को अच्छे जलवायु वाले इलाकों की ओर जाने को मजबूर कर रहा है। फिलहाल मनुष्य अपनी गतिविधियों को नियंत्रित कर कुछ बदलावों की गति धीमी कर सकता है। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग बंद कर अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग ऐसा ही कदम है।

तकनीक का अकल्पनीय विकास

500 साल पहले अमेरिका जाने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि पृथ्वी पर अनगिनत कारों से भरे हाईवे होंगे और हर ओर मोबाइल की गूंज होगी। इस बात में कोई संदेह नहीं कि अगले 500 साल में तकनीक के मामले में और भी चमत्कारिक उपलब्धियां हासिल होंगी। हालांकि, देखना यही है कि तकनीक का इस्तेमाल जलवायु की रक्षा में कितना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विकास घाटे का सौदा बन जाएगा।

इनपुट : प्रेट्र जागरण इन्फो

इधर-उधर की

बिजली से दो हिस्सों में बंटा वर्षों पुराना देवदार का पेड़

तेजी से वायरल हो रहा है घटना का वीडियो। इंटरनेट मीडिया

कैलिफोर्निया, एजेंसी : प्रकृति की ताकत के आगे सभी हार मान लेते हैं। उसके आगे किसी की नहीं चलती। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 200 साल पुराने पेड़ पर बिजली गिरने के बाद का वीडियो इसी बात की तस्दीक करता है। पिछले हफ्ते वहां बिग बियर एयरपोर्ट के पास वर्षों पुराना देवदार का पेड़ आसमानी बिजली का शिकार हो गया। बिजली का असर इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही पल में वह दो हिस्सों में फटता चला गया। वहां मौजूद शख्स ने घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाला, जो तेजी से वायरल हो रहा है।

अच्छी आदतें कम करे कैंसर का खतरा

शोध ▸ पीआरएस के आधार पर विज्ञानियों ने किया आनुवंशिक जोखिम का आकलन

जीवनशैली को तीन श्रेणियों में बांटकर किया अध्ययन

वाशिंगटन, एएनआइ : कैंसर के प्रसार को देखते हुए इसके जोखिम वाले कारकों को लेकर लगातार शोध हो रहे हैं। ताकि इसकी रोकथाम और इलाज के प्रभावी तरीके अपनाए जा सकें। इसी क्रम में अमेरिकन एसोसिएशन फार कैंसर रिसर्च के शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि लोगों की जीवनशैली या आदतें किस प्रकार से कैंसर के आनुवंशिक जोखिम को प्रभावित करती हैं। बता दें कि कैंसर के कारकों में आनुवंशिकता भी एक अहम घटक है।

इस संबंध में नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुआंगफू जिन की अगुआई में किया गया शोध कैंसर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं की दिलचस्पी डीएनए के उस क्षेत्र की खोज करने में रही है, जो विशिष्ट बदलाव के जरिये कैंसर के जोखिम को प्रभावित करता है। इसे पालीजेनिक रिस्क स्कोर (पीआरएस) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो रोगियों में व्यक्तिगत स्तर पर उन विशिष्ट बदलावों के आधार पर कैंसर का जोखिम पैदा करते हैं। जिन ने बताया- हमने एक संकेतक- कैंसर पालीजेनिक रिस्क स्कोर (सीपीआरएस) बनाने की कोशिश की है ताकि कैंसर के आनुवंशिक जोखिम को समग्र रूप में आकलित किया जा सके।
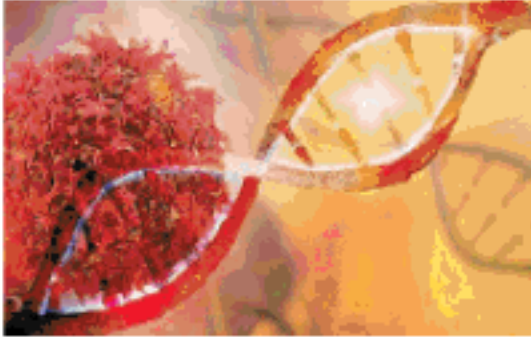
डीएनए पर होता है आदतों का असर। फाइल फोटो

कैसे किया अध्ययन : कैंसर ग्रस्त 16 पुरुष और 18 महिलाओं का जीनोम-वाइड एसोसिएशन के पास मौजूद डाटा के आधार पर पीआरएस का आकलन किया गया। इसके बाद उन स्कोर को सांख्यिकीय पद्धति के जरिये कैंसर के एकल जोखिम का आकलन किया, जो सामान्य आबादी में कैंसर के विभिन्न प्रकार में सापेक्ष अनुपात के आधार पर थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सीपीआरएस तैयार किए गए। सीआरपीएस की पुष्टि के लिए शोधकर्ताओं ने यूके बायोबैंक के 202,842 पुरुषों और 239,659 महिलाओं के जीनोटाइप सूचनाओं का इस्तेमाल किया। यूके बायोबैंक के इन सहभागियों का सर्वे जीवनशैली के विभिन्न कारकों के आधार पर किया गया था। इनमें धूमपान, शराब पीने, बाडी मास इंडेक्स (बीएमआइ), व्यायाम की आदतें तथा खानपान भी शामिल थीं। इन कारकों के आधार पर शोधकर्ताओं ने रोगियों को प्रतिकूल (शून्य से एक स्वास्थ्य कारक), मध्यवर्ती (2 से 3 स्वास्थ्य कारक) तथा अनुकूल (4 से 5 स्वास्थ्य कारक) के आधार पर वर्गीकृत किया गया।

परिणाम : जिन रोगियों में हाल-फिलहाल (2015-2016) में रोग का पता चला, उनमें अधिकतम सीआरपीएस पुरुषों में दोगुना और महिलाओं में 1.6 गुना ज्यादा पाया गया। अध्ययन में शामिल 97 फीसद रोगियों में कम से कम एक प्रकार के कैंसर का उच्च आनुवंशिक जोखिम था। इससे पता चला कि लगभग हर व्यक्ति कम से कम एक प्रकार के कैंसर के प्रति संवेदनशील है। साथ ही स्वस्थ जीवनशैली की अहमियत का भी संकेत मिला।

प्रतिकूल जीवनशैली वाले रोगियों में उच्च आनुवंशिक जोखिम अनुकूल जीवनशैली वाले लोगों की तुलना में पुरुषों में 2.99 गुना तथा महिलाओं में 2.38 गुना ज्यादा था। जो रोगी पांच साल से कैंसरग्रस्त थे, उनमें 7.23 फीसद पुरुष और 5.77 फीसद महिलाएं थीं, जिनकी जीवनशैली प्रतिकूल श्रेणी की रही। जबकि स्वस्थ जीवनशैली वाले लोगों में 5.51 फीसद पुरुष और 3.69 फीसद महिलाएं ही रोगग्रस्त पाई गईं।

दिल को रखना चाहते है चंगा तो खाने में कम करें कैलोरी

अनुसंधान

आहार पर दें ध्यान। फाइल फोटो

अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार और एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। एक नए अध्ययन में भी कुछ इसी तरह की बात निकल कर सामने आई है। इस अध्ययन के अनुसार, रोजाना के खानपान में महज 200 कैलोरी की कमी करने और हल्के व्यायाम से दिल की सेहत को चंगा रखा जा सकता है। इस तरह की जीवनशैली से बुजुर्गों और मोटापे से पीड़ित लोगों को खासतौर पर फायदा हो सकता है। सर्कुलेशन पत्रिका में अध्ययन के नतीजों को प्रकाशित किया गया है।

अध्ययन के मुताबिक, दैनिक कैलोरी में कमी लाने के साथ एरोबिक एक्सरसाइज करने का नतीजा मोटापे से पीड़ित वयस्कों में दिल की सेहत में उल्लेखनीय सुधार के तौर पर पाया गया है। इससे बढ़ती उम्र के साथ धमनी के सख्त होने के खतरे को टालने में मदद मिल सकती है। धमनी के सख्त होने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। यह निष्कर्ष मोटापे से पीड़ित 160 बुजुर्गों पर किए गए एक अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इन प्रतिभागियों की औसत उम्र 69 वर्ष थी। अध्ययन की प्रमुख शोधकर्ता और अमेरिका के वेक फारेस्ट स्कूल आफ मेडिसिन की एसोसिएट प्रोफेसर टीना ई ब्रिंकले ने कहा, 'यह पहला अध्ययन है, जिसमें कैलोरी में कमी लाने के साथ एरोबिक एक्सरसाइज का धमनी पर पड़ने वाले प्रभाव पर गौर किया गया। जीवनशैली में बदलाव से हृदय की सेहत सुधारने में मदद मिल सकती है।' -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

... तो इनसिक्योर महसूस करता हूं : अमर उपाध्याय

भूल भुलैया 2 के सेट पर 10 अगस्त से लौटेंगे अमर। इंस्टाग्राम

क्योंकि सास भी कभी बहू थी और देख भाई देख जैसे शोज कर चुके अभिनेता अमर उपाध्याय अपने 27 वर्षों के करियर में बस काम करते रहने में यकीन रखते आए हैं। एक लाइव चैट के दौरान अमर ने बताया कि मैं नान फिल्मी बैकग्राउंड से हूं। क्राफ्ट क्या होता है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है कुछ पता नहीं था। सब खुद से सीखना पड़ा। गलतियां की हैं, उनसे सीखा है और आगे बढ़ा हूं। काम की इतनी आदत हो गई है कि बिना काम के मैं बोर हो जाता हूं, इनसिक्योर महसूस करता हूं। लाकडाउन के दौरान मैंने खुद को व्यस्त रखने के नए तरीके निकाल लिए थे, कुकिंग सीखी, बर्तन साफ करता था। दरअसल, लगातार काम करने की प्रेरणा मुझे अपने पहले शो देख भाई देख से ही मिली थी। तब मैं सिर्फ 17 साल का था। कुछ वक्त बाद ऐसा समय आया, जहां करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि अगर फिल्म स्टार के जैसी प्रसिद्धी नहीं मिली, तो काम करना छोड़ दूंगा। फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी शो मेरे पास आया। वहां से मुझे सुपरस्टार का लेबल मिल गया। कभी लगा ही नहीं कि काम नहीं करना है। आने वाले 30-40 साल तक काम करना चाहता हूं। अमर की आगामी फिल्म भूल भुलैया 2 होगी। खबरों के मुताबिक अमर इस फिल्म की शूटिंग 10 अगस्त से शुरू कर सकते हैं।

गुलशन ग्रोवर ने महेंद्र सिंह धौनी से कहा- डान के रोल मत करना

फिल्म इंडस्ट्री में सितारे अक्सर अपने समकालीन कलाकार से प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर बात की जाए बालीवुड के बैडमैन गुलशन ग्रोवर की तो उन्हें इस पेशे में खतरा महसूस होने लगा है महेंद्र सिंह धौनी से। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान धौनी के नए हेयर स्टाइल ने गुलशन को परेशान कर रखा है। उन्होंने ट्विटर पर धौनी के नए हेयर स्टाइल वाली तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'माही भाई बहुत अच्छा लुक है। कृपया कोई डान का किरदार स्वीकार मत करना, वह मेरे धंधे पर लात मारने जैसा होगा। पहले ही मेरे तीन खास भाई संजय दत्त, सुनील शेट्टी और जैकी श्राफ ऐसा कर रहे हैं, ताकि मैं इस बिजनेस (फिल्म इंडस्ट्री) से बाहर निकल जाऊं। आलिम हाकिम तुम्हारे लिए बैडमैन आ रहा है।' दरअसल, दो दिन पहले सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने एमएस धौनी को नया हेयर स्टाइल दिया था, जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की थी। उन तस्वीरों को गुलशन ने अपने ट्विटर पेज पर भी शेयर करते हुए ये बातें लिखी हैं। गुलशन के इस पोस्ट को पढ़ने के बाद जहां आलिम ने हंसते हुए लिखा, 'थैंक यू सर, खुश हूं कि आपको यह पसंद आया।' वहीं गुलशन ग्रोवर के फैंस ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। एक यूजर ने लिखा, 'सर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। इस दौर में कई डान होंगे, लेकिन बैडमैन एक ही है।' एक अन्य यूजर ने लिखा कि बैडमैन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। गुलशन आखिरी बार फिल्म मुंबई सागा में नजर आए हैं।

बैडमैन के नाम से मशहूर हैं गुलशन। इंस्टाग्राम

अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म रक्षा बंधन के मुंबई शेड्यूल की शूटिंग हुई पूरी

फिल्मकार अक्सर अपनी फिल्म के लिए एक शहर में रहकर किसी दूसरे शहर ही नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया का सेट स्थापित कर देते हैं। मंगलवार को अक्षय कुमार अभिनीत फिल्म रक्षा बंधन के मुंबई शेड्यूल की शूटिंग पूरी हो गई। इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म के सेट से अभिनेत्री भूमि पेडणेकर और निर्देशक आनंद एल राय के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'मैं पहले से ही चांदनी चौक की इन गलियों में घूमना मिस कर रहा हूं। यद्यपि यह एक स्थापित सेट था। सुमित बासु आपने इसे वास्तविक दिखने जैसा बनाया, आपको सलाम। मेरी शानदार सहकलाकार भूमि पेडणेकर अपनी कमाल की प्रतिभा से फिल्म में सही संतुलन देने के लिए धन्यवाद। आनंद एल राय सर.. आप जादूगर हैं, इसके अलावा मैं आपके बारे में कह ही क्या सकता हूं। आज हमने रक्षा बंधन के मुंबई शेड्यूल की शूटिंग खत्म कर ली है, अब मैं सेट किसी दूसरे बेहतर कलाकार के लिए छोड़ रहा हूं।' अक्षय ने मंगलवार को अपनी फिल्म बेल बाटम का ट्रेलर भी रिलीज किया।

मुंबई के सेट पर अक्षय को आई चांदनी चौक की याद। इंस्टाग्राम

अपने गानों के जरिये लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली नेहा भसीन अब कैमरे के सामने बिग बास के घर में अपना टैलेंट दिखाती नजर आएंगी।

मुझे लोग अब शक्ल से भी पहचानेंगे : नेहा

जग घुमेया... चाशनी... जैसे गाने गा चुकीं गायिका नेहा भसीन बिग बास ओटीटी शो में बतौर प्रतियोगी शामिल होंगी। यह शो टीवी से पहले छह हफ्तों तक डिजिटल प्लेटफार्म वूट पर चलेगा। बिग बास के घर में प्रवेश करने से पहले नेहा क्वारंटाइन में रह रही हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने शो में जाने की वजह बताते हुए कहा कि 20 साल के अपने करियर में मैंने बहुत मेहनत से नाम बनाया है। देश में बहुत लोग होंगे, जिन्होंने मेरा संगीत सुना होगा, लेकिन शायद शक्ल से नहीं पहचानते होंगे, वह इस शो के जरिये मुझे पहचान जाएंगे। मुश्किल शो है, यकीनन रिस्क है। मैं सेलिब्रिटी हूं, लेकिन अगर लोगों को संगीत से ऊपर बिग बास शो लगता है, तो वहां जाकर खुद का नाम और आगे बढ़ाने की कोशिश करने में दिक्कत नहीं है। मुझे पता है वहां झगड़े बहुत होते हैं। बेकार की बातें सुनने की आदत मेरी भी नहीं रही है, लोग मेरे बारे में यह बात जानते हैं, लेकिन मेरा दूसरा साइड भी है। जैसे- मैं बहुत जोर से खुलकर हंसती हूं, स्कूल में मुझे शूर्पणखा के नाम से लोग बुलाते थे। बहुत ही भावुक इंसान भी हूं। मेरी कोशिश बस यही होगी कि मेरी मां अपसेट न हों। दिल्ली की लड़की हूं, मुझे सब तरीके आते हैं। हर मुश्किल परिस्थिति को हैंडल करने का एक तरीका होता है। मां की दी परवरिश का ख्याल रखूंगी। शो में जाने के निर्णय से मेरे पति सरप्राइज थे। हालांकि वह बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा जैसी हो वैसी ही रहना। वहां जाकर खाना बनाना सीख जाऊंगी। मुझमें लीडर और कैप्टन वाली क्वालिटी ज्यादा रही है, लेकिन घर के काम करने पड़े तो वह भी करूंगी। बिग बास ओटीटी शो को छह हफ्तों तक फिल्ममेकर करण जौहर होस्ट करेंगे, उसके बाद इसे बिग बास 15 के तौर पर कलर्स चैनल पर लांच किया जाएगा।

बिग बास ओटीटी शो में बतौर प्रतियोगी जाएंगी नेहा • इंस्टाग्राम

चाचा अभय के साथ वैली में नजर आएंगे करण

चाचा संग काम करने को लेकर उत्सुक हैं करण देओल • इंस्टाग्राम

अभिनेता सनी देओल के बेटे करण देओल ने फिल्म पल पल दिल के पास से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। फिल्म का निर्देशन उनके पापा ने ही किया था। अब खबर है कि उन्हें फिल्म वैली में अपने चाचा अभय देओल के साथ काम करने का मौका मिल गया है। इस फिल्म के निर्माता अजय देवगन होंगे, जबकि इसका निर्देशन देवेन मुंजल करेंगे। करण का मानना है अभय के साथ काम करना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा है, जिसे वह जीवनभर संजोकर रखेंगे। अभय को डिंपी चाचा बुलाने वाले करण उनके साथ काम करने को लेकर काफी उत्सुक हैं। करण ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में अभय के साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'हमेशा मेरा साथ देने के लिए मैं डिंपी चाचा (अभय देओल) को धन्यवाद देना चाहता हूं! वह हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं और उनके साथ काम करना मेरे लिए यादगार रहेगा।' यह फिल्म तमिल कामेडी फिल्म की रीमेक बताई जा रही है। अभय बीते दिनों रिलीज हुई वेब सीरीज 1962: द वार इन द हिल्स में सैन्य अधिकारी की भूमिका में नजर आए थे।

अपने किरदार को वास्तविकता के करीब रखा

मौजूदा दौर में देश के इतिहास में हुई वास्तविक घटनाएं और उनके नायकों की कहानियां फिल्मकारों को खूब आकर्षित कर रही हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा अभिनीत फिल्म मिशन मजनू पिछली सदी के सातवें दशक में भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान में अंजाम दिए गए एक महत्वपूर्ण मिशन पर आधारित है। इस फिल्म में सिद्धार्थ के साथ-साथ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, धड़कन और रुस्तम जैसी फिल्मों के अभिनेता परमीत सेठी भारतीय खुफिया विभाग के एजेंट के किरदार में नजर आएंगे। परमीत का किरदार एक वास्तविक एजेंट के किरदार से प्रेरित होगा। दैनिक जागरण से बातचीत में परमीत ने बताया, 'मैंने फिल्म के ज्यादातर हिस्से शूट कर लिए हैं, सिर्फ एक दिन का काम बाकी है। मैं इस फिल्म में पहली बार खुफिया विभाग के एजेंट का किरदार निभा रहा हूं। यह एक रियल (वास्तविक) लाइफ किरदार है। मैं जिनका किरदार निभा रहा हूं, वह अपनी वास्तविक जिंदगी में जिस तरह बातें करते थे, चलते थे और जैसी उनकी जीवनशैली थी, हमने फिल्म में उन्हें बिल्कुल उसी तरह से पेश करने की कोशिश की है। हमने इस किरदार के लुक पर काफी काम किया। दर्शकों को अच्छी कहानी देखने को मिलेगी। किसी की जिंदगी से जुड़े किरदार से प्रमाणिकता मिलती है और दर्शकों को भी मजा आता है।' फिल्म में सिद्धार्थ के साथ दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिंदी सिनेमा में पदार्पण कर रही हैं।

पहली बार खुफिया विभाग के एजेंट का किरदार निभा रहे हैं परमीत • इंटरनेट मीडिया

आध्यात्मिक विश्वास की वजह से स्वीकार किया धारावाहिक : श्रेणु पारिख

कलाकारों द्वारा किसी प्रोजेक्ट को स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के कई कारण होते हैं। कई बार प्रोजेक्ट स्वीकार करने के पीछे कलाकारों के भावनात्मक लगाव भी होते हैं। कुछ ऐसा ही देखा गया इश्कबाज और इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर धारावाहिकों की अभिनेत्री श्रेणु पारिख के मामले में, जो 10 अगस्त से एंड टीवी पर शुरू होने जा रहे धारावाहिक घर एक मंदिर : कृपा अग्रसेन महाराज की- में गेंदा के किरदार में नजर आएंगी। मंगलवार को आयोजित इस धारावाहिक की वर्चुअल कांफ्रेंस के दौरान श्रेणु ने कहा, 'इस शो में मेरा किरदार एक साधारण लड़की गेंदा का है, जो अग्रसेन महाराज जी में बहुत आस्था रखती है। मेरे किरदार से मेरा व्यक्तित्व काफी मिलता-जुलता है, क्योंकि मैं भी हनुमान जी में बहुत आस्था रखती हूं। उस आस्था की झलक मुझे गेंदा के किरदार में भी दिखी थी। इससे पहले मैंने ग्रे शेड वाले किरदार निभाए थे, इस बार मैं कुछ साधारण किरदार निभाना चाहती थी। जब मुझे इस शो का प्रस्ताव मिला तो मैं महाराज अग्रसेन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने उनके बारे में काफी रिसर्च की और अग्रवाल समुदाय से आने वाले अपने कई दोस्तों से भी उनके बारे में पता किया। मैं अब भी सेट पर हर दिन स्क्रिप्ट पढ़ते हुए महाराजा अग्रसेन के बारे में नई-नई चीजें जानने की कोशिश करती हूं।' बता दें कि द्वापर युग के अंतिम चरण में पैदा हुए अग्रसेन महाराज से ही अग्रवाल समाज की उत्पत्ति बताई जाती है। इस पारिवारिक धारावाहिक में श्रेणु के साथ अक्षय म्हात्रे और समीर धर्माधिकारी भी अहम भूमिकाओं में हैं।

धारावाहिक घर एक मंदिर : कृपा अग्रसेन महाराज की- में नजर आएंगी श्रेणु। टीम एंड टीवी

अलाया एफ हो सकती हैं कार्तिक आर्यन की हीरोइन

कभी किसी फिल्म से निकाले जाने को लेकर, तो कभी किसी नई फिल्म की घोषणा को लेकर अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। कार्तिक ने हाल ही में एकता कपूर के प्रोडक्शन में बन रही फिल्म फ्रेडी की शूटिंग शुरू की है। अब खबरें हैं कि इस फिल्म में कार्तिक के अपोजिट अलाया एफ होंगी। अलाया ने पिछले साल सैफ अली खान अभिनीत फिल्म जवानी जानेमन से हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया था। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इस फिल्म की अभिनेत्री के लिए एकता कपूर और निर्देशक शशांक घोष ने कई नामों पर चर्चा की, लेकिन सभी अभिनेत्रियों के बीच अलाया ही निर्माता-निर्देशक की पसंद बनकर सामने आईं। इस फिल्म में अलाया इमोशनल किरदार में होंगी। इसके अलावा वह कन्नड़ फिल्म यू टर्न की हिंदी रीमेक में भी काम कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन के अंतर्गत और समीर विद्वांस के निर्देशन में बन रही कार्तिक की अनाम फिल्म की अभिनेत्री की जानकारी भी सामने आई है। पहले इस फिल्म का शीर्षक सत्यनारायण की कथा था। विवादों में आने के बाद निर्माताओं ने शीर्षक बदलने की घोषणा की थी। इस फिल्म में कार्तिक के साथ कियारा आडवाणी के होने की खबरें हैं।

डार्क रोमांटिक थ्रिलर फ्रेडी में कार्तिक के साथ काम कर सकती हैं अलाया एफ • इंस्टाग्राम